हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1983

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 23 मार्च, 1983

	पृश्ठ संख्या
भाहीद ए आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियो को श्रद्धांजलि	(13)1

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(13)22
ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न– चौधरी हरद्वारी लाल वाईस चांसलर, महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक संबंधी	(13)32
विभिन्न विशयों का उठाया जाना– गांव बोहड़ा कला मे व्याप्त डर तथा भय संबंधी	(13)33
प्वायंट आफ आर्डर– विधान भवन मे मैंबर्ज को पम्फलैट/पब्लिके ान डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी	(13)34
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– इलैक्ट्रौनिक वोटिंग म ाीन संबंधी	(13)35
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(13)36
बिल्ज– (i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1983	(13)39

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1983	(13)39
(iii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) बिल, 1983	(13)70
बैठक का समय बढ़ाना	(13)75
दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)	(13)76
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– श्री हरि चंद हृड्डा द्वारा	(13)76
दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)	(13)77
(iv) दि हरियाणा आयुर्वेदिक एड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1983	(13)79
बैठक का समय बढ़ाना	(13)83
दि हरियाणा आयुर्वेदिक एड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1983	(13)83

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

भाहीद–ए–आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों को श्रद्धांजति।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर सहाब, आज 23 मार्च का दिन है। यह दिन हमारे इतिहास मे भाहीदी दिवस है। आज के दिन सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। सरदार भगत सिंह जी ने दे ा की आजादी के लिये ही अपना बलिदान दिया था। हम सभी को उन्ही के दिखलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम भी अपने दे ा के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सके। स्पीकर सहाब, जो प्रस्ताव मैं हाउस के सामने लाया हूं, उसके प्रति हम सब का कर्त्तव्य बनता है कि हम ऐसे भाहीदों को सच्ची श्रद्धांजति भेंट करे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मै इसलिये खड़ा हुआ हूं कि आज 23 मार्च का दिन है। आज इन भाहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिये लाखों लोग उनकी समाधि पर इकट्ठे हो रहे है। आज के दिन पंजाब सरकार ने अपना विधान सभाा का सत्र भी बंद कर दिया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव ये 1980–81 मे लाये थें लेकिन आज के ऐजेंडें पर ये इस प्रस्ताव को ला नही सके। अब मेरे जैसे किसी सदस्य ने इनको सुझाव दे दिया होगा।

चौधरी भजन लाल: आपने कोई सला नही दी। हमें भी तो कुछ पता है।

श्री मंगल सैंन: लीडर आफ दि हाउस से यह बड़ी भाी गलती हो गई है। मैं आपके जरिए इनसे कहना चाहूंगा कि आज का दिन छूट्टी का दिन होना चाहिए। यह मौके कभी कभी ही आते है जब इन महापुरूशों को याद किया जाता है। ऐसे भाहीदों के बलिदान के कारण ही हमारा दे ा स्वाधीन हुआ है। आज हमें आजाद हुए 35 वर्श हो चुके है। यह आजादी हमे इन्ही की बदौलत मिली है। इसलिये हम सभी का कर्त्तव्य बनता है कि हम उन्हे सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करें। जो प्रस्ताव ये हाउस मे अब लाये है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती चंद्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, आज 23 मार्च का दिन है। यह दिन भाहीद आजम भगत सिंह जी को याद करने

का हैं। मैं अपनी तरफ से और इस दे ा के नौजवानो के लिये एक उदाहरण है। नौजवानों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर आज की मौजूदा सरकारनही चल रही हैं ऐसे ऐसे मौको पर हम इन वीरों को याद तो करलेते है लेकिन सच्चे दिन से याद नही कर पाते। आज किसी को कोई भी बहाना मिला जाता है तो वह दफतर से गैर हाजिर होना चाहता है। आज का दिन वैसे छुट्टी का दिन होना चाहिए थां। मै यह समझती हूं कि हम चंद भाब्दों मे उनकी कुर्बानी और उनके दिखलाए हुए रास्ते के लिये सच्ची श्रद्धांजलि नही दे सकते। मैं इस प्रस्ताव का पुनः पुरजोर समर्थन करती हूं और अपने तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति नत मस्तकर होते हुए श्रद्धांजलि भेंट करती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौद): स्पीकर साहब, लीडर आफ दि हाउस से यह गलती रही कि आज के एजेंडे पर ऐसा महत्वपूर्ण विशय नही आ सकां अब इन्होंने इस प्रस्ताव को लाकर सुधार कर लिया है। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन मे खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सहाब, 23 मार्च यययययययययययका दिन हिस्टरी मे एक बहुत ही बड़ा दिन माना जायेगा। आज के दिन ही सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरू जी भाहीद हुए थे। पंजाब सरकार ने आज के दिन छुट्टी करके वाकई एक बहुत बड़ा काम किया है । मैं तो अब भी आपके द्वारा सी0एम0 से प्रार्थना करूंगा कि उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित करके आज के लिये सदन स्थगित कर दिया

जाये। आज के दिन हम इन भाहीदों को श्रद्धांजलि तो दे रहे है परंतु आज दे ा को आजाद हुए 33 साल हाो गये है ओर हम उस रास्ते पर नही चल पाये जो इन बीरों ने दिखलाया था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दे ा को आजाद करवाया था। जो स्वप्न उन्होंने इस दे ा की आजादी के लिये संजोये थे, हम उस प्रकार का दे ा नही बना पाए। उसमे हम सभी जिम्मेवार है ओर वि ोश तौर पर उन लोगो की जिम्मेवारी है जो लम्बे समय तक इस दे ा की हकूमत करते चले आ रहे । हम इस दे ा के चरित्र का निर्माण अभी तक नही कर पाए है। हममे आज के दिन भी बहुत कमियां है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तथी होगी जब हम आज के दिन यह संकल्प करें कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते और आद ार्ो पर आगे चलेंगे। स्पीकर साहब, अंत मे जो प्रस्ताव सी0एम0 साहब ने रखा है। मैं उसका अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इन भाहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समर्थन करता हूं।

श्री नेकी राम (रतिया, अनुसूचित जाति): स्पीकर सहाब, डा0 साहब ने कहा है कि लीडर आफ दि हाउस को इस प्रस्ताव को आज के एजेंडे पर लाना चाहिए था। इस संबंध मे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विचार इनके है, वे विचार दूसरे सभी मैंबरों के भी है इसलिये आप इस प्रस्ताव को आज की कार्यवाही पर ले आये और हाउस मे अनाउंस कर दे।

श्री हीरा नंद आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी दे ा मे जब उसके वीरों को श्रद्धांजलि जाती है तो यदि उनके दिखलाए हुए रास्ते पर वह दे ा चलेगा तो वह दे ा कभी आगे नही बढ़ सकेगा। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के भी अनेक वीरों ने इस दे ा की अजादी के लिये प्राण गंवाए है। राज नाहर सिंह, बल्लबभगढ़ और नवाब झज्जर ने भी इस दे ा के लिये अपनी जान की बाजी लगाई है।

श्री अध्यक्ष: आप सिर्फ इसी प्रस्ताव के समर्थन मे ही कहिए।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मैं उन लोगों की चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने दे ा की आजादी के लिये अपनी जान की बातजी लगाई है। जिन लोगों का जिक्र मैंने किया है, इन लोगो को 1857 मे दिल्ली के अंदर फांसी पर लटकाया गया था। इस संबंध मे मेरा सरकार से यह सुझाव है कि ऐसे वीरों की यादगार के लिये जगह जगह पर यादगारों बनायी जानी चाहिए। जेसा मैंने पहले भी कहा है कि जब तक कोई दे ा सच्चे दिल से अपने दे ा के भाहीदों को याद नही करता तब तक वह दे ा आगे भी नही बढ़ पाता। स्पीकर साहब, मैं फिर सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसे वीरों की जगह जगह पर यादगारें बनायी

जानी चाहिए। अंत मे मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और श्रद्धांजलि भेंट करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर सहाब, जो प्रस्ताव सदन के लीडर आफ दि हाउस ने अब रखा है, वह किसी कारण आज के एजेंडे मे इन्क्लूड नही हो सका था। जहां तक इन भाहीदो को याद करने की बात है, उसके संबंध मे मैं यह कहना चाहूंगा कि–

भाहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्श मेले,

वतन पर मरने वालो का यही बाकी नि ाां होगा।

स्पीकर साहब, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू ने दे ाके लिये कुर्बानियां दी। यह कुर्बानियां उन लोगो को जगाने के लिये दी जिन की आत्माओं मे अंग्रेज सरकार के जामने मे, सरकार की दह ात ओर जालिमाना कार्यवाहियों से डर पैदा हो गया था । उनके डर को दूर करने के लिये सरदार भगत सिंह और इसके साथियों ने कुर्बानी देने का रास्ता अख्तियार किया था। इन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसे इंडियन सो ालिस्ट रिपब्लिक आर्मी कहते थे। यह तहरीक अंग्रेज सरकार को ताकि के जोर से उलटानले का प्रोग्राम लेकर आई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी कौम, मेरे दे ावासी डरपोक बन चुके है तो उन्होंने कुर्बानी देने का रास्ता अपनाया। उन्हे डर था कि अगर लोगा के दिलों मे अंग्रेज हकूमत का डर इसी तरह बना

रहेगा तो वह तहरीक, जिसको लेकर वे मैदान मे आये थे, वह फेल न हो जाये। इसलिय उन्होंने सोचा कि कुर्बानी देकर ही इस डरपोक भारतवासियों के दिल सेदूर किया जा सकता है। उन्होने अपने आप को गिरफतारी के लिये पे ा किया तथा अपने साथियों के साथ दे ा के लोग भाहीद हुए । उस वक्त से लेकर आज तक यह दिन भाहीदी दिवस के रूप मे मनाया जा रहा है । सरदार भगत सिंह जी भाहीद ही नही बल्कि भाहीदेआजम है। इन्होंने सारे दे ावासियों को कुर्बानी का रास्ता दिखाया, जिसकी मिसाल कहीं नही मिलती। उसी नतीजे के तौर पर आज हम आजाद है और आज हमारी सरकार इस मे काम कर रही है। आज अपनी सरकारको लेकर हम इस सदन मे बैठे है यह सब कुछ उन्ही लोगो की देन है, उन्ही की कुर्बानियो का नतीजा है। इन भाब्दों के साथ मैं इन भाहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव सदन मे रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैंबर्ज, मै ंआप सब साहेबान के सैंटीमैंटस के साथ अपने आपको एसोि ाएट करता हूं। मेरी भी वही फीलिंग्स है जो सारे हाउस की है। मैं सब मैंबर साहेगान को रिक्वैस्ट करूंगा कि इनको होमेज पे करने के लिये दो मिनट के लिये खड़े हो जायें।

(इस समय भाहीदों के सम्मान मे सदन ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्र न एंव उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

Home for Destitutes at Ambala

***100. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Home for destitutes, old and infirm persons at Ambala Cantt.?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया): नही जी।

सेठ राम दास धमीजाः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि सारी स्टेट मे जिलावार डैस्टिच्यूटस होम्ज की कितनी कितनी तादाद है और एक डैस्टिच्यूट होम बनाने मे कुल कितना खर्च आता है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, वृद्ध और बृद्धाओं केलियेएक ही डैस्टिच्यूट मधुबन मे चल रहा है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय सदस्य श्री राम दास धमीजा जी के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। उन्होंने अपने इलाके के गरीबों के लिये डैस्टिच्यूट होम बनाने की बात कही है। बड़ी अच्छी बात होती अगर मेरी आदणीय बहिन जी

कह देती कि डैस्टिच्यूट, ओल्ड और इंफर्म पर्सज के लिये अम्बाला मे होम सैंट अप करने जा रहे है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जब मधुबन मे डैस्टिच्यूट बना था, वह किन हालात मे बना था ? इसको सैट अप करने के लिय कितने इंफर्म होने चाहिए, कितने ओल्ड होने चाहिए और कितने हता ा होने चाहिए ? आपने कौन सा क्राइटैरिया अपना रखा है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: इनका क्राइटरिया यही है कि जिस व्यक्ति का कोई लड़का न हो, कमाई का कोई साधन न हो, अनाथ हो ओर रोटी खाने से लाचार हो तथा कोई दूसरा व्यक्ति उसका पेट भरने वाला न हो, ऐसे लोगों के लिये ऐसे डैस्टिच्यूट होम का प्रबंध किया जाता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सहाब, क्या बहिन जी के उत्तर से यह समझा जाये कि जो क्राइटेरिया, जो मापदण्ड उन्होंने बताया है, उसके हिसाब से सब को डैस्टिच्यूट होम मे दाखिल किया जा सकता है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: इस मे दाखिला होने के लिये 50 साल की औरत और 65 साल का मर्द होना चाहिए। स्पीकर साहब, मधुबन के अंदर जो होम खाल गया हैं इस मे 100 सीटों काप्रावधान किया गयाहै, लेकिन इस वक्त 42 लोग रहते है और 58 सीटे खाली पड़ी है। इन मे चाहे भाहर के हो, चाहे गांव

के हो, जो निर्धारित किये गये क्राइटेरियो के मुताबिक वहां आते है, उनसब को दाखिल कर लेते है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, बहिन जी ने बताया ि?क 58 सीटें खाली पड़ी है। अगर हम वहां कुछ आदमी ले जाये, तो क्या सरकार दाखिल कर लेगी?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़ियाः बिल्कुल दाखिल कर लेंगे।

चौधरी रो ान लाल आर्यः क्या मंत्री महोदया बतायेंगे कि सारे हरियाणा मे कुल कितने निराश्रित लोग है, इस बात का पता लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई सर्वे किया है?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, इस वक्त घर मे बैठे हुए वृद्ध और वृद्धाओं की टोटल संख्या 18 हजार है जिनको सरकार पै ान देती है। डिसिट्रक्ट है और क्राइटेरियापूरा करता है, हम उसको इस किस्म की सुविधा देते है।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, अम्बाला मे ऐस व्थकत कम से कम दो सौ होंगे जिन मे कुछ भाई होंगे, कुछ बहिने ंहोंगे। अगर हम इनकी लिस्ट बना कर मंत्री महोदय को दे दे क्या सरकार अम्बाला मते डैस्टिच्यूट होम बनाने का विचार करेंगी?

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मधुबन मे 58 सीटें खाली पड़ी है, वहा दाखिल करवा सकते है। इससे पहले हमने दो जगहों पर खोल कर देखा है, पहले रिवाड़ी मे खोला, फिर सोनीपत मे खोला और अब मधुबन मे चल रहा है। 52 लाख की बिल्डिंग रिवाड़ी मे तैयार हो रही है। आप दो सौ आदमियों की बात करते है, हमने तो निर्णय ले रखा है कि अगर मधुबन की 100 सीटें पूरी हो जायेगी तो और जगहों पर भी खोलेंगे।

Recruitment of Police Constables/Officers

***135. Shri Lachman Singh Kamboj:** Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise number of Police Constables and Police Officers reqriuted in the State During the year 1982?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्श 1982 के दौरान पुलिस विभाग म`केवल सिपाहियों तथा सहायक उप निरीक्षकों के पदों मे ही भर्ती की गई थी। सहायक उप पुलिस निरीक्षक के पद पर भर्ती जिला स्तर पर नही की जाती है। इस वर्श के दौरान 29 सहायक उप पुलिस निरीक्षक इस बोर्ड की सिफारि ा पर भर्ती किये गये थे। चार दुसरे सहायक उप पुलिस निरीक्षक जो कि मृतक पुलिस कर्मचारियों के पुत्र थे, भी सरकार की सेंवा अवधि के

दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवार ने एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की निति के अंतर्गत भर्ती किये गये थे।

स्टेटमैंट

जिले/युनिट का नाम	भर्ती किए गए सिपाहियों की संख्या
अम्बाला	171
करनाल	165
कुरूक्षेत्र	136
जींद	113
हिसार	152
भिवानी	117
सिरसा	106
नारनौल	114
गुड़गांव	161
फरीदाबाद	141
सोनीपत	100

रोहतक	107
रेलवे पुलिस	29
प्रथम बटालियन, ह0स0पु0	9
द्वितीय बटालियन, ह0स0पु0	36
तृतीय बटालियन, ह0स0पु0	14
चतुर्थ बटालियन, ह0स0पु0	14
पंचम बटालियन, ह0स0पु0	22
वायरलैंस	15
जोड़	1722

श्री लछमन सिंह कम्बौजः स्पीकर सहाब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि करनाल मे 165 लड़के भत्री किये लेकिन क्यायह सच है कि इन्द्री हल्के से

200 लड़के टैक्स मे एपीयर हुए लेकिन एक भी लड़का नही लिया गया?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर हर जिले की फिगर्ज मे अंतर है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि हर जिले के बराबर की भर्ती क्यों नही की गई ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,जब भी पुलिस की भती की जाती है। तो जिले की आबादी का ख्याल रखा जाता है। आबादी को ध्यान मे रखते हुए भर्ती की गई है। किसी के साथ कोई भेद भाव नही बरता गया है। आबादी के हिसाब से भर्ती की गई है।

मास्टर ि ाव प्र ाद: क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि करेंगे कि हरियाणा मे हरिजन डी0एस0पी0 और एस0पी0 को किसी जिले मे लगाया हुआ है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त 10 क्लास–1 आफिसर पुलिस मे हरियाणा आफिसर पुलिस मे हरिजन है। हैड क्वार्टर पर डी0आई0जी0 भी लगाये हुए है। जिले मे कितने डी0एस0पी0 लगाये हुए है। भायद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एस0पी0 न हो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि कि ए0एस0आईज0 का जो सिलेक ान हुआ, उसमे एक्स–सर्विसमैन का कोटा पूरा कर लिया गया है?

चौधरी भजन लालः एक्स–सर्विसमैन चार लिये गये है।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब मे बताया है कि 1722 आदमी पुलिस मे भर्ती किये गये है। सिपाही सभी जिलों से भर्ती किये गये है। मेरे एक सवाल के जवाब मे मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कि इन 1722 सिपाहियों मे कितने हरिजन, कितने एक्स–सर्विसमैन और कितने बैकवर्ड जाति के लिये गये है?

चौधरी भजन लालः 310 हरिजन, 217 बैकवर्ड और बाकी एक्स सर्विसमैन और जनरल के लिये है। जितना जिस का हक बनता था, उसी के हिसाब से काटा पूरा करने की कोि ा ा की है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या एक्स–सर्विसमैन के डिपैन्डेन्ट का कोटा पूरा कर लिया है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, अगर कोई एक्स सर्विसमैन नौकरी मे नही लगना चाहता है तो उसके लड़के या लड़की को नौकरी मे ले लिया जाता है।

श्रीमती चंद्रावतीः मैने तो आपसे यह पूछा है कि क्या वह कोटा पूरा कर लिया है?

चौधरी भजन लालः अगर एक्स सर्विसमैन आ जाते है तो ले लिये जाते है। अगर नही आते है तो उनके लड़के और लड़कियों को लिया जाता है। उनका अलग से कोटा रखा हुआ है।

श्री भागी रामः मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि 310 हरिजन लिये गये है और 217 बैकवर्ड लिये है, क्या इनसे रिजर्वे ान पूरी हो गई है? दूसरे जो 29 ए0एस0आईज0 लिये है उनमे भी रिजर्वे ान पूरी हो गई है या नही?

चौधरी भजन लालः 1722 मे से 344 सिपाही लिये जाते तो हरिजनों का 20 परसैंट का कोटा पूरा हो जाता लेकिन हमने 310 लिये है। हो सकता है बाकी लोग आये न हों या मैडिकल के टाईम पर निकल गये हो। केवल 34 हरिजन कम रहे है। हमारी कोि ा ा होती है कि हरिजनों और बैकवर्ड का कोटा पूरा करे। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब इनका राज था यानी चौधरी देव लाल का राज था तो ये हरिजनों की रिजर्वे ान केवल 13 परसैंट पूरी कर पाये थे लेकिन हमने 16 परसैंट पूरी करली है। हमने पिछली कमी को कवर करने का प्रयत्न किया है और भविश्य मे बाकी कमी को पूरी करेंगे।

श्री फतेह चंद विजः हरिजनों की जो भर्ती की गई है, क्या इसमें कोई रिलैक्से ान भी दी गई है?

चौधरी भजन लालः सिर्फ हरिजनों को सिलैक्से ान देते है। हरिजनों की एक इंच छाती और एक इंच कम ले लेते है। दूसरे लोग अगर मैट्रिक पास हों तो हरिजनों को मिडल पास भी ले लेते है लेकिन दूसरे केसिज मे किसी को रिलैक्से ान नही देते है।

डा0 भीम सिंह दहियाः मुख्य मंत्री महोदय ने 1722 सिपाहियों की भर्ती के आंकड़े दिये है। सरकार ने कुछ सिपाहियों को डिसमिस भी किया था। उनके कभी 341 और कभी 731 के आंकड़े दिये जाते रहे है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस समय 1722 सिपाही तो डिसमिस नही किये गये थे जिनकी जगह यह भर्ती हुई है।

चौधरी भजन लालः इन्होंने सारे साल की भर्ती की फिगर्ज मांगी थी, वह हमने दे दी है।

चौधरी भागमलः क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि हरियाणा मे पुलिस हरिजन क्लास वन, कितने क्लास–टू और कितने इंसपैक्टर है?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ गया है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जो ए0एस0आई0 सिलैक्ट किये थे उनमे से कितने लगा दिये और कितने अभी गलियो मे फिर रहे है?

चौधरी भजन लालः इनमे से 5 हरिजन, ती बैकवर्ड क्लासिज, चार एक्स–सर्विसमैन और 17 जनरल कैटेगरी के लगा दिये है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सर्विस सिलैक ान बोर्ड ने जो सिलेक ान की है, इसमे से भ्रश्टाचार के आधार पर कितनी सिलैक ान की गयी है। क्या कोई ि ाकायत इस बारे मे इनके नोटिस मे आयी है?

Mr. Speaker: This is no question. Please sit down Mr. Arya.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मधुबन मे पिछले साल कुछ सिपाहियों को डिस्मिस किया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछगलत काम किया था। उनमे से कुछ ऐसे भी थे जो मौके पर डियुटी पर नही थे बल्कि पंजाब मे थे। उनके बारे मे मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इन्कवायरी कर लेंगे। मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐसे आदमी थे उनके बारे मे क्या वे इन्कवायरी करेंगे और जो उनमे बेकसूर थे, उनको दोबारा लेने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे से एक बार भले राम जी ने जिक्र किया था कि कुछ लोग वहां पर नही थे। मैंने उनसे यह कहा था कि उनको अपील करनी चाहिये। उन्होंने भाायद अपील की हुई है। इस मामले को हम एग्जामिन कर रहे है। अगर वाकई वे बैकसूर होंगे और मौंके पर नही थे, तो उनको जरूर इंसाफ देने के लिये हम कहेंगे। जहां तक हीरा नन्द आर्य जी ने 29 ए0एस0आईज0 की भर्ती के बारे मे भ्रश्टाचार की बात कही है, जो आदमी जैसा होता है, वैसा ही दूसरों को समझता है। ए0एस0आईज0 सारे जिलों से लिये गये है। करनाल से 2 आदमी, जींदसे 3, सोनीपत मे 4 रोहतक के 5, इसी तरह से हिसार, भिवानी, सिरसा, नरनौल और फरीदाबाद से भी लिये गये है।

एक आवाजः हिसार से कितने लिये है?

चौधरी भजन लालः हिसार के 6 लिये है।

श्री भले रामः सिरसा से कितने है?

चौधरी भजन लालः सिरसा से दो है।

श्रीमती चन्द्राववतीः स्पीकर साहब, मेर सबमि ान यह है कि न तो मेरे सवाल का जवाब आया है और न ही डाक्टर मंगल सैन के सवाल का जवाब आया है। मैंने यह पूछा था कि कितनी पोस्टें एडवरटाइज की गई थी, उनमे से कितनी पोस्टों के लिये सिलैक ान किया गया था और कितने आदमियों को अभी तक

लिया गया है और अभी तक कितने बेचारे गलियों मे भटकते फिर रहे है?

चौधरी भजन लालः 29 तो हमने लिये है। 4 आदमी हमने वह लिये है, जिनके पिता सर्विस मे थे और उनकी सर्विस मे थे और उनकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई। कुल सिलैक ान 42 आदमियों का हुआ था। 29 उनमे से हमने ले लिये है। 13 आदमी अभी ने रहते है। जब जगह होगी तो उनको भी हम लगा लेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1722 सिपाही भर्ती किये गये है। यह भी तथ्य सामने आ गया है कि ये उन आदमियों की जगह पर भर्ती किये गये है, जो निकाले गये थे। मैं भर्ती मे भ्रश्टाचार की बात के बारे मे कुछ नही पूछता लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । मुख्य मंत्री महोदय डेट नोटीफाई हुई थी, उससे एक हफता पहले ही भर्ती नही करली गई थी, अगर हां, इसके क्या कारण थे?

चौधरी भजन लालः यह क्या सवाल हुआ।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक अन स्टार्ड क्वै चन था, उसका जवाब मुझे यह आया है कि भर्ती के लिये नोटिफिके ान के मुताबिक 26.8.1982 की डेट फिक्सड थी लेकिन किन्ही एडमिनिस्ट्रेटिव कारणो से यह भर्ती 20.8.1982 की कर ली गयी। स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों वाली बात हमारी

समझ मे नही आती। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 तारीख की बजाय 20 तारीख को ही भर्ती क्यों करली गई ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि हमे मधुबन मे हुई बात की वजह से फौरी तौर पर भर्ती करनी पड़ी है। (व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः * * * * * * *
* * * * * * *
*

चौधरी भजन लालः * * * * * * *
* * * * * * *
*

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः * * * * *
* * * * * *
* * *

चौधरी भजन लालः * * * * * * *
* * * * * * *
*

श्री हीरा नन्द आर्यः * * * * * * *
* * * * * * *
*

चौधरी भजन लालः * * * * * * *
* * * * * * *
*

श्री भले रामः * * * * * * * *
*

श्री हीरा नन्द आर्यः * * * * * * *
*

श्री अध्यक्षः जो बाते इस सवाल से इररैलेवैनट थी, वह रिकार्ड न की जाये। इस के अलावा, मैं दोनो साइडज से अपील करूंगा कि इस हाउस की कुछ मर्यादा रखी गयी जाये, कुछ डीसैंसी रखी जाये ओर कुछ डैकोरम रखा जायें जो कुछ बातें अभी यहां पर हुई है, उनको जो लोग यहां पर बैठे हुए हाउस की कार्यवाही देख रहे है, वे भी अच्छा नही समझेंगे और गलत इम्प्रै ान लेंगे। जिस ढंग से यहां पर प्रोवोके ान हुई और उसके बाद री प्रोवोके ान हुई उसके बारे मे आप ही खुद महसूस करेंगे कि यह कोई अच्छी बात नही है। मैं मानता हूं कि हर आदमी की रंगों मे खून है। आर्य जी औरब लबीर सिंह की रगों मे भी खून है। हर आदमी घर मे रोटी खाता हैं अगर लीडर आफ दि हाउस को इतनी बुरी बात कहनेंगे तो फिर आप यही ऐक्सपैक्ट करूंगा कि हाउस के डैकोरम को कायम रेखे। दोनो साइज से, चाहे इधर से कोई बात आई है या उधर से आई हे वह मैंने रिकार्ड न करने के लिये कह दिया है और वह रिकार्ड नही की गई है।

Arrears of H.S.E.B. outstanding against Industrial Consumers

***187. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount of arrears outstanding at present against the industrial consumers in the SDtate on account of electricity charges; and

(b) the amount, out of the amount referred to in part (a) above if any, outstaning for more thatn one year?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Rs. 1202 lacs ending 12/82.

(b) Rs. 1055 lacs.

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 12 करोड़ दो लाख रूपये के बिजली के बिल्ज इंडस्ट्रियलिस्टस के खिलाफ बकायाहै और एक साल के उपर की जो रा ि ा बताकया है वह दस करोड़ पचपन लाखरूपये है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कोन से कन्सर्न है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनके अगेन्स्ट पन्द्रह लाख रूपये से उपर के अमाउंट के बिल बकाया है और नके खिलाफ क्या ऐक ान लिया गया है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिजली बोर्ड एक साल मे 120 करोड़ से 140 करोड़ रूपये के बीच कंज्यूमर्ज से इकटठे करता है। उसमे से 12 करोड़ 2 लाख इंडस्ट्रीज की तरफ से बकायाहै जिसमे से 10 करोड़ 55 लाख रूपया एक साल मे बकाया हैं इसकी तफसील इस प्रकार हैं 12 करोड, मे से साढ़े नौ करोड़ रूपया पब्लिक सैक्टर कंज्मूमर्ज की तरफ है। ये पब्लिक सैक्टर कंज्यूमर्ज है पानीपत की ने ानल फर्टिलाइजर, एम0आई0टी0सी0। स्पीकर साहब, इसी तरह की और कुछ पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज है जिनमे से कुछ गवर्नमैंट आफ इंडिया की है और कुछ स्टेट गवर्नमैंट है जिनमे से कुछ गवर्नमैंट आफ इंडिया की हे और कुछ स्टेट गवर्नमैंट है। मेजर अमाउंट इनकी तरफ है। अढ़ाई करोड रूपये प्रावेट लोगो की तरफ है। इस अढ़ाई करोड़ रूपये मे से डेढ़ करोड़ रूये का अदालतों से स्टे आर्डर मिला हुआ है। बाकी जो एक करोड़ की अमाउंट है, वह प्राईवेट इंडस्टीज की तरफ है। इनके खिलाफ हमने ऐक ान लिया है। उनके कनैक ंज जिस कनैक्ट कर दिये है और रिकवरी कीर पोजी ान एडवांस स्टेज पर है। स्पीकर साहब, मैंबर साहब ने यह भी पूछा है कि जिनकी तरफ पन्द्रह लाख रूपये से ज्यादा का अमाउंट बाकी है उनके नाम क्या हैं वह भी मैं बता देता हूं (1) मैसर्ज नौर्दन इंडिया बल्लभगढ़ इनकी तरफ 43 लाख रूपया है। इनका केस कोर्ट मे पैंडिंग है। मैसर्ज पी0सी0 महे वरी, इनके खिलाफ 16.43 लाख रूपया बाकी है। इन्होंने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मैसर्ज डबरीवाला, इनके

खिलाफ 17.38 लाख रूपया है। इन्होंने सुप्रीम कोई से स्टे आर्डर लिया हुआ है मैसर्ज बी0टी0एम0 भिवानी, इनके खिलाफ 49 लाख रूपया बाकी है। इन्होंने भी कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। सहगल पेपर मिल, धारूहेड़ा, इनके खिलाफ चालीस लाख रूपया बाकी है। इनका कनैक ान डिस कनैक्ट कर दिया है और रिक्वरी की पोजी ान एडवांस स्टेज पर है। अध्यक्ष महोदय, और कोई कम्पनी या कंज्यूमर नही है जिसकी तरफ पैसा बकाया हो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज और फैक्ट्रीज की तरफ इतना भारी अमाउंट आउटस्टेडिंग है और इन्होंने कोर्टस से स्टे आड्डर ले लिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टे को वेकेट कराने के लिये सरकारने क्या कदम उठाये है। ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे बिजली बोर्ड कार्यवाही करता है, सरकार पिक्चर मे नही आती। बिजली बोर्ड के बाकायदा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को अंगेज करके केसिज परसू करता है।

श्री सागर राम गुप्ताः मंत्री महोदय ने बताया है कि ने ानल फर्टीलाइजर फैक्टरी पानीपत जो पब्लिक सैक्टर मे है और गवर्नमैंट आफ इंडिया की है उनके खिलाफ पैसा बकाया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसके खिलाफ कितना पैसा बकाया है और उनके साथ क्या झगड़ा है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ने ानल फर्टीलाइजर फैक्टरी के खिलाफ तीन करोड़ उनसठ लाखरूपया आउटस्टैंडिंग है। आर्बीट्रे ान के पास केस है और अभी इसका फैसला नही हुआ है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि के क्या यह बात सही है कि सरकार के या ओर्ड के जो लीगल एडवाइजर्ज है वे ठीक ढंग से केस को प्लीड नही करते है। अच्छे वकील अप्वायंट नही किये जाते है और वाई डिफाल्ट केस हार जाते है जिसकी वजह से इन कम्पनियों से कोर्ट से स्टे आर्डर मिल जाता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः यह बिल्कुल गलत बात है कि कौर्ट मे ठीक ढंग से केस प्लीड होते । यह तो कोर्ट को मालूम है कि स्टे क्यों दिए जाते है। हम तो कोर्ट से पूछ नही सकते यह तो फाइल से हीपता लग सकता है और हम फाइल मंगवा नही सकते। बाई डिफाल्ट कोई ऐसा बात नही है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात उनके नोटिस मे कब आई कि बारह करोड रूपया इंडस्ट्रिलिस्टस के खिलाफ बकाया है और इसमे से दस करोड पचपन लाख रूपया एक साल से बकाया है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि यह रूपया बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ बकाया है और उद्योगपतियों ने स्टे आर्डर लिया हुआ है।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि स्टेट फाइनैंि ायल कार्पोरे ान ने भी इन उद्योगपतियों को कोई रूपया दिया है और क्या इस कार्पोरे ान का रूपया भी इन उद्योगपतियों के खिलाफ बाकी है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, स्टेट फाइनैंि ायल कार्पोरे ान के बारे मे मैं जवाब कैसे दे सकता हूं कयोंकि यह कारपोरे ान मेरे पास नही है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला है । आप इस माले पर आधे घंटे की चर्चा अलाउ कर दें। बिजली बोर्ड का साल का रेवेन्यू लगभग 1.20 करोड़ रूपये हे और उसका दस परसैंअ लोगों के पास फंसा हुआ है। यह बड़ा सीरियस मामला है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड मे करोड़ो रूपये का घपला है। इसलिये आप इस पर आधे घंटे की डिस्क ान अलाउ कर दे।

डा0 ओम प्रका ा भार्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रकम फैक्टरीज के खिलाफ बकायाहै यह कितने पीरियड के अंदर बनी और जब पहली दफा रा ि ा इन फैक्टरीज के खिलाफ बनी उस दौरान बिजली बोर्ड की तरफ से इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, 12/82 तक जो कंजूमर्ज डिफाल्टर्ज थे कैटेगरी वाइज उनका मैं

बता देता हूं। जनरल कंजूमर्ज की संख्या 14151 है उनकी तरफ 1 करोड़ 15 लाख रूपये इंवाल्व है। इडस्ट्रीयल कंज्यूमर्ज 2119 है, उनकी तरफ अमाउंट इंवाल्व है 12 करोड़ 2 लाख रूपये, एग्रीकल्चर कंजूमर्ज 5986 है उनकी तरफ इंवाल्व है 79 लाख रूपये। इस तरह से टोटल कंजूमर्ज की संख्या 22256 और उनके अगेन्स्ट अमाउंट है 13 करोड़ 96 लाख रूपये । इनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, वह भी मैं बता देता हूं। जनरल कंजूमर्ज मे से 11 हजार 98 के कनैक ानज डिसकनैक्ट कर दिये गये और बाकी से एज एरियर्ज आफ लैण्ड रैवन्यू रिकवरी की जा रही है। इसी तरह से इंडस्ट्रीयल कंज्यूमर्ज 2119 मे से 1537 के कनैक ान काट दिये गये और जो बाकी बचे, उनसे एज एरियाज आफ लैंड रैवेन्यू करक्वरी की जा रही है। एग्रीकलचर कंजूमर्ज जो थे, वे 5986 थे और उनकसम`से 1827 के नैक ान काट दिये गये है। अयह डिफरेंट कैगबक` बारे मे मैक बतादेता चाहता हूं कि उनके खिलाफ 14 करोड़ रूपये अभी आउटस्टैंडिंग है। इंडस्ट्रीज के खिलफ 12 करोड 2 लाख और उसमे से साढ़े 9 करोड़ रूपया जिन जिन के नाम है, वे मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

पब्लिक सैक्टर मे जिनकी खिलाफ अमाउंट बकायाहै, वे हे नेशनल फथ्टलाईजर पानीपत उनके खिालफ 3 करााडढ़ 59 लाख हरियाणा कनकास्ट के खिलाफ 2 करोडख 9 लाख यडालमिया सीमेंट फैक्टरीख दादरी के खिलाफ 1 करोड, 18 लाख, एम0आई0टी0सी0 1 करोड़ 30 लाख, म्यूनिसिपल कमेटीज

ओर पंचायतों के खिलाफ 20 लाख, के करीब है। अध्यक्ष महोदय इसमे लिफट इरीगे ान स्कीम का 1 करोड़ के लगभग है। इस तरह से छोटा मोटा अमाउंट ओर भी हे जैसे ओरिएंटल स्पीलज फरीदाबार वगैरह। अगर ये चाहे तो मैं उनके बारे मे भी बता देता हूं। (ाोर एंव व्यवधान)

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया हे मेरा सवाल था कि क्यायह सारा अमाउंट एक ही दिन मते इतनाबढ़ गया या बताएं कि यह इतना हयूज अमाउंट कितने अमाउंट पीरियड मे बना है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ये जो प्रावेट इंडस्ट्रीज वाले है न का एक करोड़ रूपये से जयादा अमाउंट नही हैं पब्लिक सैक्टर के खिलाफ अमाउंअ जरूर इंवालवड हैं उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर फिर चाहे तो मैं दोबारा बता देता हू। डालमियासीमेंट फैक्टरी, दादी को सरकारने टेक ओवर कर लिया थां यह अमाउंट किसी भी वक्त का हो, इसके लिये जो रिसीवर मुकर्रर किया था, उसके पास रिकवरी के लिये केस पैडिंग है।

आवाजे: स्पीकर साहब, हम यह पूछना चाहते है कि यह रूपया कब से पैंडिंग है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: यह काफी लम्बी चौड़ी इंफर्मे ान हे, अलग अलग कंजूमर्ज के खिलाफ अलग अलग डेटस से अमाउंट पैंडिंग है।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, हम इस बारे मे फ्रे ा नोटिस देंगे ताकि सरकार की मतरफ से पूरापूरा जवाब हमें मिल सके।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: ठीक है।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि डालमिया सीमेंट फैक्टरी, दादरी के खिलाफ 1 करोड़ 18 लाख रूपया बकााया है, कया यह पैसा उस फैक्टरी को सरकार के टेकओवर करने के बाद का है या कि पहले का । दूसरी बात यह है कि उस फैक्टरी के खिलाफ भारत सरकार ने 70 लाख रूपया और निकाला है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे इसका 20 परसेंट भी पैसा वापिस नही दे पायेंगी, क्या यह सच है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल तो पूछा नही, सूचना दी है, आफिसर्ज ने नोट कर ली होगी, इसका हम पता कर लेंगे।

चौधरी हुकम सिंह: स्पीकर साहब,श जो बड़क्षे बड़ इंडस्टियलिस्ट है,इनके खिलाफ लोखो` पैसा बकायाहोता है और वे जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले आते है। उनके मीटर वगैरह भी

डिसकनैक्ट नही किये जाते लेकिन जो छोटे छोटे कंज्यूमर्ज है, किसार है, चाहे उनके खिलाफ 40 रूपये ही क्यों न हो, उनकार कनैक ान एक दम काट दिया जाता है क्या ऐसे लोगो के लिये ऐसा नही हो सकता कि वे भी स्टे ले ले और उनके कनैक ान भी एक दम बिन सुचना के न काटै जाये?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, स्टे तो किसान ले ले, आर्डिनरी कंजूमर ले ले या बड़ा ले ले। स्टे लेने के लिये बिजली बोर्ड तो किसी को नही कहतार। लोग स्वयं परसयु करते है और हाई कोर्ट मे चले जाते है। जो बड़े बड़े कंजयूर्ज है नान पैमेण्ड केसिज मे उनके खिलाफ सरकार ने अव य कार्यवाही की है, इसके बारे मे मैं पहले बता चुका हूं।

Shri Virender Singh: He is always sevading every question, Sir.

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इसमे इवेडकर ने की कोई बात नही है। हमारी पूरी पूरी हमदर्दी लोगो के साथ है। 2119 इंडस्ट्रीज वाले डिफाल्टर पाये गये। उनमे से 1537 के कनैक ऱान काट दिये औरबाकियों मे से कुछ को स्टे मिला हुआ है और कुछ एक से एकज एरियार्ज ऑफ लैंड रैवेन्यू रिकवरी हो रही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जो रिकवरी का ढंग बताया, उससे हम लोगो को संतोश नही होता है। स्पीकर साहब, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के लिखाफ साढ़े 9 करोड़ रूपये बकाया है। सरकार इनको सबसिडी भी देती है इसके बावजूद भी हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर लोगों को वि वास नही है। प्राईवेट इंडस्टरी वाले भी कोर्ट मे चले जाते है और पब्लिक अंडरटेकिंगज वाले भी कोर्ट मे चले जाते है, इस कारण से उनके कनैक ानज नही कटते। कोर्ट मे पांच छ साल तक केस चलते रहते है। सरकार जिस तरह से डोमैस्टिक कनैक ानज को पहले बिल की पेमैंण्ट न होने पर काट देती है, इन बड़े इंडस्ट्रीज वालों के साथ भी ऐसा क्यों नही किया जाता कि उनके कनैक ंज भी पहले बिल की नान पैमैंझट कीवजहइ से काट दिये जाये। ऐसा करने से आगे के लिये सरकार को किसी किस्म की दिक्कत नही होगी और न ही वे लोग कोटस मे जा कर स्टें ले सकेंगे। क्या ऐसा प्रोसीजर सरकार अडाप्ट करने का विचार रखती है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, कनैक ान काटने काप्रोसीजर मैं बतादेता हूं। पहले एक महीने तक अगर कोई बिल की पैमैंट नही करता तो फिर ग्रेस पीरियड तक इंतजार किया जाता है। अगर तब तक भी बिल की पेमेंट न हो तो फिर कनैक ान टैम्पोरेरी तौर पर काट दिया जाता है। अगर वह एक महीने मे उसको रिवाइव नही करवाता तो उकसा परमानैंट

कनैक ान काट दिया जाता है। मतलब मीटर और वायर वगैरह काट देते है या उतार देते है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय अधिकारी 60 दिनों का नोटिस देकर रिकवरी की प्रोसीडिंग्ज भुरू करते है। इस प्रोसीडिंग केखिलाफ लोग फिर कोर्ट मे जाते है तो वहां से उनको स्टे मिल जाती है। वैसे ऐसी कोई बात नही है कि उन लोगो के साथ कोई रियायत की जाती हो, सभी के साथ एक ही व्यवहार किया जाता है। हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी टयूट एक्ट, 1970 के तहत एज एरियाज आफ रैवनयू रिकवरी की जाती है।

श्री फतेह चंद विजः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदयने डिस्कनैक ान का प्रोसीजर बतायाहै कि पहले एक महीने तक अगरकोर्अ बिल कीपेमैंट नही करता तोउसे प्रेस पीरियड दियाजाता है । अगररि भी पेमैंट नही होती तो टैम्पोरेी तौर पर कनैक ान काट दियाजतात है क्या मंत्री महोदया बतायेंगे कि इतने दिनो तकइंतजार करने की क्या आव यकता है। एक हीमहीने मे सरी कार्यवाही फाइलन करकेकनैक्शान क्यों नही काट दिया जाता ताकि सरकार को भी फायरनैि ायल लौस न हो और कंजयूमर भी आगे से इस बाम का ध्यान रखे कि समय पर बिल की पेमैंट करनी है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हमें प्रोसीजर के अनुसार ही सारी कार्यवाही करनी पड़ती है।जैसा कि मैंने बताया है कि एक महीने तग अगर कोई बिल कीपेमैंअ नही करता तो फिर ग्रेस पीरियड तक इंतजार किया जाता है अगर तब तक भी बिल की पेकमैंट न हो तो टैम्पोरेी तौर पर कनैक ान

काट दिया जाता है । अगर एक महीने तक उसको रिवाइव नह ीकरवाया जाता तो फिरपरमोनैट कनैक ान काट दिया दिया जाता है। उसके बार फिरअगर नान पेमैंट का केस हो, तो 60 दिनों का नोटिस देकर अधिकारी संबंधित पार्टी या आदमी के खिलाफ इंक्वायरी भुरू कर देते है और इलेक्ट्रीसिटी डयूट एक्ट, 1970 के अंतर्गत एज एरियार्ज आफ लैंडरेव्न्यू रिकवरी की जाती है।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि डोमैस्टिक और कमर्ि ायल कनैक ानज को डिसकनैक्ट करने का अलग अलग क्राईटेयिा क्या है। जो इन्होने अभी ब्यान किया वह डोमैस्टिक केबारे मे था या कमर्ि ायल के बारे मे था?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सभी कंज्यूमर्ज के लिये एक ही क्राईटेरिया हैं सिर्फ डिसकनैक्ट करने केअख्तियार मे फर्क है। 100 के0वी0 तक तो एस0डी0ओ0, 500 के0वी0 तक एक्सीयन, 1000 के0वी0 तक एस0ई0 और 1000 के0वी0 से ऊपर के लिये हैउक्वार्टर परचीफ इंजीनियर को अख्तियार है। बड़े कनैक ांनज मे इसलिये देर लग जाती है कि उनका केस हैडक्वार्टर तक पहूंचते देर लग जाती है।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, जो कमर्ि ायल कनैक ाज है या जो तिजारती अदारे या फैक्टीज है उनमे कुछ स्माल युनिटस भी होती है और कुछ बड़ी यूनिटस भी होती है।

कुछ बड़ी युनिटस भारत सरकार के लेवल की भी होती है और कुछ यूनिटस स्टेट लैवल कीहोती है। इस लिस्ट केअंदर जो बड़े बड़े अदारे है वह मैं समझता हूं कि भारत सकरार के लैवल के अदारे है। क्या उकने लिये भी वही क्राईटेरिया है जो हरियाणा के आदम दुकानदारो के लिये या छोटे कारखानों के लिये है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जनवरी 1983 मे हरियाणा मे 48864 इंडस्टियल कंज्यूमर्ज थे उनमे से लार्ज 796 थे, मीडियम 3603 और स्माल 44465 थे। सप्लाई का क्राईटेरिया यह है कि 100 के0वी0 से उपर लोड तक तो लार्ज माना जाता है, 21 से 100 के0वी0 तक मीडियम माना जाता है ओर 20 के0वी0 तक स्माल माना जाता है। जहां तक पैसेवसूल करने के क्राइटेरिये का संबेंध है उससे उनका मतलब रिकवरी से होगा। उसके बारे मे कोइ डिफरैंट क्राईटेरिया किसी के लिये नही है, सब के लिये एक ही क्राईटेरिया हैं

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सारा हाउस इस बरे मे बहुत कंसर्ड है कि पूंजीपतियों से बिजली केबिलनहीलिये गये। हमें कुछ इस मामले मे संदेह हैं इस बारे मे हमारे टैजरी बैंचिज के भाई भी कह रहे है और हम भी कह रहे है । इस लिये आप इस पर आधे घंटे की डिस्क ान मान लीजिये। उस पर हम अपनी बात कह सकेंगे, अब तो इतनी सप्लीमैंटरी पूछने की इजाजत नही मिलेगी।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, मैंने इसलिये तो इतना ज्यादा टाईम इस सवाल पर दिया है।

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे अभी इन्होंने डा0 ओम प्रका ा जी से सवाल के जवाब मे बताया कि बिलों की अदायगी के लिय सब के साथ एक जैसा ही तरीका हैं क्या मत्री जी बतायेंगे कि जिन से इतनी धन रा ि ा लेनी है उनके साथ भी वही प्रोसीजन अपनाते है क्या उनका कनैक ान भी टैम्पोरेरली डिसकनैक्ट किया जाता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, मैं पहले भी बिता चुका हूं कि हमने 1500 के करीब कनैक ान काटे है। जो बाकी हे उनके बारे मे भी किसी ने किसी स्टेज पर कार्यवाही चल रही है। किसी के केस मे कोर्ट ने स्टे कर दिया है और किसी का केस आर्बीट्रे ान मे चल रहा है

मास्टर ि ाव प्र ाादः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूछने का मतलब यह था कि जब उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया उससे पहले इतना समय था जिसमे ये अपने पोसीजर को अपनाते हुए कनेक ान काट सकते थे,

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः माननीय सदस्य अगर किसी वि ोश केस के बारे मे पूछेंगे तो मैं मुकम्मल तौर पर बता

सकता हूं। सैंकड़ों केसों के बारे मे मैं इस समय आफ हैंड नही बता सकता।

श्रीमती बसंती देवीः अध्यक्ष महोदय, जो लोग इतने दिनों तक 50–50 लाख रूपये के बिजली के बिल पे नही कर पाए क्या जिस वक्त वेपे करेंगे उनसे इन्ट्रैस्ट भी लिया जाता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः उन पर 2 प्रति ात सरचार्ज लगाते है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, पिछले दिनों चौधरी भजन लाल जी ने जब भिवानी के बारे मे रिलीफं दिया तो उस समय किसानों की तरफ 17 लाखरूपये बकाया थेक। हमने इनको कहा था कि 31 मार्च की बजाये किसानों को 31 मई तक की एक्सटैं ान दे दी जाये। क्या मत्री जी बतायेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्टस के साथ ये लिनिएंट व्यू क्यों अपनाया जा रहा है? उन्होंने एक एक साल से उपरका रूपया रोका हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डालमिया सीमेंट फैक्टरी की रिकवरी किस स्टेज पर है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्ट भिवानी से चले थे ओर पता नही किस 17 लाख रूपये की बात कर गये उसने बाद डालमिया की तरफ पहुंच गये। मैं इनको बताना चाहता हूं कि डालमिया की तरफ कोई रिकवरी बकाया नही है। डालमिया फैक्टरी तेा गवर्नमैंअ ने टैक

ओवर कर ली गिरी ओर वह लिक्वीडे ान मे चली गई थी, उनकी तरफ बकाया है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, पहला सवाल मेरा यह था कि पीछे मुख्य मंत्री जी ने बिजली के रेट बढ़ाने के बारे मे भिवानी जिले के किसानो को रिलीफ दी थी । किसानो की तरफ 17 लाखरूपया बकाया थ। मुख्य मंत्री जी ने कहा गिा कि यह पेमैंट 31 मार्च तक करनी होगी ओरहमने कहा था कि यह पैमैंट 31 मई तक कर दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े इंडस्ट्रयलिस्टस की तरफ तो एक एक साल से इतनापैसा बकाया पड़ा है किसानो को टाईम क्यों नही दिया जाता?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी ने लोगों की और उस इलाके के विधायक की बात को मानते हुए डीप टयूबवैल वाले किसानों को बड़ा भारी कनसै ान दिया ओर साथ्र मे जासे उन्होंने डिफाल्ट किया था उस बारे मे भी यह कहा कि वह अप्रैल के महीने मे दे देगा जो उनके खिलाफ पीछे की कार्यवाही है वह नही की जायेगी। अब पता नही ओर कौन सी बात पूछ रहे है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन प्राईवेट इंडस्टीज को बिजली के

बिलों की अदायगी का कोर्ट से स्टे मिला हुआ है जब उन केसों का कोर्ट से फैसला हो जायेगा तो क्या वह सारा अमाउंट विद इन्टैस्ट वसूल किया जायेगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे पहले ही बता चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग बिजली के बिलों की दो परसैंट सरचार्ज लगाकर रिकवरी की जाती है

श्री राम विलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि किन किन कारखानेदारों की तरफ एक लाख से उपरके बिजली के बिलों की रिकवरी बाकी है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, एक लाख से उपर जिन जिन कारखनेदारों की तरफ करवरी बाकी रहती है, वह इस प्रकार हैः—

M/s Northen India, Ballabgarh	Rs. 73 lacs
M/s P.C. Maheshwari, Ballabgarh	Rs. 16.34 lacs
M/s Oswal Steels, Faridabad	Rs. 7.88 lacs
M/s S.G. Steel, Ballabgarh	Rs. 10.75 lacs
M/s Dabriwala, Faridabad	Rs. 17.38 lacs

M/s B.T.M Bhiwani	Rs. 49.83 lacs
M/sMohta Electro Steel, Bhiwani	Rs. 10.65 lacs
National Fertilizers Ltd. Panipat	Rs. 3.59 lacs
M/s Haryana Concast, Hissar	Rs. 209 lacs
M/s Dalmia Cement Factory, Charkhidadri	Rs. 118.64 lacs
M/s Nepco Faridabad	Rs. 2.21 lacs
M/s Paryag Dass Faridabad	Rs. 1.61 lacs
M/s Prem Enterprises, Rewari	Rs. 2.28 lacs
M/s Sehgal Paper Mill, Dharuhera	Rs. 40.44 lacs
M/s I.T.C. Haryana, Chandigarh	Rs. 130 lacs
Municipal Committees and Panchayat in the State	Rs. 20 lacs
M/s Orient Steel, Faridabad	Rs. 1.84 lacs
M/s Hindustan Wires Ltd., Faridabad	Rs. 3.22 lacs
M/s Venus Paper Mill, Faridabad	Rs. 2.41 lacs
M/s Haryana Paper Mill, Faridabad	Rs. 1.83 lacs
M/s H.S. Sethi, Faridabad	Rs. 1.90 lacs

M/s Lajwani Chemicals, Faridabad	Rs. 5.84 lacs
M/s H.N.G. Bahadurgarh	Rs. 1.05 lacs
M/s Swastika Woolen Mills, Panipat	Rs. 1.16 lacs
M/s Swastika Woolen Mills, Panipat	Rs. 1.02 lacs
M/s Rajpura Singla, Panipat	Rs. 1.13 lacs
M/s Steel Sales, Panipat	Rs. 1.61 lacs
M/s Amar Flour Mills, Sirsa	Rs. 1.08 lacs
M/s India Steel Alloy, Hissar	Rs. 2.66 lacs
M/s Godara Cotton Factory, Sirisa	Rs. 1.19 lacs
M/s Seth Suraj Mall, Sirsa	Rs. 2.49 lacs
M/s Barmalt, Gurgaon	Rs. 1.22 lacs
M/s Apricot, Faridabad	Rs. 3.38 lacs
Lift Irrigation	Rs. 1.00 crore
M/s Haryana Electro Steel, Sonepat	Rs. 6.88 lacs

श्री हरि चंद हुड्डाः स्पीकरसाहब, रूल के मुताबिक यदि कोई आदमी सरकार का डिफाल्टर हो, जब तक वह आदमी अपने डिफाल्ट को दूर नही कर लेता तब तक वह सरकार की कोई भी फैसिलीटीज नही ले सकता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं

कि जो आदमी सरकार का डिफाल्टर है क्या उसको फैथ्सलीटीज दी हुई है अगर दी हुई है तो कयों दी हुई है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य पता नही किस किस्म की फैसियलीटी के बारे मे पूछना चाहते है। इनको अपने सवाल मे यह बात क्लीयर करनी चाहिए थी कि किस फैसिलिटी के बारे मे जानना चाहते है। (ाोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, अब क्वै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित

प्र नों के लिखित उत्तर

Haryana Government cases handled by the private Adocates of Supreme Court and Hight Court

***290. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of private Advopcates of Supreme Court and Punjab and Haryana High Court practising inDelhi and Chandigarh respectively, entrusted with Government cases since the date the present Advocate General of Haryana took over the charge;

(b) the descriptions of cases entrusted to eachone of the advocates referred to in part (a) above togetherwith the amount of money paid in each cases; and

(c) the number of cases involving the Boards and Corporations of Haryana handled by the said Advocate General and the amount of money paid to him in each case?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) से (ग) सूचना इकटठी करने मे जो समय और परिश्रम लगेगा उससे वि ोश लाभ न होगा।

Uniforms to Haryana Roadways Employees

***234. Shri Devi Dass:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether any unifosrm is given to the Conductors and Drivers of Haryana Roadways; if so, whether the same is made of woollen, cotton or terrycot cloth;

(b) the total amount spent ont he supply of the said uniforms during the period from January, 1982 to January, 1983 alonwith the rate of per metre cloth thereof;

(c) the total amount of expenditure incurred on sewing the said uniforms togetherwith the sewing charge paid per unifiorm during the said period separately;

(d) the name of the Agency with its address from wherw the said cloth was purchased; and

(e) whether uniforms are also given to the employees of Haryana Roadways other than the Conductors and Drivers; if so, the categories thereof?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Yes, the conductors and Drivers of Haryana Roadways are provided woollen uniform in winter and terrycot uniform insummer. Malmal cloth for turbans is also given.

(b) The statement at Annexure I is laid on the Table of the House.

(c) (i) Total expenditure incurred on sewing of uniforms: Rs. 404288/-

(ii) Rate of sewing charges paid per inifor:-

(i) Woollen uniform : Rs. 38.10 to Rs. 80.00

(ii) Terrycot uniform : Rs. 18.50 to Rs. 25.00

(d) The Statement at Annexure II is laid on the Table of the House.

(e) Yes, the uniforms are also given to:-

(i) Operational Staff.

(ii) Workshop staff.

(iii) Class IV staff.

Annexure I

(i) Total amount spent on uniforms during the period from January, 1982 to January, 1983 Rs. 2975582/-.

(ii) Rate of Cloth per metre:-

(a) Woollen Serge : Rs. 94.50

(b) Terrycot : (i) Rs. 41.81

(ii) Rs 45.54

(c) Malmal : (i) Rs. 3.31

(ii) Rs. 3.39

Annexure II

(i) Woollen Serge : M/s New Egeton Woollen Mills, Dhariwal.

(ii) Terrycot Cloth : (i) M/s Jagatjit Cotton Textile Mills Ltd.,

Phagwara.

: (ii) M/s. Beni Parshad & Co. Amritsar.

(authorised by M/s J.C.T. Mills Ltd.)

(iii) Malmal : (i) M/s. Goyal Corp., Chandigarh.

(ii) M/s. Swastika Trading Corp.

Ambala Cantt.

Accidents on G.T. Road in the State

***251. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the total number of motor vehicle accidents occurred on G.T. Road in Haryana from 1st September, 1982 to-date;

(b) the total number of persons died or periously unjured in the above said accidents during the said period; and

(c) whether the Government proposes to widen the said road at some specific places on G.T. road to facilitate overtaking by heavy vehicles at such specific places only tioll the four lane road is conpleted?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) 193 (28—2—1983)

(ख) मरे 82

घायल हुए 230

(ग) जी हां।

Benefits to MilitaryPensioners re-employed in Civil Departments

***262. Chaudhri Balvir Singh Grewal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the revised Scale of Pay Rules; 1980 have beenmade applicable to the military pensioners inthe service of Haryana Government;

(b) whether the benefit of exemption of military pension upto Rs. 125/- while fixing the pay of a military pensioner in the Civil Department has been allowed to all such millitary pensioners as were in Haryana Government service before or after 1-4-79 upto 1-2-83,if not, the reasons therefore; and

(c) whether all the military pensioners appointed in Civil Dept. on similar categories of posts before or after 1-4-79 upto 1-2-83 are drawing the same pay scales; if not, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नही।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

Shortage of Electric Power in the State

***270. Shri Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it an acute shortage of electric power in the State at present; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to overcome this shortage?

Irrigation and Powder Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): There is no acute shortage of electric power in the State at present. Continuous watch is kept to improve the performance of thermal units of the State.

Motital Nehru Schol of sports

***285. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister of State of Technical Education be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred on the Motilal Nehru School of Sports, Rai During the financila years 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 to date;

(b) the total number of students in the School during the years referred to in part (a) above, separately;

(c) the number of studients out of those referred to in part (b) above belonging to scheduled Castes, Backward, Classes and Rural area, separately; and

(d) whether all the categories of studients are charged the same amount of fee or different categories of students are charged differently?

Minister of State of Technical Education (Shri Lachhman Dass Arora): The requisite information has been indicated in the enclosed statement which is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The Total expenditure incurred on Motilal Nehru School of Sports, Rai during the financial year 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 to date is as under:-

	Year 1979-80	Year 1980-81	Year 1981-82	Year 1982-83 (upto Feb. 83)
Plan	1590050/-	3045396/-	1142245/-	482270/-
Non-Plan	4045757/-	4291251/-	4926638/-	4941371/-
Total	5635807/-	7336647/-	6068883/-	5423641/-

(b) Total numbers of students in the School during the years referred to in part (a) above is given below separately:-

Years	Boys	Girls	Total
1979-80	415	144	559

1980-81	406	156	562
1981-82	449	168	617
1982-83	455	150	605

(c) The numbers of studients out of those referred to in part (b) above belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and rural areas separately are asunder:-

Years	Scheduled Castes	Backward Classes	Rural Area
1979-80	12	4	206
1980-81	14	5	305
1981-82	16	8	324
1982-83	20	9	351

(d) The school fee of Rs. 2500/- per year, but Haryanavee students are charged concessional fee in the following manner:

(a) Students whose presnts income is Rs. 500/- or below, will be free.

(b) Students whose presnts income is between Rs. 501/- and Rs. 1000/- per month, will pay Rs. 600/- per annum.

(c) Students whose presnts income is between Rs. 1001/- and Rs. 1500/- per month, will pay Rs. 1200/- per annum.

(d) Students whose presnts income is between Rs. 1501/- and Rs. 2000/- per month, will pay Rs. 1800/- per annum.

(e) Students whose presnts income is between Rs. 2000/- will pay Rs. 2500/- per annum.

(f) Students who are admitted through lateral entery are required to pay full fee of Rs. 2500/- per year.

Upgradation of Schools

***279. Ch. Nar Singh:** Will the Minister of State of Education be pleased to state the constituency wise number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High Schools during the period from 1978-79 to 1981-82?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी है।

सूचना

क्र0 संख्या	जिले का नाम	कौन स्टीच्यूए का नाम	प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च
1	**अम्बाला**	कालका	5	4
		नारायणगढ़	5	10
		सढौरा	5	2
		छछरोली	7	4
		यमुनानगर	5	2
		जगाधरी	2	3
		मुलानां	6	6

		अम्बाला छावनी	1	–
		अम्बाला भाहर	2	–
		नागल	7	6
		कुल	45	37
2	**भिवानी**	बढ़ड़ा	7	6
		दादरी	6	3
		मुढ़ालखुर्द	7	3
		भिवानी	2	2
		तो ाम	10	6
		लोहारू	9	8
		बवानी खेड़ा	10	5
		कुल	51	33
3	**फरीदाबाद**	फरीदाबाद	3	4
		मेवला महाराजपुर	9	4
		बलबगढ़	7	3
		पलवल	6	3

		हसनपुर	5	5
		हथीन	9	6
		कुल	39	25
4	**गुड़गांव**	फिरोजपुर झिरका	8	6
		नूह	12	1
		तावडू	10	6
		सोहना	5	3
		गुड़गांव	5	3
		पटौदी	5	3
		कुल	45	25
5	**हिसार**	बरवाला	4	2
		नारनौद	4	6
		हांसी	6	5
		भट्टूकलां	18	10
		हिसार	2	3
		घिराये	5	10

		टोहाना	14	6
		रजिया	6	7
		फतेहाबाद	10	7
		आदमपुर	19	14
		कुल	88	70
6	**जींद**	कलायत	4	4
		नरवाना	9	4
		उचाना कलां	5	6
		राजोंद	4	2
		जुलाना	7	7
		जींद	10	3
		सफीदों	11	3
		कुल	50	29
7	**करनाल**	इंद्री	11	6
		नीलोखेड़ी	9	5
		करनाल	—	2

		जुंडला	8	5
		घरोंडा	11	3
		अंसध	4	6
		पानीपत	4	1
		सामलखां	4	3
		नौलथा	3	3
		कुल	54	34
8	कुरूक्षेत्र	भााहबाद	9	3
		रादौर	7	5
		थानेसर	9	5
		पिहोवा	7	4
		गुहला	7	3
		कैथल	2	4
		पुण्डरी	6	6
		पाई	3	1
		कुल	50	31

9	**महेन्द्रगढ़**	बावल	9	6
		रिवड़ी	7	5
		जाटूसाना	8	4
		महेन्द्रगढ़	11	7
		अटेली	11	8
		नारनौल	7	3
		कुल	53	33
10	**रोहतक**	हसनगढ़	3	6
		किलोई	2	2
		रोहतक	—	1
		महम	3	9
		कलानौर	9	5
		बेरी	6	5
		साहलावास	13	6
		झज्जर	5	6
		बादली	7	3

		बहादुरगढ़	10	8
		कुल	58	51
11	**सोनीपत**	बरोदा	3	8
		गोहाना	6	5
		कैलाना	15	9
		सोनीपत	2	3
		राई	4	3
		रोहट	4	4
		कुल	34	32
12	**सिरसा**	ऐलनाबाद	1	3
		सिरसा	12	3
		रोड़ी	15	5
		डबवाली	9	5
		दड़बाकलां	11	5
		कुल	51	21
		कुल जोड़	618	421

Sugar Mill at Shahabad

***309. Shri Nirmal Singh:** Will the Minister for Coopration be pleased to state—

(a) whether any cooperative Sugar Mill is proposed to be set up at Shahabad; and

(b) if so, details of the areas proposed to be brought unde the operation of the said Mill?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) प्रचालन क्षेत्र हरियाणा गन्ना नियंत्रण बोर्ड द्वारा चीनी मिल के कार्य आरम्भ करने के समय नियत किया जायेगा।

Prevention of Blindness

***325. Master Shiv Parshad:** Will the Minister be healthe be pleased to state—

(a) whether any scheme has been formulated for the prevention of belindness in the State;

(b) whether any grant is being received from the Government of India for the scheme, referred to in part (a) above, if

any formulated; if so, the amount so received during the year 1982-83 (to date); and

(c) whether the Government proposes to provide eye specialists in the rural primary health centres in the State for the Treatment of eye diseases of rural people?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्श 1982–83 मे अब तक भारत सरकार द्वारा 4.79 लाख रूपये की धनरा ि । प्रदान की गई

(क) जी नहीं।

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि * * * * * * * * * * * ** * *(ाोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है * * * * * * * * (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह जो पर्सनल बातें हुई है, इन को रिकार्ड न किया जाये।

ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न–

चौधरी हरद्वारी लाल, वाइस चांसलर, महर्शि दयानंद युनिवर्सिटी रोहतक संबंधी

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही सीरियस बात कहना चाहता हूं कि कल जब हम यहां आए तो चैम्बर से बाहर जो मैंबर्ज के हस्ताक्षर करने के लिये रिजस्टररखा हुआ है, उस जगह पर एक आदमी इस रंग का पम्फलैट बांट रहा था जो इस समय मेरें हाथ मे है। उस आदमी ने मुझे वह पम्फलैट लेने के लिये कहा। मैंने उसे कहा कि यह क्या है? उस आदमी ने कहा कि वाइस चांसलर श्री हरद्वारी लाल जी ने यह पम्फलैट लिखा हैं मैंने उसे कहाकि रहने दीजिए मुझे यह पम्फलैट नही पढ़ना, आप यह पम्फलैट श्री हरद्वारी लाल जी को वापिस दे दीजिये। स्पीकर साहब, बाद मे वह पम्फलैट मैंने अपने साथियों से लिया औरा बड़े गौर से पढ़ां उन्होंने इस पम्फलैट मे प्रैस की भी काफी आलोचना की है। चलो यह बात जो प्रैस वाले जाने, उनको प्रैस के बारे मे कहने का संवैधानिक अधिकार है। स्पीकर सहाब, उन्होंने इस हाउस के बारे मे भी इस पम्फलैट मे बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने इस हाउस की डिगनिटी को अंडरमाइन किया है। स्पीकर साहब,ख उन्होंने आप पर भी एसप र्न किये है। उन्होने इस पम्फलैट मे माननीय सदस्यों का हयूभिलेटिंग ढंग से जिक्र

किया है। सभी माननीय सदस्यों को मीन कहा है। और यह भी कहा है कि सभी सदस्य उन स्क्रूपलस हैं वे जो गालियां उन्होंने दी है। उन्होने गवर्नर साहब को भी नही बख्शा। उन्होंने अपने पम्फलैट मे यह भी लिखा है कि गवर्नर साहब ने जो कार्यवाही की थी, वह गलत की थी। उन्होंने गवर्नमैट को भी नही बख ा। उन्होंने गवर्नमैंट के बारे मे लिखा है कि कैबिनेट के मिनिस्टर्ज ने मेरे खिलाफ साजि ा की थी और मैमोरैंडम लिखवाए थे। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, सारी बातें क्लीयर हो गई है। आपने जो प्रिविलेज मो ान का नोटिस दिया था, वह मुझे मिल गया है, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह मामला बहुत ही सीरियस हैं यह प्रिविलेज मो ान का नोटिस सारी अपोजी ान के मैंबर्ज ने दिया है और उस नोटिस से ट्रेजरी बैंचिज को भी कंसर्ड होना चाहिए। यह सारे हाउस की इज्जत का सवाल है। कोई आदमी अबव बोर्ड नही है। श्री हरद्वारी लाल ने अपने आपको एंजल प्रोजैक्ट किया है ओर हम सब को अंडरमाइन किया है। आप उस प्रिविलेज मो ान के नोटिस को एडमिट कीजिए और प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिये।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं। जो भी फैसला होगा उसका जवाब आपने पास भेज दिया जायेगा।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना–

गांव बोहड़ाकलां मे व्यापत डर तथा भय संबंधी

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा मे एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था कि गुड़गांवा जैसे मे बोहड़ा कलां गांव मे भ्रश्टाचार के खिलाफ बहुत जब्रदस्त आंदोलन ही रहा है और वहां के लोगों मे जुल्म के खिलाफ बहुत असंतोश हैं मैने अपनी काल अटैन् ान मोशन के नोटिस के साथ गुड़गांवा जिलें की 93 पंचायतों के हस्ताक्षरों का एक पत्र भी जोड़ऋा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे काल अटैंशन मो ान को स्वीकर करें और सरकार से कहें कि वह इस बारे मे अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं। जो भी फैसला होगा उसका जवाब आपके पास भेज दिया जायेगा।

प्वायंट आफ आर्डर–

विधान भवन मे मैम्बर्ज को पम्फलैट/पब्लिके ान डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कल जब चेयरमेन साहब हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे उस समय मेने यह क्वै चन रेज किया था कि श्री हरद्वारी लाल द्वारा लिखित पम्फलैट बांटा गया था। स्पीकर साहब, चैम्बर के गेट पर यहां मैंबर साहेबान रजिस्टर मे साईन करते है, उस जगह पर वह पम्फलैट बांटा गया था। उस पम्फलैट के आपके खिलाफ और दूसरे सभी माननीय सदस्यों के खिलाफ बहुत अ ाोभनीय बातों की चर्चा की हुई है। इस संबंध मे मैने कल भी क्वै चख्न रेज किया था उस समयचेयरमैन साहब ने यह आ वासन दियाथा कि वे इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि आया इस प्रकार का कोइ पम्फलैट विधानसभा की परसिंकटस के अंदर बांटा जा सकता है या नही। उन्होंने इस बारे मे अपनी रूलिंग रिजर्व रखी थी। स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो पम्फलैट बांट ा गया है आया वह आपकी इजाजत से बांटा गया है या विधान सभी के किसी एम्पलाई की तरफ से बांटा गया है?

श्री अध्यक्ष: हमारा कोई एम्पलाई बिना परमि ान के ऐसा पम्फलैट डिस्ट्रीब्यूट नही कर सकतां अगर विधान सभा के किसी एम्पलाई ने वह पम्फलैट मैंबर साहेबान को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो मैं उस एम्पलाई के खिलाफ सख्त एक ान लूंगा।

प्रोफेसर सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे पास एक नौजवान आयाथा वह हरियाणा कनफैड के आुसि मे सर्विस करता

था। उसको कनफैड से 30 महीने तक की तनखाह अब तक नही मिली है। उस कर्मचारी को ससपैंड केर दिया गया था। उसको पहले बहुत थोड़ी तनखाह दी जाती थी। उसको सस्पैं ान पीरियड का अलांउस भी नही दिया गया है। उस आदमी ने धमकी दी है.....(ाोर एवं विध्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय जब तक आप किसी मैंबर को बोलने की इजाजत नही देंगे तो वह बात रिकार्ड नही होनी चाहिए। इसके अलावा जब तक कोई मैंबर किसी विशय के बारे मे आपकी लिख कर के नही देता है, उसको उस विशय पर बोलने के इजाजत नही दी जानी चाहिए। उन्होंने आपको लिख करके कोई भी नोटिस नही दिया है फिर भी यह आपकी इजाजत के बगैर बोल रहे है। इसलिये इनकी बातों का रिकार्ड नही किया जाना चाहिए। (ाोर एवं विध्न)

Mr. Speaker: I would request the hon. Member go please give a proper notice for any matter that he wishes to raise. I will not permit is to be raised like this.

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, सदन के अंदर हुड्डा साहब ने जो लीडर आफ दि हाउस की भाान के खिलाफ बात कही है, वह अपनी नर्मी के कारण ही कही है। कुछ लोग आपकी नर्मी का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। * * *

* * * * * यह बात मुझे बड़े खेद के साथ कहनी पड़ रही है। (ाोर)

श्री हरि चंद हुड्डा: स्पीकर सहाब, मैं बड़ी नर्मी से एक बात और कहना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। As I have already ordered, the personal exchanges that have taken place between you and the Leader of the House will not be recorded.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हरद्वारी लाल जी के खिलाफ प्रिवलेज मो ान लाने की बात डा0 मंगल सैन जी ने कही है। इस संबंध मे मैं भी कुछ कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं उसे सभी कंसिडर कर रहा हूं।

श्रीमती चन्द्रावती: जो बात सम्पत सिंह जी ने कही है, वह भी मैं कहना चाहती हूं। स्पीकर साहब, मेरे पास भी एक चिट्ठी आई है। (ाोर)

चौधरी भजन लाल: आप लिख कर नोटिस दे।

Mr. Speaker: I have alredy said that a proper notice for that may be given.

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

इलैक्ट्रानिक वोटिंग म ाीन संबंधी

Mr. Speaker: Now I am making an announcemnet. The Chief Electoral Officer of Haryana has arranged to display the lates model of the electronic voting machine today, the 23rd March, 1983 form 10 a.m. to 3 p.m. in the Committee Room of the Haryana Vidhan Sabha Secretriat. Hon'ble Members may please see the electronic voting machine in batches of 5 to 15.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

Mr. Speaker: Motion moved—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर माहेदय, मंत्री जी ने रूल 30 को सस्पेंड करने के लिये कहा है। बृहस्पतिवार जो नौन आफिि ायल डे होता है उसको सरकार औफिि ायल डे मे कन्वर्ट करना चाहती है और इसलिये यह प्रस्ताव लाए है। आप भी

महसूस करते होंगे कि मैंबरो को बोलने के लिये पूरा समय दिया जा रहा है इस सदन के मैंबर होने के नाते हम प्रांत के लोगो के कहतोंकी बात यह और कों बात यहां पर ही कह सकते हैं स्पीकर साहब, जितने भी स्टेट के सब्जैक्ट है उसके बारे मे विधान सभा मे ही खुले तोर से पूछा जा सकता है और यही एक ऐसा मोाक ाहै यहां पर हर विधायक अपनी बात कह सकता है। नौन आफि ियल डे का जो कांस्टीच्यू ान के अंदर प्रोवीजन है उसी के आाध पर कोई मेंबर अपनी बात अलग से कह सकता है यह नौन आफि ाशिल `डे इसलिये बनाया गया है कि कोई भी मो ान लाने से पहले वह सैक्रेटरी साहब के पास जाता है वहा पर नम्बर लगता है फिर कहीं जाकर उस पर आगे बहस चलती है स्पीकर सहाब ये हमारे अधिकार छीनना चाहते है। आज डैमोक्रेसी का तकाजा यही है कि हरि विधायक अपनी आत साफ साफ कर सके। यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो विधायकों को अपने विचार प्रकट करने का मौका नही मिलेगा औरन ही कोई विधायक अपने ख्याल इमजाद कर सकेगा। यदि इस तरह से काम चलता रहा तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नही रहेगी। इस संबधं मे मेरी आप से प्रार्थन है कि आप इस प्रस्ताव पर दोबरा गौर करे। अंत मे मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से प्रार्थन करता हूं कि इसे पास न किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनोंद): स्पीकर साहब जब से मौजूदा असैम्बली का इजलास भाुरू ह आ है और वि ा ा तौरपर

जब से बिनैस एडवाईजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई है उसी समय से हम लगातार यही कोि ा ा करते रहे है कि वर्तमान सत्र का समय बढ़ाया जाये। जिससमय बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई है, उसी समय से हम लगातार यही कोि ा ा करते रहे है कि वर्तमान सत्र का समय बढ़ाया जाये। जिस समय बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस समय इतफाक से मैं औरराव निहाल सिंह जी भी आपके चैंबर मे मौजूद थे। मै खूद फील कर रहा था कि सरकार, बोलने के लिये हमें कम समय दे रही है आप भी चाहते थे कि समय और दिया जाना चाहिए क्योंकि जो समय सरकार देने जार ही है वह मैंबरों को बोलने के लिये कम है और आपकी आत्मा भी कहती थी कि कम समय दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः आप मेरी आत्मा के बारे मे कैसे कह सकते है कि मैं क्या चाह रहा हूं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपके सामने रूलज आफ प्रोसीजर थे, जिनके कारण समय बढ़ाने मे आप भी मजबूर थे। हमने हर मुमकिन कोि ा ा की कि समय बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ट्रेजरी बैचिज की तरफ से अभी तक मुि ाकल से सिर्फ 10 विधायक ही बोल पाये है और हमारे दल के भी मुि कल से सिर्फ 7–8 ही विधायक ही बोल पाये है । बाकी मैंबरों को न तो बजट पर बोलने का मौका मिला और न ही डिमांडों पर बोंलने का मौका मिल पाया है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा हतो

आज एप्रोप्रिए ान बिलों पर भी मु कल से एक घंटा या सवा घंटा ही मैंबर बोल पायेंगे। इस बार हमारे समय बढ़ाने की कोि ा ा आखिरी कोि ा ा होगी, क्योंकि फिर तो हाउस समाप्त होने जारहा है। इस संबंध मे मेरी आप से रिकवेस्ठ हे कि नौन आफि ायल डे को आफिि ायल डे मे कन्वर्ट न किया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे अधिकारों परकुठाराघात किया जायेगा हमारी तरफ से भी दो रैजोल्यू ान थे और धीमाज साहब कीतरफ से था। अभी मैंबरों ने उन पर अपने विचार प्रकट कर सके। जो प्रस्ताव ये ला रहे है उससे ये हमारे उपर कोई रहम नही कररहे । स्पीकर साहब, जेसा कि चर्चा चल रही हे कि ये सै ान के आखिरी मुख्य मंत्री होगे। ये जिस कुस्री पर बैठै है उस परदे ा मे इतिहास लिखा जायेगा और उसके साथ साथ इनके संबंध्या मे अन डैमोकेटिक भी लिखा जायेगा। स्पीकर साहब, प्राइवेट बात करते समय यह कहते है कि दुबारा सै ान बुलाने पर बहुत खर्चा आयेगा। मैं इन को अपने दल की तरफ से कहता हूं कि तीन चार छुट्टियों के बाद जब भी हम सै ान के लिये दोबारा इकट्ठे होंगे, यदि इन मुद्दोकं पर चर्चा हो जाती है, जो हाउस के सामने पे ा है तो हम उन दिनों का कोई अलांउस या भत्ता वगैरह नही लेंगे। यदि इसकेबाद भी ये नही मानंगे तो मैं यही कहूंगा कि–

अजब दस्तुर जबां बंदी है तेरी महफिल मे,

कि यहां कुछ कहने को तरसती है जबां मेरी।

श्रीमती चंद्रावती (बाढडा): ट्रैजरी बैंचिज कीतरफ से जो मो ान रूल 30 के तहत लाई गयी है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। स्पीकर सहाब, यह प्रस्ताव लाने से पहले जब बी0ए0सी0 की मीटिंग हो रही थी, उस समय गवर्नमैंट की तरफ से भी प्रतिनिधि थे ओरहमारे भी प्रतिनिध थे। उस समय हमाने बारबार यह कहा था कि इसनौन आफि ियल डे कोआफि ियल डे मे कंवर्ट न किया जाये। इस बात कोप्रत्येक मैंबर चाहता है कि चाहे वह अपोजी ान का है या टैजरी बैंचिज का कि इसे आफि ियल डे न बनाया जाये। जिस तरह से डैमोक्रेसी मे हमारे डैमोक्रेटिक अधिकार है, यह भी उन अधिकारों का एक अंग है, इसलिये हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए ताकि मैंबर साहेबान अपने हल्के की बात कह सके। सै ान का टाईम बढानें के लिये हमने बार बार अर्ज की थी, लेनिये माने हीनही। जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह नेकहा कि अगर खर्चा ज्यादा होने की बात है तोहम इन दिनों का भत्ता नही लेंगे, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं। और आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि हारउस को एक्सटैंड किया जाये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट जब सदन ने एडाप्ट की थी, उस वक्त हाउस को एक्सटैंड करेने पर विस्तार से विचार हुआ था और इन्ही तीन माननीय सदस्यों ने हाउस मे चर्चा की थी। अब रूल 30 की मो ान जो

हाउस मे आई है ,यह तो एक फार्मैलटी है लेकिन फिर भी हाउस के मैंबरान ने इसका फैसला करना है। अध्यक्ष महोदय, डा0 मंगल सैन जी ने कहा कि उनके इलाकें पर बड़ी भारी छापा मारा है। नान आफि ियल–डे को आफि ियल–डे मे कन्वर्ट करने के सिलसिले मे पहले ही काफी बाते हो चुकी है, मैं दउनबातों को इस वक्त रिपीट नही करना चाहता। उस वक्त माननीय सदस्यों का जो सुझाव था, उस पर विस्तारसे डिस्क ान हुई थी। धमीजा साहब के रैजोल्यू ान पर इन्होंने भुरू से ही कहा था कि वे इस पर डिस्क ान नही करना चाहते लेकिन फिरभी उस पर डिस्क ान भुरू हुई क्योंकि उस पर 12–14 आदमी हमारी तरफ से भी बोलना चाहते थे। हमने अपने मैंबरों का हक काट कर अपोजी ान की बात मानी। इनकी मांग का एतराम करते हुए हमने 25–3–83 को नान आफि ियल–डे को आफि ियल–डे मे कन्वर्ट किया ताकि इनको डिफरेंट मैंटर्ज पर बोलने के लिये ज्यादा वक्त मिल सके। स्पीकर साहब, इस के खिलाफ इनके पास कोई दलील नही है और बार बार एक ही बात को रिपीट करते है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने एक भोर पढ़ा है, मुझे भोयरो भाायरी तो आती नही लेकिन इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं–

नजर उनकी, जुबां उनकी फिर भी तजबुजब है,

नजर कुछ कहती है, जुबां कुछ कहती है उनकी।

ये अपोजी ान के लोग सिर्फ अपोज करने के लिये ऐसा कर रहे है, बात कुछ भी नही है।

श्री अध्यक्षः आजकल किसी की जुबान पर कंट्रोल नही है, जो मर्जी आये कह सकते है। अभी श्री ओम प्रका ा जी फरमा गये कि डैमोक्रेसी खत्म होने वाली है। (व्यवधान)

मास्टर ि ाव प्र ाद (अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि वे गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन मे बदल रहे है और सरकारी बिजनैस टेक अप करना चाहते है। इस के बारे मे मेरा एक सुझाव है कि जिस मेम्बर की तरफ से रैजाल्यू ान आया है, अगर वे अपने प्रस्ताव को विदड्रा कर रहे है, फिर तो इस दिन को आफि ियल डे कर लिया जाये वर्ना जो बिजनैस आलरेडील तय हो चुका है, उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 24th March, 1983.

The motion was carried

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सहाब, मैं सुझाव देना चाहता हूं अगर

आपकी इजाजत हो तो दोनों एप्रोप्रि ान बिल्ज इकट्ठे ही मूव कर दिये जाये और दोंनो पर इकटठी ही डिस्क ान हो जाये।

Mr. Speaker: Is it the sense of the House?

आवाजे: ठीक है जो, दोनो बिल इकटठे ही मूव कर दिये जाये।

Mr. Speaker: Al right.

बिल्ज

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1983

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1983

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to introduce—

(i) the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1983, and

(ii) the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1983,

Sir, I also beg to move—

(i) That the Haryana appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

(i) That the Haryana appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

As decided, these Bills will be discussed together and the hon'ble Members can speak on them. But, the motion in respect these Bill, will be put to vote separately.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, सदन मे एप्रोप्रिए ान बिल नं0 1 और 2 पर विचार करने के लिये मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है। जिस दिन सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस सदन मे पेश हुए थे, उस दिन हम वाक आउट कर गये थे औरह मे अपनी बात कहने का मौका नही मिला थताा। लेकिन आज 51, 91, 99, 316 रूपये की मांगों पर खर्चा करने के लिये सदन की स्पीकृती मांग रहे है। स्पीकर साहब 1982–83 मे इन्हौंने यह रूपया खर्च कर दिया है। स्पीकर साहब, आप जरा गौर फरमायें, किस बेरहमी के साथक जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को मिसयूज किया जा रहा है। फाईनै।स मिनिस्टर बड़े घिसेपिटे अंदाज मे, बड़ी बात कहनी थी तो काई वजनदार बात कहते और हम उनकी बात को स्वीकार कर लेते। ये तो कमजोर मुकददमे के कमजोर वकील है। इनका सदन मे बहुमत है। इसलिये सदनकमे बिल लेते आओ और पास करवाते चलो। स्पीकर साहब, डैमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमैंट मेक और पालियामैंटरी सिस्टम आफ गवर्नमैंट मे हमे अपनी बात कहने का अधिकारी है।

इन्होंने डिमांड नं0 2 के तहत जो रूपया खर्च किया हैक। इस खर्चे को जस्टिफाई करने के लिये इन्होंने कुछ भी नही कहा था। हां, जो टैक्स लगाया है उसकी वकालत जरूर कर दी कि इस टैक्स का आम आदमी पर कोई असर नही होने वाला है। इन्होंने इस बात पर कुछ नही कहा कि छोटी कैबिनेट होनी चाहिएख निगम तोड़ देने चाहिए। जहां तक इररैगुलेरिटीज का ताल्लुक है, इस बारे मे सदन मे काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इस पवर ज्यादा नही कहूंगा। डिमांड नं0 3 पुलिस विभाग से संबंध रखती है । इसमें कुछ एडी ानल पोसटें क्रिएट की गई है। चौधरी भजन लाल जी ने हाएस को बताया था कि 1982 मे 1722 आदमीर नये रख थे, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों को हटाया गया। वे कुछ सुविधाये लेना चाहते थे, उनकी कुछ कठिनाईयां थी, जिनको वे हल करवाना चाहते थे। लेकिन बजाये उनकी कठिनाईयों को हल करने के, इन्होंने उनको नौकरियों से निकाल दिया। इसके वाबलूद भी ये समझते है कि पुलिस इन्हें इमदाद देगी औरजब ये चुनाव क्षेत्र मे जायेंगे तो पुलिस इनके आगे पीछे होगी। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए) ये जनता पररोब डालने के लिये पुलिस वालों को ले जाते है। अंदर की कहानी तो पुलिस वाले ही जानते है।

Now, sir, i refer you to demand No. 5 wherein an additional amount of Rs. 1631020 jas neem asled fpr “(i) sanctioning of additional posts to ensure effective and

salutary measures against illicit distillation and sale of sup0erious/;adultrated liquor which if not checked can l3ead to boock tragedies and (ii)....." Further, an additional amount of Rs. 11385568 has been demanded on account of (i) sanctioning of additional posts (ii) grant of instalments of additional drarness allowance (iii) extensive touring by the eforcemnet stalff foir condemined vehicles, purchaswe of nwe cvbehcil efor mobile cheking units of important sales tax check barriers etc.

चेयरमैन साहब, सन् 1981 और 1982 के साल मे कालांवाली और नरवारलन मे नकली भाराब पीने से कितने आदमी मर गये थे। नरवाश्ना मे चौधरी भाम ेर सिंह जी का हल्का है। वहां कुछ लोग मरे थे कुछ अंधे हो गये थे लेकिन आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही नही की गई। रूपया तो ये लें लेंगे लेकिन उस का असर कुछ भी नही । चेयरमैन साहब, डिमांड नम्बर आठ मे फरमाते है कि जहां पर मंत्री रहते है।, उनकी बिल्डिंग की फरनि ांग के लिये और ज्यादा पैसे की आव यकता होगी क्योंकि प्राइसिज बहुत हाई हो गये है। डिमांड नम्बर नौ मे नेहरा साहब ने भी पनैसा मांगा है। यह पैसा कालेजिज के लिये मांगा गया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राईवेट कालेजिज की 95 परसैंट लौस को सरकार करवर करती है। जहां सरकार कालेजिज की बात कर रही है। वहां स्कूलों को भी सुविधायें देनी चाहिए। चेयरमैन साहब, अब तो प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज ने अपना एजीटेशन भी वापिस ले लिया है। आप लोगो की प्रैस्टिज का भी प्वायंट नही रहा। प्राईवेट स्कूल6ों के

टीचर्ज यहां आये थे और उन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन अब वह वापिस ले लिया है इस लियेक अब तो इनकी बात सरकार को मान लेनी चाहिए। इन लोगो की दो मेन डिमांडज है, एक तो टेजरी से तनखाह और दूसरे गवर्नमैंट सर्वेंटस के बराबर का ए0डी0ए0। तीसरी डिमांड मैडिकल फौसिलिटीज के बारे मे है। वह भी सरकार को मान लेनी चाहिए क्योंकि बीमारियां तो सभी के लिये बराबर होती है। चेयरमैन साहब, इन्होने 83 लाख रूपये मे से 8 लाख रूपया दयानंद महर्शि यूनिवर्सिटी के लिये मांगा हैं। चेयरमैन साहब, इसके बारे मे तो मैं कल बिल पर ही बोलूंगा। लेकिन हाउस को बताना चाहता हूं िदुल्ल्त साहब की रिपोर्ट 58 पेज की है। उसरिपोर्ट मे और वे किस प्रकार के थे। इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि म्यूनिस्पिल कमेटी को बड़ी उदारता से पैसा दिया जाना चाहिए। हरियाणा प्रांत की आबादी एक करोड़ 30 लाख बनती है, और हरियाणा की कुल आबादी का 30 परसैंट हिस्सा भाहरों मे रहता है। आप गांवों पर 70 परसैंट पैसा खर्च करें लेकिन 30 परसैंअ भाहरों पर भी तो करना चाहिए। अगर आप सही सही पैसा इयर मार्क करे तो किसी को किसी प्रकार का उल्हानाही न हरे। चेयरमैन साहब, इन्होंने एक डिमांड नं0 13 रखी हैं एक स्टेट ग्रिवैन्सिज कमेटी बनाई हुई है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी का क्या काम है, यह मिनिस्टर्स ने लोगो के ग्रिवैन्सिज सुनने बंद कर दिये है, इसलिये यह कमेटी बनायी है या किसी और कारण से बनाई है। जब आप टूल पर जाते हो तो टूर प्रोग्राम मे लिखा

जाता है कि आप लोगोक के ग्रिवेसिीज सुनने के लिये जा रहे है अब पता नही यह कमेटी किस लिये बनाई है ? टूर प्रोग्राम ग्रिवेसिज सुनने के लिये होता हे। हमो पास तो इन लोगो का टूर प्रोग्राम भी नही आता है। सरदार लछमन सिंह का पहुंच जाता है लेकिन भाम ोर सिंह जी और सरदार हरपाल सिंह जी का तो पहुंचता ही नही। गलती से कभी कभी फूल चंद जी का भी पहूंच जाता है। चेयरमैन साहब, मे यह प्रार्थना कर रहा था कि उस टूर प्रोग्राम मे लिखा होता है कि फलां जहह पर जायेंगे और लोगो के ग्रिवेंसिज सुनेंगे। जब आप ग्रिवेस्ज्ि सेनुते है तो ये नयी नपयी कमेटीया बनाने की क्या आव यकता है? क्याये कमेटिया इसलिये बनाई जाती है कि जे लाग पालिटिकनी डिस ग्रेन्ल्ड है, उनको एडजस्ट किया जा सके?

इनकी मजबूरी हम समझते है। आप उनको कुछ चीजें देना चाहते है, बख्भाी ा देना चाहते है तो कुछ और दीजिये। चीफ मिनिस्टर साहब, यहां पर बैठे नही है। उनकी गैर मौजूदगी मे कुछ कहता मै अच्छानही लगता। बड़ी खु ाी होगी, अगर इनकीो प्रोमेा ान हो जाये जैसे कि पिछले दिनो खबर आयी ाि कि इनको भाायद सवैंअर मे लिश्या जा रहा है। हमे इसमे कोइ अरमान नही हैं यही पर रो तो भी ठीक है ागवान इनकी जो थोड़ी बहुत तकलीफ है, उनसको दूर कर दे और यह ठीक हो जाये ताकि अइच्दी तरह से काम कर सके। मैं यह कहना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, कि इस ग्रीवैंसिज कमेटी का कोइ तमलब ही

नही है यह फिजूल है, आलपैसरी है ओर यह एक्सबैकर के ऊपर बोझ है यह हरियाणा के किसान, मजदूर छोटे व्यापारी और मेहनतक ा आदमी के गाढ़े पसीने के पैसा का मिसयूज करने वाले बात है। चेयमैन साहब, इसमे ओल्ड ऐज पैं ान के लिये भी पैसा रखा गयाहै। यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। बहिन जी बैठी नही है ंयह बात तो उनकी तारीफ के काबिल है। ये स्वयं हरिजन ओरगरीब परिवार से संबंधरखती है। इसलिये वे गरीब आदमयितें के दुख को जानती हैं इसके अलावा उन्होंन अपने डिमापटमैंअ के रासट रीललफ के लिय`एक लाखरूपयामांगा है मैं जानता हूं कि कहीं पर रायटस हो यगे जहां रीलीफ देने के लिये रूपयामांगा कयगा है क्या हरियाणा मे कहीं पर रायटस हो गये या दंगें हो गये या यह पैक्सा पंजाब मे भेना है क्योंकि पंजाब मे कांग्रेस गवर्नमैंट फेल हो रही है। ला एण्ड आर्डर को मेनटेल करने के लिय `पंजाब परमैंट नाकामयाब है वहां पर रोज बेचारे निरंकारी लोगा को गोलियों से मारा जाता है ओर उनको मारकर वे उग्रवादी याएक्सट्रीमेस्टस नानकर निसास के आंदर के अंदर घुस जाते है। क्या आपसे वहां पर यह रूपया भेजना हैं यह किसव परपज के लिये मांगा जा रहा हैं इसके बारे मे आप पेज 60 पर देखे, उसमे यह लिखा हुआ है—

"Relief to persons affected by riots Rs 50000 (Non-recurring) That scheme provides, for relief to persons affected by riots for which a sum of Rs. 1 lakh was provided in Budget Estimantes 1982-83. Government decided to donate cash as

well as supply banketes to the Palestinian refugees who were victims of Israeli aggreassion....."

चेयरमैन साहब, आप देखिए, हरियाणा सरकार को दर्द जागता है इसरायल के एग्रै ान के खिलाफ फिलोसीलो रिफयुजियों के लिये। उसके लिये ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे है। चेयरमैन साहब, यह इंटरफै ाल मांमला है। इस मे क्यां ये अपने आपको इंवाल्व कर हरहे है पहले यह हरियाणा का ही दुख तो दूर कर ले। हरियाणा के गरीबों कादुख दूर कर ले। अगर भेजना ही है तो रूपयाआसाम के उन उजड़े हुए लोगों के लिये भेजों जिनकी कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार ने अपनी बी0एस0एफ0 से ओर सी0आर0पी0एफ0 से मरवा दिया। वहां पर जो साढ़े चार हजार आदमियों को मार कर फेक इलैक ांज करवायें है, उकनो फैमलीज को बसाने के लिये भेजों अगर आप आसाम के उजड़े आम लोगों के लिये यह पैसा भेजते तो हम मानते लेकिन आप तो भेज रहे हो फिलीर्स्त नयिो को। ये ऐसवे एसे काम कर रहे है। चौधरी कटार सिंह जी जैस एंव्रेजिंग मिनिस्टर जब यहां पर बैठे हुए है तो इनकी कटार इधर चलनी चाहिए। लेकिन उनकी कटार इधर तो चलती नही इसी तरह से अब मैं डिमांड नं0 16 पर कुछड कहूंगा। सरदार लछमन सिंह जी ने सैंट्रल सबसिडी, बैकवर्ड एरियाज के लिये 10 प्रति ात से बढ़ा कर 15 प्रति ान करने की वजह से कुछरूस्पया मांगा है और उनका कहना यह है कि यह रूपया गवर्नमैंट आफ इडिया देगी। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमैंट आफ इंडिया को , जो उसने

किसी एरिया को बैकवर्ड एरियाडिकलेयर करने का क्राईटेरिया बना रखा है, उसको रिवाईज करने के लिये खिालासं। धर्म जी साहब, कुछ कागज पस्ढ़ रहे है। इस सज्ज्न पुरूश मे गांधी जी की आवाज है, वे भाक्ल सूरत से भी गांधीवादी लगते है। उन्होंने गरीबों की बात रखनी चाही थी लेकिन इन्होंने मासूम कली को रौंद कर रख किदया। चेयरमैंन साहब, लछमन सिंह जी मैं क्या कहूं। हमे ंपरवानु बुलाकरखुद इधरचले गये । इन्होंने यह कहा है कि "Grant of 20 % subsidy for the purchase of generating sets.." चेयरमैंन सहाब, यह बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा का बिजली बोर्ड मोस्ट अन सर्टन है, बिजली की सप्लाई के बारे मे इन्के एक ांज मोंस्ट अन सर्टन है। कि कब बिजली चली जायेगी और कब आ जायेगीं किसी को कुछ पता नही है। आपने देखा है कि जब असैम्बलीर का सैक ान नजदीक आयेगा त्यों त्यों, सारे अफसर भागेंगे ताकि चौधरी भाम ेर सिंह जी को सदन मे यह कहने का कोई कठिनाई न हो कि हब बिजली मे कोइ्र कटौती नही है। अब पूरी बिजली दी जा रही है। जब हम घर जायेंगे तो फिर बिजली गायब हो जायेगी। पता इनको भी है कि 6 महीने तक फिर कोई बोलने वाला नही है। यह जो इंडस्ट्रीज वालों को जनरेटिंग सैंटस के लिये सबसिडी दी जा रही है यह बहुत अच्दी बात हैं मेरा कहना यह है कि यह ठीक लोगो को जैनुयन लोगों को मिलनी चाहिए। चेयरमैन साहब, साहब मैं एक और बात के बारे मे कहना चाहता हूं। स्पोर्टस कार्पोरे ान बनाने के लिये भी यहां पर बिल लाया जायेगा। फूल चंद जी बैठे नही है।

उनको यहां पर होना चाहिए था। स्पोर्टस एक कंट्रोवर्शियल इश्यु है। गवर्नमैंट को चाहिए कि जो उसने किया है, वह न करती । उन्होंने मैंबर्ज को, मिनिस्टर जो क्वीनर थे और कैंबिनट को बुला कर यह कह दिया कि यह फैसला कर दो। उसमे केई बाते ऐसी कंवीनय थे और कैबिनट को बुला कर यह कह दिया कि यह फैसला कर दो। उसमे कई बाते ऐसी रिवील हुई है, जिनसे स्मैंल आती है कि उसमे कहीं पर कोई न कोई गड़बड है। चेयरमैन साहब, मैं तो कटार सिंह जी को बड़ा ही इन्नौसैंट समझत था लेकिनउनके तो काम देखने मे आए है उनसे तो यह उल्ट भी निकले। मैं तो यह समझता था चुंकि ये हमारे पुराने वित्त मंत्री बाबू मूल चंद जी को हर कर आये है जो कि दो बार वित्त मंत्री रह चुके है, इसलिये भाायद इनको यह भार सौंपा गया है। लेकिन इसमे तो बात ही कोई और है। इतना ही कहकर अंत मे मैं एप्रोप्रिए ान बिल नं0 1 और 2 दोनो का ही विरोध करता हूं।

श्री किताब सिंह (गोहाना): चेयरमैन साहब, आज एप्रोप्रिए ान बिलों पर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि जो रूपया कृशि के लिये इसमे रखा गया है यह बहुत ही थोड़ा है। अभी पिछले वर्श कुंछ जगहों पर ओले पड़े थे। मेरी समझ मे एक बात नही आती । एक तरफ तो सरकार के यह आंकड़े है कि 6 लाख 85 हजार एकड़ रकबे मे 170 करोड़ रूपये की फसल कानुक्सान हुआ लेकिन उसका जो मुआवजा हदया गया हैं वे केवल 14 करोड़ 49 लाख रूपये दिया गया है। अगर इस हिसाब

से हम एवरेज लगाये तो यह केवल 200 रूपये प्रति एकड़ निकलती है। दूसरी तरफ 170 करोड़ रूपये का जो 6 लाख 85 हजारएकड़ रकबे का नुक्सान हुआ है, अगर उसकी एवरेज निकाली जाये तो 2480 या 2482 रूपये के करीब पड़ती है। इतना ज्यादा किसानका नुक्सान हुआ है और गेहूं की फसल का तो सैंटपरसैंट नक्सान हुआ है। लेकिन सरकार ने दिया है 25 से 50प्रति ान नुक्सान हुआ है। लेकिन सरकार ने दिया है 25 से 50 प्रति ात नुकसान वाले इलाके मे 200 रूपया, 50 से 75 नप्रति ात वाले इलाके मे 300 रूपये और 75 से 100 प्रति ात नुकसान वाले इलाके मे 400 रूपये प्रति एकड़ इनके आपने आंकड़ों के मुताबिक किसानों का 2480 रूपये प्रति एकड़ की एवरेज के हिसाब से नुक्सान हुआ है। इसके मुबाकले मे उनको बहुत कम दिया गयाहै और जो दिया गया है उसमे भी गलत तरीके से और हेरा फेरी करके दिया गयाहैं एक बात मैं और कहना चाहूंता हूं कि कृशि के लिये जो पैसा रखा गयाहै, वह पले ही कम है हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है। कृशि की बात तो यहां पर सारे भाई कहते है लेकिन मैं कृशि के उत्पादन की कीमतों के मुकाबले मे दूसरी चीजों की कीमते कितनी बढ़ी है, यह बताना चाहता हूं सन् 1970 मे मिटटी के तेल की कीमत 67 पैसे प्रति लीटर भी ओर 1975 मे मिटटी के तेल का भाव 1.39 रूपये हो गया । इस प्रकार से 107. 5 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई है। 1970 मे गेहूं का भाव 76 क्विंटल था और चावल का भाव 89 रूपये क्विंटल था 1975 मे गेहूं का भाव 105 रूपये क्विंटल था औरचावल का भाव 117 रूपये क्विंटल

था। इस प्रकार से चेयरमैन साहब, गेहूं के भाव मे 38.16 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई औरचावल के मूल्य मे 31.46 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई। इससे पता लगता हे कि कृशि उत्पादन के मुकाबले मे दूसरी चीजों कीकीमत ज्यादा बढ़ी है। (ाोर एंव व्यवधान)। मै कह रहा थाकि जिस प्रकार कृशि के काम आने वाली चीजें, उनके रेट ज्यादा बढ़े कृशि उत्पादन की वस्तुओं कारेट दूसरी चीजों के मुकाबले बहुत कम बढ़ा। चेयरमैन साहब, ये सरकार आंकड़े है, चेयरमैन साहब, कल कृशि मंत्री जीने कहा थाकि 1978–79 मे रिकार्ड तोड़ फसल हुई थी। यह बात ठीक है कि वह वर्श फसल के लिये बहुत अच्छा वर्श था परंतु कृशि मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने पंजाब के गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिये है। 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978 मे आंकड़े किसान को जो प्रति हैक्टेयर बचत हुई है उसके आंकड़े दिये है वे इस प्रकार है– 1974 मे 762.51 रूपये प्रति हैक्टेयर, 1975 मे 465.18 रूपये, 1976 मे 128.26 रूपये, 1977 मे 82.09 रूपये और 1978 मे 32.33 रूपये पर हैक्टेयर बचत हुई है। इन सब चीजों को देखकर पता लगता है कि दूसरी चीजों की कीमत बढ़ती रही और कृशि से जो उत्पादन हुआ उसकी कीमत उतनी नही बढ़ी और इसलिये किसान की पर हैक्टेयर बचत कम होती चली इुई । चेयरमैन साहब, एि ाया मे जितने मुल्क है, उनके मुकाबले हिनदुस्तान के किसान को सब से ज्यादामहंगा ाादअपनेखेत मे डालना पड़ता है और कुशि मे जितनी चीजें काम आती है उनकी सब से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। चेयरमैन साहब, भारत मे किसन को जो डीजन स्नेहक, उपकरण और

उर्वरक आदि इस्तेमाल करने पड़ते है, उनके बारे मे भी मैं आकंडे देना चाहता हूं। 1970–71 मे डीजल का सुचकांक 131.1 था और जुलाई 1975 मे 324.2 रूपये था, 167.7 प्रतिम ात की बढ़ोतरी हुई स्नेहक का सूचकांक 1970–71 मे 171.9 था जो जुलाई, 1975 मे 448.9 हो गाया और इसमे 216.3 प्रति ात की बढ़ोतरी हुई। उपकरण और औजार का सूचकांक 1970–71 मे 161.6 था जो जुलाई, 1975 ` 311.3 रूपये हो गया और इसमे 92.4 प्रति ात की बढ़ौतरी हो गई। उर्वरक का सुचंकाक 1970 मे 135.6 रूपये था और 1975 मे 292 रूपये हो गया ओर इसमे 115.3 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई। जहां तक किसान की पैदावार के भाव का ताल्लुक है गेहूं का भाव 1970–71 मे 76 रूपये क्विंटल था जो 1975 मे 105 रूपये हो गया ओरइसमे 38.16 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई। चावल का रेट 1970 मे 89 रूपये था और 1975 मे 117 रूपये हो गया और इसमे 31.46 प्रति ात की बढ़ौतरी हुई। चेयरमैन साहब, अगर जापान को देखे तो वहां पर एक किलों भाुद्ध नाईट्रोजन की कीमत कम है और एक किलों जीरी की कीमत ज्यादा है लेकिन भारत मे इसके उलट है। इसी तरह से कोरिया, बंगला दे ा और दूसरे दे ाो की हालत है। चेयरमैन साहब, भारत के किसान को दूसरे दे ाो के मुकाबले मे खर्च ज्यादा करना पड़ता है और उसकी आमदनी कम होती है। यह सरकार अपने आपको किसानों की सरकारकहती है लेकिन किसानों के साथ सही किस्म काव्यवहार नही करती। चेयरमैन साहब, यहां पर किसान को नकली खाद सप्लाई किया जाता है। मेरासुझाव है कि जो भी

आदमी नकली खाद बेचता पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए खाद को बेचने का काम प्राईवेट सैक्टर मेनही दिया जाना चाहिएबल्कि सरकारी एजैंसी द्वाराबेचा जाना चाहिए।अब मैं थोड़ा सा सिंचाई के बारे मे कहना चाहताहूं। चेयरमैन साहब, किसानको नवम्बर, 1981 से मई 1982 तक पानी की कोंं आव यकता नही पड़ी लेकिन जून, जुलाई ओरअगस्त मे उसकोपानी की आव यकता पड़ी। उसवक्त बिजली परकट लगा दिया गया और उस वक्त जो जीरी पकने वाली थी बिजली की कट लग जाने से वह सूख गई। चेयरमैन साहब, जहां तक पैदावार का ताल्लूक है चीन, जापान और कोरिया के मुकाबले हमारी पैदावार तीस प्रति ात पर हैक्टेयर आती है लेकिन जिस खेत को हम प्रदे ान के लिये तैयारकरते है उसकी पैदावार उनके बारबर आती है। इससे साबित होता है कि अगरपूरी सहायता किसान की की जाये तो उन दे ाों मे जितनी पैदावार होती है उतनी ही हमारी यहां को सकती है। चेयरमैन साहब, इस सरकार जितनी किसानो को सहायता न देने का कारण यह है कि सरकार प्रोसिान नही है सरकार कृशि की बात जरूरी कहती है। लेकिन जो सहायता किसान को देनी चाहिए वह सहायता नही देती है। चेयरमैन साहब, कृशि की मद मे जो पैसा रखा गया है वह बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं सरकार से मुआवजा देने के बारे मे एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार सरकार ओले से ुसल खराब होने कामुआवजा देती है उसी प्रकार सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि अगर किसान की फसल

बाढ़ से, आंधी से या किसी औरतरीके से खराब हो जाती है तो उसको भीमुआवजा दियाजायेगा। चेयरमैन साहब, मंत्री परिशद ओर एम0एल0एज0 पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। इसका ज्यादा खर्च नही किया जानाचाहिए। चेयरमैन साहब, 1971 मे भारत सरकार ने राज महाराजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त किया था लेकिन अब सरकार ने एम0एल0एज0 की पैं ान भुरू करके राज महाराजाओं जैसा प्रिवी पर्स फिर भुरू किया है। मेरा सुझाव है कि इस पैं ान को बंद किया जाये।

चौधरी मांगे राम (बहादुरगढ़): चेयरमैन साहब, यह सरकार जो विधेयक प्रस्तुत कर रही है, मैं उसके बारे मे कुछ कहना चाहता हूं कि यह पैसा खर्च हो रहा है। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के के अंदरगांव किरोड़ी, प्रहलाद,पाइ मे सड़ेा का काम भुरू हुआ था जिस परमिटटी रोड़ पड़ी है। लेकिनवह काम एक साल से बंद पड़ा है। जब हम अफसरान से सड़क के बारे मे मिलते है तो वे कहते हे कि पैसा नही है। सारा पैसा आदमपुरहल्के मे लगायाजा रहा है। चेयमैन साहब, क्यांकि मैं विरोधी दल का सदस्य हूं, इसलिये मेरेहल्के के साथ सौतेला व्यवहारहो रहा है। चेयरमैन साहब, इसी तरह सवे मे हल्के मे कोईवाटर वर्क्स पानी नही दे रहा है। ग्राम मुकंदपुर, वाई ब्राही, दिसावरखेड़ी, माडौठी जाखोदा, ई ारहैड़ी, बरोझा, निहलौठी, हुलारहेड़ी, डाबोदा ओरलोवामाजराके वाटरवर्क्स अधूरे पड़े हैक्ळ यसह पैसा भी आदमपुर या नारायणगढ़ मे लग रहा है। विरोधी दल का मैंबर होने के कारण मेरे हल्के

मेपैसानही लगया जा रहा है। चेयरमैन साहब, वाटर वर्क्स परसीमेंट ओरलोहासरे आम बिकता है लेकिनसरकारइसकी तरफ कोई ध्यान नही देती। चेयरमैन साहब, इस प्रांत मे भ्रश्टाचार इतना है कि बगैर पैसे कोई काम नही होता। किसी भी दफतर मे चले जाओ बगैर पैसे कोई काम नही होता। चेयरमैन साहब, इस तरह हमारी तहसील के अंदर रजिस्ट्री क्लर्क ने सरे आम लूट मचा रखी हैं असने एक साल के अंदर दो काठी और एक कार बना ली है। इस कर्ल्क ने बहुत भारी रकम बना ली है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से हसनगढ़ कालेज मे ओ0टी0 के दाखले मे भारी रकम ली गई और इसी वक्त प्रिंसीपल ने सरकार को टेलिग्राम के माध्यम से सूचना दी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसी कालेज मे कई प्रौफेसरों को नौकरी से भी हटाया गया है मैनेजमैंट इस कालेज को बंद करना चाहती है। सरकार इस तरह अव य ध्यान दे। इसके आगे चेयरमैन साहब, एकआत बात एम0आई0टी0सी0 के बारे मे बताना चाहत हूं जो पक्के खाल बने हुए है, वे एक हफते के अंदर टूट जाते है क्योंकि उन खालों को बनाने के वक्त उन परसीमेंट कम लगाया गया है। सीमेंट को बेच दिया जाता है, सरकार इनको कब करवाये। किसान बहुत दुखी है। क्योकि उन खालों मे पानी नही चलता।

इसी तरह से चेयरमैन साहब, मैं नम्बरदारों के बारे मे आपको बताना चाहता हूं। नम्बरदारों को 1947 मे पहले भी सौ रूपये पर तीन रूपये मिलते थे आज भी वही हालत है। उन्हे

आज भी सौ रूपये परतीन रूपये ही मिलते है जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आज मजदूरी की दर बढ़ कर 15 रूपये हो गयी है और नम्बरदार बेचाराउन्ही तीन रूपयो पर ही गुजाराक रता हैं। इस तरह की अंधेर गर्दी यहां पर वमी हुई है सरकार को इस तरहफ पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इस भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। एक बार अंत मे फिर मैं सरकार से यह कहूंगा कि जो जो बाते ंमैंने यहां पर कही हे, उनपर विचार किया जाये और तुरंत एक ान लिया जाये।

श्री जसवंत सिंह चौहान (राई): चेयरमैन साहब, 1983–84 के बजट के संबंध मे जो एप्रोप्रिऐ ान बिल यहां डिस्कस हो रहा है उस पर मै ंअपनी विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं हमारे इस बजट मे जो कर लगये गये है। उससे सरकार को कुी आमदन होगी ओर उससे गरीब आदमी पवर कोई बोझा नही पड़ें इसके साथ साथ मैं सरकार से यह कहूंगा कि बे ाक ऐसे कुछ कर ओर लगा दिये जाये। जिससे कि गरीब अदमियों पर कोई बाझा न पड़े । इस बारे मे मैं कुछेक सुझाव सदन के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। आ ाा है कि आदणीय सदस्यगण मेरे इन सुझावों के साथ सहमत होंगे और इस पर पुरजोर ताईद भी करेंगे। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि ज्यादा खर्च न करा सकने की वजह से कई भाादियां नही हो पाती उस वजह से कोई लड़के और लड़कियां

खुदक ाी कर लेते है। बहिन बंसंती देवी जी ने भी इस बात परकाफी जोर दिया हेक तेरा एक सुणव है कि इस पर भी कोई एसेा कर या बैलडीटी सरकार की तरफ से लगायी जाये या कोइ्ऐसाी लिमिट फिकस की जाये ताकि हर आदमी सरकार द्वारा फिकस की हुई लिमिट के अुदर ही ब्याह भाादियों का आयोजन करे। इससे हर आदमी को खु ाी होगी, राहत मिलेगी ओर इस तरह के खुदर्ि ायों के केसिज भी नही होंगे जोकि आजकल आम हो रहे है। भागर कोई आदमी डैकोरे ान पर यादेहत वगैरा पर कुकर्रर की हुई रा ि ा से ज्यादा खर्चा करेगा तो उस पर कर लगाया जाये। इससे सामाजिक कुरीतियों से आम आदमी को छुटकारा मिलेगा और लोगों का जीवन भी सुखमय और खु ाहाल हो सकेगा।

दूसरी सुझाव मेरा यह है कि जैसाकि भाई निहाल सिंह जी ने हैल्थ मिनिस्टर जी को कहा कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये ताकि लोंगों की सेहत ठीक रह सके। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य, राव इंद्रजीत सिंह पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, मैं भी इसहक मे हूं कि इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा के अंदर बनायी जाये जिससे लोगों की सेहत बरकरार रखी जा सके। इसके साथ साथ हरियाणाकी जनता पर ऐसा कोई टैक्स लगया जाये जिससे प ाु पालन को बढ़ावा मिले। यानी जिस घर मे प ाु न हो, उस पर टैक्स लगाया जाये।

Shri Ram Bilas Sharma: On a point of order, sir, the hon. Member is speaking on the Budget. This is not the budget speech which is under discussion. I may tellhim through you, sir, that the discussion is going on on Appropriateion Bills. He should speak on the Appropriation Bills, Sir.

Mr. Chairman: This is no point of order. Please take your seat.

श्री जसवंत सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, हमारे हरियाणा की एक कहावत म ाहूर है कि 'हरियाणा दुख दही का खाना'। इस बारे मे हम आज क्या देख रहे है कि हरियाणा के अंदर यह बात केवल नाम मात्र की ही रह गयी है। अब तो सुनने की ही बात है। इस बारे मे मैं यह भी महूंगा कि प ाुओं को बाहर जाने से रोक कर, उन से आमदनी का साधन जाये ताकि हरियाणा सरकार की आमदनी बढ़े।

इससे आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कि हरियाणा के नौजवान ही ज्यादातर पुलिस और मिलट्री मे भर्ती के लिये जाते है । इससे भारत वर्श सारे हरियाणा का नाम रो ान होता है, इसलिये इस सरकार से मेरी रिक्वैस्ट है कि हरियाणा चाहिये। जब तक सरकार प ाुपालन पर कोई ध्यान नही देगी तब तक यह काम पूरा नही हो सकेगा। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी साहब सिंह सैनी पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, अब मैं अपने हल्के के बारे मे कुछेक बाते कहना चाहूंगा। मेरे हल्के, की कुछेक समस्याए हे, वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। हमारा हल्का राई फलडिड एरिया है। हालांकि सरकार की पालिसी है कि हर गांव मे सड़कें दी जायेंगी लेकिन मेरे हल्के मे कुछेक गांव अभी तक भी ऐसे है जहां पर सड़कें नही पहुंची है। कारण क्या है कि वहां पर एक हाई स्कूल है, वहां जाने के लिये बच्चों को काफी दिक्कत होती है। हालांकि वह स्कूल केवल एक किलोमीटर पर ही है लेकिन पुल न होने के कारण बच्चों को चक्कर काट कर वहां कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। इसलिये में सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि ऐसे गांवों मे जल्द से जल्द पुल और सड़कें बनायी ताकि लोगों को और खासकर बच्चों को स्कूल तक जाने के लिये कोई परे ाानी न हो।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि यमुना की बाढ़ से भी हमारे इलाके मे नुकसान होता है। दिल्ली से लेकर मूरथल गांव तक एक कच्चा बांध बना हुआ है। बरसात के पानी से उसमे ि ागार हो जाते है। जिसके कारण बहुत से गांव तथा फसलें बर्बाद हो जाती है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली वालों ने स्कीम बनाकर हरियाणा के बार्डर तक यमुना के बांध को पक्का किया हुआ है, उसी तरह से आपको भी यह चाहिये कि इस बांध को दिल्ली के बार्डर से लेकर मूरथल तक पक्का किया जाये। उसके साथ एक सड़क भी बनाई जाये।

जैसा कि दिल्ली की तरफ अब बांध के टूटने का कोइ खतरा नही रहा, उसी तरह से इस और भी ऐसा कोई इंतजाम किया जाये ताकि किसानों को परे ाानी न हो और एक प्रकार से राहत भी मिले और वे आगे से लाखों रूपये के नुकसान से बचे।

इससे आगे मैं यह कहूंगा कि ड्रेन नम्बर 8 जो है, उससे भी लोगों को काफी नुक्सान होता है। जब बरसात का मौसम आता है उसमे पानी काबहाब काफी हो जाता है और बाढ़ भी आ जाती है जिससे गांवों के अंदर तक पानी भर जाता है और फसलों को काफी नुकसान होता है। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि ड्रेन नम्बर 8 को यमुना तक पुखता किया जाये।

अगली बात मेरी अपने हल्के के स्कूलों से संबंधित है। हमारे वहां पर बहुत ऐसे गांव है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से स्कूलों की बिल्डिंगें तैयार की हुई है। जैसे जाखोली गांव है, वहां पर लड़कियां के स्कूल के लिये एक बिल्डिंग बनी हुई है। इसी तरह से नांगल गांव है, उसमे भी स्कूल की बिल्डिंग तैसार है। इसी तरह से राई मे, बहोली गांव मे और कमासपुर मे भी बिल्डिंग तैयार पड़ी हुई है।

मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उन गांवों मे कम से कम बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल को अपग्रेड किया जाये ताकि उनको अपनी मेहनत का फल मिल सके। अगली बात यह है कि मेरे हल्के राई मे फरीदाबाद की तरह से इंडस्ट्रीज बगैरह बनी

हुई है। वहां पर जो किसानों की उपजाउ जमीन थी उसको लेकर वहां पर बहुत फैक्ट्रीज लगा दी हैं वहां का जो किसान है या देहात मे रहने वाला कोई भी आदमी है जिनका गुजारा खेती पर ही निर्भर करता है, वे बाहर के आदमियों को नौकरी पर न रखे और हमारे गांवों के आदमियों को ही रखे। आजकल यह हो रहा है कि वे उन इडस्ट्रीज मे बाहर के प्रदे ाों के वर्कर और कारीगरों को रखा जा रहा है और हमारे हल्के के एक आदमी को भी भरती नही किया जा रहा है। मेरे हल्के राई मे एक प्रोब्लम और है। मेरा हल्का दिल्ली के नजदीक पड़ता है। वहां से हजारों आदमी सर्विस करने वाले रोज दिल्ली जाते है और बहुत से आदमी सब्जी बेचने के लिये दिल्ली जाते है। इनको दिल्ली जाने के लिये बहुत से आदमी होती है क्योंकि लम्बे रूट की बसें वहां पर नही रूकती है। दिल्ली को जाने वाली बसें हमारी देहातों मे होकर बहुत कम चलती है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो हमारे बड़े बड़े गांव है जैसे मूरथल, राधना बगैरह कम से कम दिल्ली जाने वाली बसें इध्यान से जानी चाहिए ताकि सर्विस करने वाले और सब्जी ले जाने वाले लोगो को सहूलियत हो सके। धन्यवाद।

श्री हरि चंद हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, आप का बहुत बहुत भाुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया। यह जो एप्रोप्रिए ान बिल आया है जब मैं इसके टोटल को देखता हूं तो वह 819199316 बनता है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर,

विलेज एंड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और माईनर इरीगे ान के लिये रा‍ि ा को देखा जाये तो वह इसके 9 प्रति ात के करीब बनती है। मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नर एड्रैस को भी और इस एप्रोप्रिए ान बिल को भी आम जनता समझ नही पाई, लेकिन आम जनता को इसकी मार जरूर पड़ी है। जिससे वह तिलमिला उठी है। आम जनता इस चीज को समझे कि यह एक कागज है जिससे तुम्हारी किस्मत का सत्याना ा किया जाता है। उधन जो हमारे भाई बैठे है चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल, फाईनैंस मिनिस्टर चौधरी कटार सिंह जी तो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त है। मैं इनको बिल्कुल दोशी नही ठहराता। असली दोश तो डिफैक्टिव ला का है। मैं आप का ध्यान कांस्टीच्यू ान की धारा 372 की तरफ दिलाना चाहता हूं which hsa perpetuated the imprial legal inheritage and our codes and laws of the colonial ventage haunt it like voice from the grave. असली जो बात है वह यह है कि हम इनको दोशी इसलिये नही ठहराते क्योंकि हमारी व्यवस्था और ला इस किस्म के बना दिये जैसे अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज कर गये और कालोनी राज बना गये थे। मुझे अफसोस है कि हमारा जो कांस्टीच्यूए ान है इसकी कुछ धाराएं इंगलैंड से ली गई है। इन दोनो के बीच मे एक ऐसी लाईन आई कि न घोड़ी रही न गधी रही । इस डिफैक्ट की वजह से हम दुखी हो रहे है।
* * * ** * * * * * * ** * * * * * * यह जो बजट आया है इस बारे मे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं...........

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने अभी जो बात कही है यह कार्यवाही से एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री सभापतिः ये भाब्द एक्सपंज कर दिये जाये।

श्री हरि चंद हुड्डाः चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता था कि–

पंछी समझते है कि चमन बदला, हंसते है सितारे कि गगन बदला,

भाम ाान की खामो ाी मगर कहती है कि है ला ा वही सिर्फ कफन बदला।

तो यह तो इनका बजट था। जहां तक मांगो की बात है मांगों को ये तो समझते नही, मैं समझता हूं। यह मांग वह मांग नही , इस मांग मे लोकतंत्र की खु ाबू नही, यह मांग तो वह मांग है जिसमे नोट तंत्र की बू आती है। (ाोर) अब हमारे सामने यह चीज आ गई है। आज 56 प्रति ात लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह गये है। and it is because of the polioies of you and your leaders. जिसको आप लीडर मानते हो, महात्मा कहते हो for them I can say on the floor of the House that they are all responsible for the pverty in the country.

चेयरमैन साहब, कृशि के लिये सिर्फ 6–7 करोड़ रूपया दिया गया है जबकि डिमांडज मे 82 करोड़ रूपया से ज्यादा पैसा

है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट हुआ, डिमांडज हुई और गवर्नर साहब का एड्रैस हुआ ये कागजात हल के साथ नही जुड़ सकते और न ही इनसे किसान अपने खेत मे कोई खूड निकाल सकते है। हल मे तो बैल और किसान जुड़ेंगे । इस बजट के कागजों से किसान का हल चलने वाल नही है, किसान का तो बेल ही चला सकता है। इस मुल्क के मसले किसानों ने हल चला कर ठीक करने है। बैल और किसान दोनों मजबूत होंगे तो प्रोडक ान लाजमी तौर पर होगी। लेकिन ये जो बजट और डिमांडज के कागजात हमारे सामने आए है इनसे हमारे हरियाणा की जनता मर रही है। इन कागजों द्वारा जनताको जो तकलीफ दी गई है, उस तकलीफ को तो जनता महसूस कर गई लेकिन यह ड्रामा जनता नही समझती है। चेयरमैन साहब, हमारा दे ा 1300 साल गुलाम रहने के बाद आजाद हुआ। जब हमारा दे ा 35 साल पहले आजाद हुआ तो उस समय से यह भुखमरी का ि ाकार है। अगर यही हालात दे ा मे रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे चार हजार साल तक यह दे ा आजाद रहे तो फिर भी इसदे ा की भूखमरी खत्म नही हो सकती। चेयरमैन साहब, यह सरकार हमारे दे ा को भुखमरी की जिम्मेदार है। हमारे दे ा मे 56 फीसदी लोग गरीबाी की लाइन से नीये है। हमारे दे ा मे करीब लोग बहुत परे ाान है और उस परे ाानी का नतीजा यह हुआ है कि आसाम मे रिवेरिलयन है। वहां पर लगभग 5–6 हजार मारे गयें चेयरमेन साहब, 1965 के पाकिस्तान के आप्रे ान मे कुछ साढ़े चार हजार नौजवान मारे गये

थे लेकिन आसाम मे 5–6 हजार आदमी मर चुके है। इसी तरह से पंजाब मे रिबेलियन है और क मीर मे ला को खुल्मखुला अफेड कर रहे है, वहां पर भी रिबेलियन है। साउथ मे पीसफुल रैवोल्यू ान आया हैं मेरे कहने का मतलब है कि हमारे दे ा मे दे ा के अंदर रिववेलियन और रैवोल्यू ान घुस चुके है। गुरबत की वजह से हमारे दे ा मे रिबेलियन और रैवौल्यू ान आ चुके है। What is this is happening in diffenrent parts fo the country? That is a ravage from you and your Government. चेयरमैन साहब, 35 साल तक इस दे ा के बडे बड़े लोग अपने अपने कर्म करके चले गये लेकिन वे इस दे ा की भुखमरी को समाप्त नही कर सके। चेयरमैन साहब, मै यही कहूंगा कि वह सोना किस काम का जो कानों को काटे, वह लीडर किस काम का जो कौमों को बांट दे, वह दुकानदार किस काम का जो सौदा घाट दे, वह सरकार का कानून क्या जो इंसाफ को काट दे। चेयरमैन साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि आपके ये बजट कागज डिमांडज और एप्रोप्रिए ान बिल जो आए है ये ला तो है लेकिन इंसाफ नही दे रहे है। इसलिये यह एक बहुत ही झूठा ड्रामा है। चेयरमैन साहब, मैंने देहात के गरीब किसानों को देखा है, छोटे दुकानदारों को देखा है और मजदूरों को देखा है, वे सब भूखमरी के ि ाकार है। हमारे दे ा मे पूंजीपति दो किस्म के है जो इस दे ा के सारे माल को हड़प रहे है। एक तो वे है जिनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई लगाम नही है, वे सारे दे ा का धन हथिया रहे है और गरीब लोगों का खून चूस रहे है। * * *

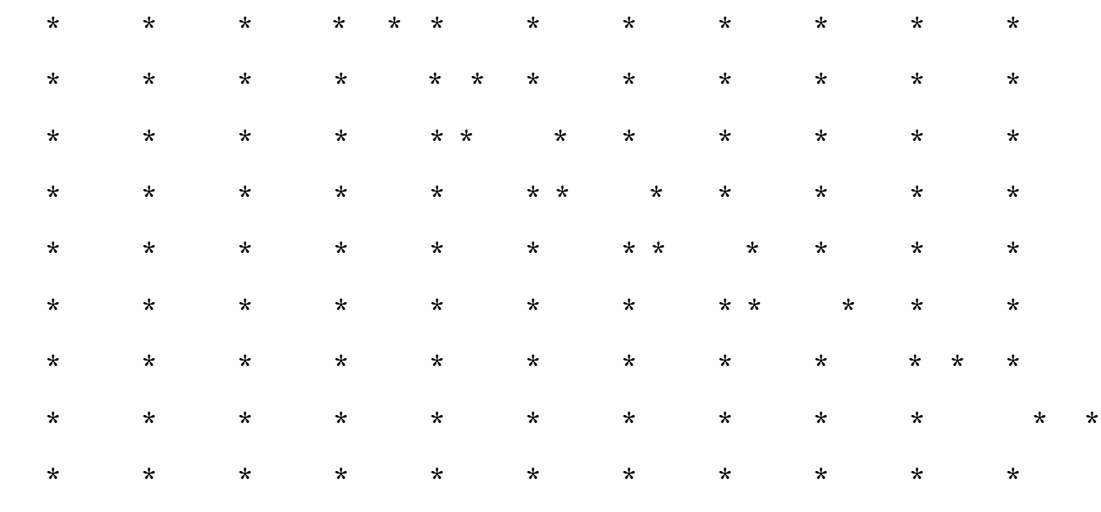

। इन भाब्दों के साथ मैं इस एप्रोप्रिए ान बिल का विरोध करता हूं। और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी ई वर सिंह (पुंडरी): चेयरमैन साहब, एप्रिप्रिए ान बिल नम्बर एक पर हाउस मे चर्चा चल रही है। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, यह एप्रोप्रिए ान बिल सप्लीमैंटरी डिमांडज के बाद रखा गया है। सप्लीमेंटरी डिमांडज मे 81 करोड़ 92 लाख रूपये मांगे गये है। चेयरमैन साहब, यह इस किस्म का खर्चा है जो पहले एनविसिज नही हो सका। जैसे सरकार ने अपने प्रांत मे डिवैल्पमैंट के कार्य किये या सैंटर की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आई जो कमजोर वर्ग के लोगों के लिये थी, उस पर खर्च किया गया पैसा है या सरकारी कर्मचारियो को जो ए0डी0ए0 की इनस्टालमैंट दी गई थी, और उसी हिसाब से कुरूक्षेत्र और एम0डी0 युनिवर्सिटीज के कर्मचारियों को ए0डी0ए0 की इनस्टालमैंट दी गई थी या उस मेले मे कुछ खर्चा हुआ था उसके

बारे मे भी सप्लीमैंटरी डिमांडज मे पैसा मांगा गया है। चेयरमैन साहब, मेरे अपोजी ान के भाईयों इस बिल पर बोलते हुए कुरूक्षेत्र मे मेले की बहुत आलोचना की । डाक्टर मंगल सैन ने कहा कि इन्टरने ानल ट्रेड फेयर पर बहुत भारी खच्र कर दिया गया । मैं आपके द्वारा डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि उस मेले मे जो स्टाल लगाई गई थी, वह सारे मेले मे फर्स्ट आई थी जिससे हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। इसी प्रकार डाक्टर साहब ने एि ायाड के बारे मे कुछ बातें कहीं एि ायाड के बारे मे डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि एि ायाड मे हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने कम्पीटी ान मे हिसा लेकर बहुत सराहनीय खेल दिखाए। आज गवर्नर साहब ने यहां लगीाग 232 खिलाड़ियों को ईनाम बांटे जायेंगे, जिन्होंने एि ायाड मे और दूसरे खेलों मे हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से ए0सी0 चौधरी साहब ने म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे मे बताया था कि जो कमजोर म्यूनिसिपल कमेटीज थी उनको ग्रांट दे कर सफाई का अभियान चलाया है उसके लिये भी सप्लीमैंअरी डिमांड के जरिये पैसा रेडज के खर्चे के बारे मे भी कुछ बातें कही थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक्साइज एंड टैक्से ान तो सयरकार की आमदनी का मेजर हिस्सा है। यदि उनके रेडज के लिये कुछ रूपया खर्च हो गया तो उससे डबल आमदनी होगी। पिदले साल एक्साइज एंड टैक्से ासन से 160 करोड़ रूपये की आमदनी सरकार को हुई है, वह सारापैसाा हमारे प्रदे ा के डिवैल्पमैंट के कार्यो पर खर्च किया गया

है। एक्साइज एंड टैक्से ान से सरकार को जितनी आमदनी होती है वह सार पैसा प्रदे ा के डिवैल्पमैंट के कार्यों पर खर्च होता है। चेयरमैन साहब, फिलीस्तीनी रिफयूतजीज के बारे मे भल कहा गया । मैं इस बारे मे यह कहना चाहताहूं कि वाकई फिलीस्तीनी रिफयूजीज कती स्थिति बहुत खराब है। जो उनको एक लाख रूपया दिया गया है, इससे कुछ नही होता यह तो उनके प्रति टोकन हमदर्दी है। जब चर्चिल साहब को यह कहा गया कि हिन्दुस्तान को आजादी दे दी जाये तो उन्होंने उस समय यह कहा "I have not become the Prime Minister of England to liquidate the British Empire." चेयरमैन साहब, लगभग 25–30 लाख आदमी फिलिस्तान से निकाले हुए है और वे लेबनान मे अपना डेरा डाले हुए है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अभी पिछले दिनों जब दिल्ली मे नान अलायन कंट्रीज की कांफ्रैंस हुई, उसमे 101 दे ाो ने भाग लिया था। उस कांफ्रैंस मे युनानीमसली हमदर्दी का यह रैजाल्यू ान पास किया गया कि उएनको वहा पर बसाया जाये। उस कांफ्रैंस मे युनासनीमसली यह आवाज उठाई गई कि चूंकि उन लोगों को उनके घरों से उजाड़ दिया गया है। इसलिये उनको बसाया जाये। चेयरमैन साहब, लेवनान मे जितनी आबादी है उतनी ही आबादी फिलिस्तीनियों की है। ये लोग कुछ सीरिया मे भी है। मैं पिछले दिनों बैरूत गया, मैंने वहां पर उनकी हालत देखी थी। उनका बहुत बुरा हाल है। चेयरमैन साहब, जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है हमें उनको सिम्पथी देनी चाहिए हम उनसे क्रूड आयल और पैट्रोल लेते है। यदि हम फिलिस्तीनी लोगों को हमदर्दी के

लिये एक लाख रूपयादेने तो जितनी भी मिउल ईसट कंट्रीज है, उनको भी हमारे साथ हमदर्दी होगी। उन कंट्रीज से हमें बड़ी भारी मात्रा मे तेल लेना पड़ता है जो एक लाख रूपया टोकन हैल्प के रूप मे दिया गया है। यह बहुत थोड़ा पेसा है और बहुत जायज मांग है। अभी हमारे दूसरे भाइयों ने भी इसके बारे मे काफी कुछ कहा है। इस बिल के जरिये जो पैसे मांगे जा रहे है, अगर गौर से देखे तो ज्यादातर पैसा कर्मचारियों को पांच ए0डी0ए0 की किस्तें देने पर खर्च हुआ हैं बाकी पैसा वाटर सप्लाई स्कीम के लिये म्यूनिसिप्ल कमेटियों द्वारा सफाई अभियान के लिये, तथा लोगो को दूसरी सुविधा प्रदान करने के लिये खर्च हुआ हैं हरिजनों के लिये ने ानल परमिट लेने के लिये 50 लाख रूपये रखे गये है। इसी प्रकार हरिजन टूरिस्टों के लिये भी 25 लाख रूपये रखे गये है ताकि वे भी घूम फिर सके। इसी प्रकार से हरिजनों को जमीन देने के लिये 40 लाख रूपये रखे गये है ताकि वे भी पैट्रोल पम्प आदि लगा सके। इसी प्रकार से हरिजनों को डेरी के लिये, सुअर पालने के लिये तथा मकान आदि बनाने के लिये पैसा सरकार दे रही है। जो हमारे बच्चे डैस्टीच्यूट हो गये है, उनके लिये भी सरकार पूरा पूरा ध्यान रखरही है। हमारी सरकार ओल्ड एज पै ान भी देने जा रही है तथासाथ ही साथ मे जो औरतें विडो हो गई है, उनकी तरफॅ भी ध्यान दे रही है। सरकार इंटैग्रेटिड चाइल्ड डिवैल्पमैंट स्कीम की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दे रही है और इसके लियें इस एप्रोप्रिए ान बिल मे पैसा रखा गया है। सरकार बूढ़ों ओरमजोर लोगो के लिये रिवाड़ी

के अंदर एक होम बना रही है। चेयरमैन साहब, जो रूपया सरकार मांग रही है, वह सारे का सारा जायज है और यह ठीक जगह पर ही खर्च होगा। जिन किसानों की फसल ओलावृश्टि से खराब हो गई थी, उनको भी सरकार ने सहायता दी है। सरकार किसानों को खाद की भी सुविधा दे रही है। महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार और रोहतक जिलों मे फसलो को कीड़ो आदि से बचाने के लिये दवाई भी प्रदान की है। यह डिमांड जो सरकारने रखी है, बिल्कुल जायज है ओरमैं इसका समर्थन करता हूं। जहां तक एप्रोप्रि ान बिल नं0 2 का सवाल है, यह बजट से संबंध रखता है । इसके बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अंदर चहूमुखी विकास हो रहा है। आज सरकार डिवैल्पमैंट के काम अधिक कर रही है। एग्रीकल्चर की तरफ भी सरकार का पूरा पूरा ध्यान हैं सरकार एग्रीकल्चरिस्टस को रा मैटिरियल भी ठीक ढंग से सप्लाई कर रही है। सरकार किसानों को सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये भी खूब कार्य कर रही है। इसी प्रकार बिजली की मात्रा को भी बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान हैं सरकार नई सड़के भी बना रही है। कुछ गरीब लोगों द्वारा इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये लोन देने का प्रोवीजन भी रखा गया हैं इस बिल मे जो पैसा मांगा गया है वह ठीक है और यह हरियाणा के सही विकास कार्यो पर ही खर्च होगा। आज हरियाणा मे चारों तरफ विकास हो रहा है। फिर भी मैं सरकार को कुछ सजै ांज दूंगा, जिन पर गहराई से विचार करना जरूरी है।

जहां तक एजूके ान का सवाल है उसके बारे मे मै। कहना चाहता हूं कि Education gives practical side of life. जो भी कुछ काम हमे उसे क्रियात्मक रूप देना चाहिए। खाली ि ाक्षा देने से कुछ बात नही बनती। आज हमारी ि ाख की पद्धति ठीक नही है। जिस कारण तो उससे काफी बोरोजगारी दूर हो सकती है। बच्चों ाक मौरल एजूके ान मिलनी चाहिए। जहां तक मौरल एजुके ान देने की बात है यह घर मे और दे ा मे जो कुछ हो रहा है। या प्रांत मे जो कुछ हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। बच्चों को जैसी ि ाक्षा दी जाती है, वैसा ही प्रभाव उन पर पड़ता है। सरकार का स्कूलों मे धार्मिक एजूके ान भी बच्चों को बराबर दी जाती है। इस संबंध में सरकार को मेरा सुझाव है कि बच्चों को धार्मिक ि ाक्षा भी बराबर दी जानी चाहिए। बच्चों को धार्मिक ि ाक्षा भी बराबर दी जानी चाहिए। बच्चों को स्कूलो के अंदर फिजिकल ि ाक्षा तो दी जाती है लेकिन योगा की तरफ ध्यान देने के लिये पूरे ग्राउंड भी नही है। जहां पर स्कूल बने हुए है। वे बहुत कम जगह मे बने हुए है। स्कूलों मे अधिक मैदान नही होते जहां पर बच्चे फिजिकल काम कर सके। सरकार को मेरा सुझाव है कि बच्चों को योगा की ि ाक्षा भी हर हालत मे दी जाये। हमारे यहां पर चीन के हयूनसांग और फाहियान आए थे। नालंदा युनिर्वसिटी मे काफी समय तक ठहरे थे। उस युनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अध्यपकों आदि को मिला कर कोई 17 हजार व्यक्ति रहते थे। उन्होंने लिखा है कि जितने समय तक हम उस युनिवर्सिटी मे ठहरे, उस समय मे सिर्फ एक

बावर्ची ही बीमार हुआ था । इसका कारण उन्होंने दिया है कि उस युनिवर्सिटी के अंदर प्रत्येक बच्चे को योगा अभ्यास प्रतिदिन करवाया जाता था । इसलिये सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से म्यूजिक के बारे मे भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को म्यूजिक की ि ाक्षा भी बराबर देना चाहिए। म्यूजिक इन्स्टरूमैंटस हमारे स्कूलों मे है लेकिन उन्हें इस्तेमाल नही किया जाता। इस संबंध मे मैंने पहले भी एक भोर सुनाया था कि–

मैहतरानी होके रानी गुण गुणायेगी जरूर,

कुछ भी हो जाये जवानो गुणगुणायेगी जरूर।

गाने की ि ाखा भी बच्चों को जरूर दी जानी चाहिए। आजकल की जो किताबें है वे ठीक नही है, उनमे जहर भरा पड़ा है। इसलिये इन किताबों को भी ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से मैं हौर्टिकल्चर के बारे मे कहना चाहता हूं कि इस तरफ सरकार खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध मे मेरा यह भी सुझाव है कि यदि मैंट्रिक तक का स्कूल है तो उसके पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यदि कोई स्कूल आठवीं क्लास तक का स्कूल है तो उसके पास 8 एकड़ जमीन होनी चाहिए और यदि कोई स्कूल पांचवी तक है तो उस के पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। हौटिकल्चर के संबंध मे मै। यह कहना चाहता था कि गार्डन आदि की ि ाक्षा बच्चों को एनीमल

हस्बैण्डरी के बारे मे और एग्रीकल्चर के बारे मे भी ि ाक्षा दी जानी चाहिए। 1983–84 के बजट के अंदर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 200 प्राईमरी स्कूल लड़कियों के खोल रहे है। यह फैसला सरकार का बहुत ही अच्छा है। सरकार ने इसके लिये भी एक करोड़ रूपये रखे है। इसी प्रकार से मैं ट्रांसपोर्ट के बारे मे कहना चाहूंगा। सरकार अब नए अड्डे भी बनाने जा रही है। बस स्टैण्डज के लिये जब जगह एक्वायर की जाती है तो वहां पर पक्की सड़के भी बनायी जाती है। मेरा सुझाव है कि पक्की सड़कें अनाने से पहले सरकार को जमीन एक्वायर करते वक्त छायादार वृक्ष लगादेने चाहिए जिससे लोगो को वहां पर खड़े होने मे सुविधा हो सके। आप उदाहरण के तौर पर पिपली के अड्डे को ले लीजिये।वहां पर अड्डे के अंदरबसें काफी खड़ी होती है लेकिन लोगों को बैठने के लिये न तो कोई भोड बने हुए है और न ही कोई छायादार पेड़ है। हमारे यहां बरोजगारी की भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध मे मै। सरकारको गुजारि ा करूंगा कि जो हमारी बसें है उनमे उस समय एक एक कंडक्टर है। यदि इन बसों मे एक एक कंडक्टर लगाने की बजाये दो दो कंडक्टर लग दिये जाये तो उससे भी बेरोजगारी काफी कम हो जायेगा। सरकार पर एक बस पर दो कंडक्टर लगाने से कोई ज्यादा बोझ नही आयेगा। यदिदो कंडक्टर होंगे तो एक अगली खिड़की से टिकट काटेगा और दूसरा पिछली खिड़की से टिकटें काटेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी बसों ने एि ायाड के दौरान बड़ा ही

सराहनीय काम किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने स्टेट एक्सचैकर मे 32 करोड़ रूपये जमा करवाये है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) स्पीकर साहब, सरकार ने इंटेग्रेटिड चाईल्ड डिवैल्पमैंट की स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जायेगा और उनका मैडीकल एग्जामिने ान समय समय पर किया जायेगा। स्पीकर साहब, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से गांवों के अंदर जो पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, वह पानी काफी बर्बाद हो जाता है। इस संबंध मे भी मेरा सरकार को सुझाव है कि यदि पानी बर्बाद होने से भी बच जायेगा। इसके साथ मेरा सुझाव यह भी है कि गांवों के अंदर औरतों को जंगल पानी जाने के लिये जगह नही है, सरकार को उनके लिये कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए। हमारे हरियाणा के अंदर इण्डस्ट्रीज की भी काफी तरक्की हुई है। अर्बन डिवैल्पमैंट के संबंध मे मैं यह कहना चाहता हूं कि उस मे किसानों के लिये भी कालोनियां बनायी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और सरदार हरपाल सिंह जी ने भी कहा है कि भविश्य मे किसानों की जो भी जमीन ली जायेगी, उसकी कीमत किसानो को मार्किट प्राईस की दी जायेगी। यह काम भी सरकार बहुत अच्छा करने जा रही है। जिन किसानों की जमीन ली जाती है। उनको प्लाटस भी दिये जाने चाहिए। भाहरों के अंदर जो किसान बैठे है, उनके घरों मे बडी भीड़ है। उनके पास मवे ाी है और काम आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। इनके लिये भी कालोनियां नो प्रोफिट नो लौस बेंसिज पर बनाई जानी

चाहिए। इस ढंग स मकान बनाने चाहिए जिससेये खुदआगे की तरफ रहे और मवे ाी पीछे की तरफ रखे जा सके। इनको भी प्लाट दिये जाये, दुकानें दी जाये क्योंकि अकेली खेती से आज काम नही चलता। अगर गवर्नमैंट मदद करे तो ये जमीदार दूसरे धंधे भी कर सकते है। अगर किसान की जमीन एक्वायर कर ली जाती है तो उसे मुआवजा पुरा नही मिलता। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाना चाहिए। (घंटी)

अब मैं रैवेन्यू के बारे थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। अगरहर जिले मे चार पांच पटवारखाने बना दिये जायें तो पटवारियों को का करने मे अच्छी सुविधा मिल जायेगी। जहां तक मैं जानता हूं, पटवारी की पोस्ट सैकड़ों सालो से चली आ रही है। उस वक्त न तो इतनी इंडस्ट्री थी, न इतने टैक्स थे, सारे दे ा का खर्चा लैंड रैवेन्यू से ही चलता था। इसलिये पटवारी के पटवारखाने के लिये जगह जरूर देनी चाहिए क्योंकि अगर किसी किसान ने फर्द लेनी होगी तो उसको जगह जगह जाना पड़ेगा। अगर पटवारी एक जगह बैठेगा तो किसान को परे ाानी कम हो जायेगी। (घंटी) इन भाब्दों के साथ मैं एप्रोप्रिए ान बिन नं0 1 और 2 का समर्थन करता हूं।

चौधरी हुकम सिंह फोगट (दादरी): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय ने एप्रोप्रिए ान बिल नं0 1 विधान सभा मे पे ा किया है और सरकार इसको पास करवाना चाहती है, मैं इस बिल

का विरोध करता हूं। स्पीकर साहब, अगर यह पैसा स्टेट की डिवैल्पमैंट पर खर्च होता तो कोई बात बनती थी इस खर्चे को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि आज जनता के पैसे को लूटाया जा रहा है। डिमांड नं0 2 मे जो लिखा है उसके मुताबिक राजभवन मे एक हाल बना रहे है और फौरन से एक कार खरीदी जा रही है। इतना बड़ा महल बनाने की क्या आव यकता थी? जनता के पैसे को इस तरह से बरबाद करने की क्या आव यकता है। इन्होंने मंत्रिपरिशद को बड़ा लम्बा चौड़ा बना दिया है। * *

* * * * * * * * * *

अगर ये मंत्री न बनते तो कोई बात बन नही सकती थी ओर अब इनकी कारे खरीदने के लिये यह पैसा खर्चा जा रहा है। इनकी कोठियों की सजावट के लिये जनता के पैसे को बूरी तरह से बहाया गया है। इसके दूसरी तरफ वाटर वर्क्स बन रहा है लेकिन वहां से वाटर पाईप्स का एक ट्रक कोई आदमी ले गया है। इस वाटर वर्क्स का सीमेंट खुलेआम बिक रहा है। यह वाटर वर्क्स पिछले 10 साल से बन रहा है लेकिन आज तक इसका काम पूरा नही हुआ है। कई गांवों मे खारा पानी है और लोग दो दो, तीन तीन मील चलकर अनी प्सास बुझाने के लिये जाते है। इसी तरह से एक वाटर वर्क्स इमलौट मे पिछले पांच साल से बन रहा है लेकिन अभी तक पूरा नही हो पाया है। स्पीकर साहब, भ्रश्टाचार की भी कोई हद होती है। आज खुलेआम सीमेंट बिक रहा है, नहर की लाइनिंग मे जो सीमेंट लगाना था वह चोर बाजारी मे बिक रहा है। लोहा और सीमेंट खुलेआम बिक रहा है। स्पीकर

साहब, एम0आई0टी0सी0 द्वारा मोघ डिस्ट्रीब्यूटरी पर लोहाखेड़ा मे चार पांच साल पहले खालें पक्की की गई थी लेकिन इस खालों मे चेपियां पड़ गई थी लेकिन इन खालों मे चेपियां पड़ गई है और पानी नही चलता। इससे तो कच्चे खाल ही अच्छे थे क्योंकि किसान बेचारे कच्चे खालों से अपनी जमीन को पानी तो लगा लिया करते थे। इन्होंने खाल पक्के तो कर दिये लेकिन सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल नही किया, सिर्फ बजरी ही बजरी चेप दी है। इन चेपियों को ठीक करवाने के लिये किसान भागता फिरता है। ये खाले एम0आई0टी0सी0 ने बनाई है और पिछले पांच सालों से ही खालों मे पानी न चलने के कारण किसान परे ाान है। जब खालो का पानी सुखता है तो चेपियां फट जाती है। स्पीकर साहब, सरकार इंडस्ट्रीज की बात करती है तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिये सरकार ने बहुत पैसा रखा है। इंडस्ट्रीज के बारे मे जब विधान सभीा मे हम कोई सुझाव देते है तो सरकार मानने के लिये तैयार नही होती। सरकार कहती है कि देहातों मे इंडस्ट्रीज लगाई जायें लेकिन अब्बल तो कर्जा मिलता ही नही, अगर मिले तो एक एक साल तक बैकों के चक्कर लगाने पड़ते है। बहुत से लोग कर्जा लेने केक लिये पांच पांच सौ रूपया खर्च कर के चुपचाप बैठे जाते है, कर्जा नही मिलता। अगर कोई आदमी कोि ा ा करके छोटी माटी इंडस्ट्री लगा लेता है तो सरकार की तरफ से उसको मदद नही मिलती। जो माल वह बनाता है, सरकार के पास कोई प्रबंध नही है। कि उस माल को बिकवाये। रूरल इंडस्ट्रीज मे जासे माल तेयार होता है सरकार को उस माल को बेचने मे इंडस्ट्रियलिस्ट

की मदद करनी चाहिए । यह तो जनता के साथ एक किस्म का धोखा है। कर्जा तो बेचारा बैंक से किसी तरह से ले लेता है लेकिन रा मैटीरियल उसको मिलता ही नही और यह जिम्मेदारी सरकार की है जो थोड़ा बहुत माल वह बनाता है, वह बिकता ही नही, परिणामस्वरूप आखिर मे वह इंडस्ट्री फेल हो जाती है। अगर सरकार इस समस्या का समाधान नही करेगी तो सारी की सारी रूरल इंडस्ट्री फेल हो जायेगी। नौकरियां तो लोगो को मिलती ही नही, जो मिलती है वह पैसों से बिकती है। अगर किसी गरीब आदमी के पास नौकरी खरीदने के लिये पैसा न हो तो वह इंडस्ट्री की तरफ भागता है और इंडस्ट्री का हाल तो आपने देख ही लिया है। आज गरीब इतनातंग है कि वह अपने दिन भूखा रह कर काट रहा है। स्पीकर साहब, चौधरी ई वर सिंह ने बताया कि किसानों को खाद के लिये 11 करोड़ रूपये की सैंट्रल एड आती है और यह एड सबसिडी के रूप मे दी जाती है। स्पीकर साहब, किसान को खाद पर सबसिडी उस वक्त देनी चाहिये जब किसान खेत मे बीजाई करता हूं क्योंकि बीजाई से पहले किसान खेत मे खाद डालता है या पहला पानी जब गेहूं के लिये लगता है, उस वक्त डालता है। इसलिये फरवरी ओर मार्च मे अगर किसान को खाद पर सबसिडी दी जाये तो किसान उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नही कर सकता, वैसे ही इधर उधर खुर्दबुर्द हो जाता है। फरवरी और मार्च मे खाद डालने का कोई मतलब नही होता। जो रूपया खाद के लिये आया भी है, वह हेराफेरी करके खुर्दबुर्द कर दिया गया। झूठे परमिट काट कर उस पेसा के खुर्दबुर्द कर

दिया और किसान को इसका कोई लाभ नही हुआ। किसान के नाम पर एक ऐंट्रल एड आती है लेकिन इसको दूसरे ही लोग हाजम कर जाते है। सरकार किसान की हमदर्द बनती है और कहती है कि 11 करोड़ रूपये की एड दी है। मैं पूछना चाहता हूं यह क्या खाक एड दी है। इसी तरह से बिजली बार्ड की बुरी हालत है। आज बिजली बोर्ड दीवालिया बन कर रह गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों मे बड़ी लार्ज स्केल पर बिजली की चोरी हो रही है। अगर कोई साधारण आदमी या किसान बिजली का बिल एक दो महीने न दे तो बिजली बोर्ड वाले उसका कनैक्शन काट देते है। इसके दूसरी तरफ मेरे एक क्वैश्चन के जबाव मे सरकार ने बताया है कि पचास पचास लाख, एक एक करोड़ रूपया एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ बकाया पड़ा है लेकिन इनके कनैक्शन नही काटे जाते। अगर इनके कनैक्शन काटने तो एक एक करोड़ रूपया इनकी तरफ बकाया न होता। किसान अगर एक महीने तक टयूबवैल की बिजली का बिल न भरे तो उसका कनैक्शन काट दिया जाता है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की यूनियन की तरफ से एक चार्ट पेश किया गया है। जिस मे बताया गया है कि बिजली बोर्ड मे कितना भ्रश्टाचार है,किस तरह से पैसे को खुर्दबुर्द किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जांच नही करवाई जा रही । अगर जांच करवाते तो महत्वपूर्ण नतीजे सामने आ सकते थे। स्पीकर साहब, जांच तो क्या होनी थी, बोर्ड मे भ्रश्टाचार आज चरम सीमा तक पहूंच गया है। बगैर पैसे के कोई काम नही होता। किसी भी डिपार्टमैंट मे लचे जाये, पटवारी के

पास चले जाये, पुलिस मे चले जाये, इतना भ्रश्टाचारहै कि बिना पैसे से कोई आदमी दफतर मे घुसने नही देता। लोग कहते है–

भजन लाल का राज है, लूटा जा तू लूट,

पाछे फिर पछतायेगा, जब भजन जायेगा टूट। (हंसी)

हर आदमी सोचता है, तू लूट ले और खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है । (घंटी) नहर का, बिजनी का, किसी भी डिपार्टमैंट को देख ले, सब का बूराहाल है। स्पीकर साहब, हरियाणा कृशि प्रधान प्रदे ा है। लोहारू कैनाल मे केवल एक बार पानी देते है जबकि उस एरिया मे कहरा पड़ा हुआ है गेहूं मे कम से कम पांच पानी की आव यकता होती है। एक पानी दे कर आबियाना उतना ही वसूल कर लेते है। एक पानी से किसान की तो कमर टूट जाती है, लगान तो उसे देना ही पड़ता है लेकिन नहर मे दोबारा पानी नही आता। सरकार ने रेतीले इलाकों मे छोटे छोटे मोघे लगा दिये है जिनसे पूरी सिंचाई भी नही हो सकती। नहर विभाग तो इसी हेरा फेरी मेलगा रहता है कि कहीं पर मौघे छोटे कर दिये और कहीं पर बड़े कर दिये। भिवानी जिला कहत की लपेट मे आया हुआ है। डिपार्टमैंट वाले पानी की चोरी खुद करवाते है। दादरी हल्के मे पांच छः टेल्ज है, वहां कहीं पर भी पानी नही पहुंचता है। किसानों की कुछ मदद हो जाती, अगर ये पानी वहां तक पहुंचा देते लेकिन यह सरकारन उन्हें पानी दे रही है और नही सस्ती बिजली दे रही है। किसानों की किसी

प्रकार की भी सहायता नही कर रही है। किसानों की पैदावार की भी पूरी कीमत सरकार नही दे रही है। स्पीकर साहब, आप भी किसान है और इस बात को जानते है कि गेहूं कीमत का आज तक एग्रीकलचर प्राइस कमी ान ने एलान नही किया जबकि गेहूं मार्किट मे आने वाला है। सरकार ने खाद, बिजली और खेतों मे इस्तेमाल होने वाली दवाईयों की कीमते तो बढ़ा दी लेकिन गेहूं की कीमत आज तक नही बढ़ पायी है। इस सब चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद भी किसान को अपने गेहूं की कीमत सही नही मिल पाती है। मंडी मे गेंहू जाता है तो वहां पर सरकार का इंस्पैक्टर लूटता है। किसान के गेहूं की कीमत सरकार मुकर्रर करती है लेकिन इंस्पैक्टर मंडी मे आधी ढेरियों को रिजैक्ट कर देता है कि ये खरीदने के काबिल नही है। इन्सपैक्टर से मंडी के व्यापारी मिल लेते है। वे इंस्पैक्टर की मिली भगत से उस गेहूं को खरीद लेते है और बाद मे फूड कार्पोरे ान को बेच देते है। इसलिये मैं इस एप्रोप्रिए ान बिल का विरोध करता हूं। यह पास नही किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः वित्त मंत्री।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, एप्रोप्रिए ान बिलपर तो ओर भी मैंबर बोलना चाह रहे है। इसके बार तो और कोई टाईम नही रहेगा कि हम किसी बात पर बोल सके।

श्री अध्यक्षः अब मैंने वित्त मंत्री को काल अपोन कर लिया है इसलिये आप नैक्सट बिल पर बोल लेना।

श्रीमती चंद्रावतीः सर, आप वित्त मंत्री को हुक्म दे कि दस मिनट के लिये बैठ जायें क्योंकि एप्रोप्रिए ान बिल पर तो बोलना बड़ा जरूरी है। जहां तक नैक्टस बिल का संबंध है उस पर तो कुछ नही कह सकते। अगर आप इजाजत दो तो अभी बोल लेती हूं। अपोजी ान को टाईम मिलना चाहिए केवल एक या डेढ़ घंटे का समय मिला है। अगर आपकी मर्जी हो तो समय और बढ़ा दे।

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, अगरआपकी अनुममि हो तो मुझे भी केवल पांच मिनट दे दे क्योंकि करोड़ों रूपये का एप्रोप्रिए ान बिल पास करवाने जा रहे है। मैं इस बारे मे बड़ी जरूरी बात कहने जा रहा हूं। आपको नये सदस्यों को भी टाईम देना चाहिए ताकि हम भी अपने विचार सदन मे प्रकट कर सके।

श्री अध्यक्षः अब समय नही दिया जा सकता क्योंकि अभी दो बिल और भी है। इसलिये आप उन पर बोल लेना।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, एप्रोप्रिए ान बिल नम्बर एक और दो सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस सन् 1982–83 तथा वर्श 1983–84 से संबंधित है, के बारे मे सदन मे बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे। हाउस के अपोजी ान

के साथियों को पहले मौका नही मिला था क्योंकि वे उस दिन वाक आउट कर गये थे इसलिये उन्होंने आज बहुत सी बातें कही है। कुछ साथियों ने अपने क्षेत्र के बारे मे कहा है जो जवाब देने योग्य भी है। मैं एक बात सदन के नोटिस मे लाऊं केवल रिवाइजड एसटीमेटस 81 करोड़े 92 लाख रूपये के रखे गये है जिनमे से 41 करोड़ 79 लाख रूपया ऐसा होगा जो वास्तविक रूप से खर्च होगा। 40 करोड़ 23 लाख रूपया ऐसा है जो हमें बाहर से सहायता के रूप मे मिल जायेगा या काउंटर एंट्री होनी है, उनसे पूरा हो जायेा। खाते मे एंटरी होगी, जितना आया होगा उतना व्यय हो जायेगा, वह खाता ठीक रखने के लिये है। इसमे से ज्यादातर पैसा डिवैल्पमैंट के कामो पर खर्च हुआ है। जैसा सूखा पड़ गया था लोगो को राहत देने पर खर्च हुआ। डिवैल्पमैंट पर 7 करोड़ 36 लाख हैल्थ पर 5 करोड़ 26 लाख, सो ाल वैल्फेयर पर, 5 करोड़ 70 लाख, इंडस्ट्री पर एक करोड़ 79 लाख और एग्रीकलचर पर 7 करोड़ 90 लाख रूपया खर्च हुआ है। वही सारे का सारा डिवैल्पमैंट के काम पर खर्च हुआ है, जिनके बारे मे उस वक्त यानी बजट के टाईम पर अनुमान नही लगा सके थे। साल के दौरान इस पैसे को खर्च करना जरूरी समझा गया था क्योंकि प्रदे ा के लिये वकास के जरूरी काम करने थे, इसलिये इस बारे मे साथियों को आपत्ति नही होनी चाहिए। इसे पास करना चाहिए। डाक्टर मंगल सैन जीने और एक साथी ने कहा कि मिनिस्टरों के घरों और दफतरों की फरनि िंग का खर्चा बढ़ गया है। यह बात उनकी किसी हद तक ठीक है लेकिन यह बात

भी सही है कि उस खर्चे की केवल लिमिट बढ़ायी गई है, यह लिमिट बहुत पहले की रखी हुई थी। आज के दिन चीजों के दाम ज्यादा हो गये है, मकानों के किराये भी पहले की रखी हुई थी। कुर्सी और दूसरे फर्नीचर की कीमतें भी बढ़ गई है। ये चीजें आज सेपांच दस साल पहले के भाव पर नही मिलेगी। अगर इस मार्किट से कोई भी चीज आज के दिन खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं हाउस को यह वि वास दिलाता हूं कि कोई लग्जरी का आइटम नही बढ़ाया है केवल पैसे की लिमिट बढ़ायी है, वह भी इसलिये बढ़ायी है कि कीमतों मे वृद्धि हो चुकी है।

स्पीकर साहब, कारों के बारे मे भी बात कही गई। जहां कार की जरूरत होती है वहीं के लिये कार ली जाती है। कारों पर नियम के हिसाब से सरकार ने रोक लगा रखी है ताकि कार का कोई गलत इस्तेमाल न करे। जहां तक मुझे याद है पिछले साल मे तीन चार कारें खरीदी है वरना हम पुरानी कार की रिपेयर करा कर ही कहते हे कि इसे ही आप चलाये। कई बार रिपयेर मे भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ज्यादा पैसा फिजुल मे खर्च नही किया है। बोर्ड और कार्पोरे ांज का भी सदन मे ख्चर्चा हुआ । इस बारे मे कोआप्रे ान मिनिस्टर साहब जवाब दे चुके है। उन्होंने बताया था कि कई कार्पोरे ांज और बोर्ड घाटे मे है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हे कर्मचारियों को तन्खाह और डी0ए0 तो देना ही पड़ता है । यहां कहा गया कि वहां चोरी बढ़ गई है। अगर वहां बिजनैस की एक्टीविटीज हो तो यह खर्च और आमदनी

मे इतना ज्यादा अंतर न रहे। वहां की एक्टीविटिज भी घाटे की है। जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज ने ट्रैक्टर्ज खरीदे थे। जब तक वे नये रहे तो मुनाफे मे चलते रहे लेकिन जब वे कंडम हो गये है। उनके ड्राइवरर्ज तो यों के यों रखे हुए उनस दूसरा काम लेना पड़ता है। ऐसे काम सरकार ने भुरू किये हुए है जिसमे घाटे और मुनाफे की ज्यादा की बात नही है, इसलिये गरीब और किसान वर्ग को उठाने के लिये एसेा करना जरूरी है। यहां सदन के कुछ सदस्यों ने कहा कि अगर ये सारे बोर्ड और कारपोरे ांज अमीर आदमियों को बेच दी जायें या उनके हवाले कर दी जाये, फिर देख लेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन फैक्ट्रियों का या कंसंर्ज का अमीरों को बेचना, कोई अच्छी बात नही है और यह प्रदे ा के हित मे भी नही होगा। जो बातें यहां पर हो चुकी है, मैं उनको दोहराना नही चाहता। पुलिस के खर्च बढ़े है। अक्ष्यक्ष महोदय, इस बारे मे भी बहुत बाते ंयहां पर हो चुकी है। सवालों के जवाब मे आ चुका है कि पुलिस के खर्चे निसंदेह बढ़े है और उसके केई कारण है। कुछ तो सिपाहियों ने और दूसरे रैंक्स ने थौड़ी सी इनडिस्पिलिन की बात कर दी । इसके अलावा एि ायाड के इंतजाम बगैरह की वजह से कुछ ला एड आर्डर की बात भी खास रही । ला एंड आर्डर कोमेनटेन करने के लिये और सिक्योरिटी रिजन की वजह से कुछ खर्चे बढ़े है। हमने इस बात की पूरी कोि ा ा की है कि यह खर्चे महसूद रहे और जरूरत के मुताबिक हो और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न हो। मुझें आ ाा है कि कुल मिला कर सारा सदन मेरी इस बाम से मुतलिफ होगा

कि अगर पुलिस के खर्चे बढ़े है तो हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की हालत मे सारे दे ा मे सबसे अच्छी रही है। वह कोई बात नही होती कि अरग किसी एक आदमी की जान का नुकसान हो जाये और हम मुंह दुखते रह जायें किसी की जान का नुकसान न हो, इस बात की जिम्मेवारी सरकार की है। ऐसे तो बात नही बनती कि पहले किसी की जान का नुक्सान होजाये फिर जवाबतलबी होती फिरे। सरकार ने ला एंड आर्डर ठीक रखने के लिये और अमन को कायम रखने के लिये जो पुलिस के कुछ खर्चे किये है, यह प्रदे ा के और दे ा के हित के लिये किये है। एक्साईज डिपार्टमैंट के लिये रिवाईज्ड एस्टीमेटस मे कुछ खर्चा मांगा गया है। चौकिया बढ़ायी गयी है, कुछ स्टाफ बढ़ाया गया है, चौकसी/रेड्स करने के लिये और टैक्स की इवजन को रोकने के लिये हमने स्टाफ बढ़ाया है। इससे हमारी पहले के मुकाबिले आमदनी भी बढ़ी है और इवेजन पहले से कम हुआ है। डाक्टर साहब ने कालेजों को दी जाने वाली ग्रांट की तो सराहना की लेकिन प्राईवेट स्कूलों के बारे मे एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि उनकी भी कुछ मांगे है, उनको मान लेना चाहिए। डाक्टर साहब को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ कोई कड़ी निगाह नही रखती। इन प्राइवेट स्कूलों को भी हरियाणा सरकार की ओर से उनके घाटे का 75 प्रति ात अनुदान या ग्रांट के रूप मे दिया जाता है। ऐसा पिछले दो तीन सालों से हो रहा है। पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख रूपया इन प्राइवेट स्कूलों को घाटे की वजह से दिया गया था जो अब इस

साल बढ़ कर 3 करोड़ 35 लाख हो जायेगा। जहां तक इन प्राइवेट स्कूलों के सारे घाटे/खर्चे का संबंध है, वह तो भाायद सरकार बर्दा त नही कर पायेगी। इस बात को हमारे आनरेबल मैंबर्ज भी महसूस करेंगी कि हम इनके साथ कोई ज्यादती नही कर रहे है। ऐसी कोई बात नही है कि हम जान बूझ करइनको नही देना चाहते आपके पता ही है कि जैसे जेसे स्टेट के फाइर्नसिज एलाउ करते है, उसी हिसाब से यूनिवसिर्टी रोहतक को 8 लाख रूपया देने के बारे मे कही। अगर तो यह पैसा कहीं मिसयूज हुआ है, फिर तो अलग बात है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि यह पैसा सिर्फ एम्पलाईज के एडी ानल डी0ए0 का है और कुछ जो 1979 मे एम्पलाईज की तनख्वाहें इंक्रीज हुई थी, उसकी वजह से प्रोवीडैंट फंड जो उनका बढ़ा है, उसका खर्चा है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने तो इनसे यह अ योरैंस मांगा था कि दुलत कमी ान ने रिपोर्ट मे वहां के वाइस चांसलर के बो मे कमैंटस दिये है, उनके बारे मे आप एक ान कर तक ले लेंगे?

चौधरी कटार सिंह छोकरः सदन मे यह बात पहले भी हो चखुकी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका जवाब दे दिया है कि वह रिपोर्ट प्रोसैस हो रही है। उस रिपोर्ट को अभी सरकार देख रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन बातों का जवाब आ चुका है, उन बातों को दोहराने की जरूरत नही है। एक बात यहां

पर स्पोर्टस के बारे मे कही गयी। एि ायाड मे हरियाणा के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किये, इसकी तो तारीफ की गयी। और कुल मिला कर सारे खिलाड़ियों के मुकाबिले मे यह भी कहा गया कि हमारा बहुत ही अच्छा योगदान था। एक बात डाक्टर साहब ने कही, भाायद मैं उसको गलत समझ सका हूं और या डाक्टर साहब उसको ठीक तौर पर समझा नही सके। उन्होंने यह कहा कि अर्बन डिवैल्पमैंट के लिये कम खर्च रखा गया है। यह अनुपात के हिसाब से होना चाहिए था। भाायद उनका मतलब रिवाईज्ड एस्टीमेटस मे दिये गये खर्चो केबारे मे था। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि ये रिवाईज्ड एस्टलमेटस या किसी सारे साल के एस्टीमेटस किसी अनुपात से नही बनाये जाते। (व्यवधान व भाोर).....

श्री मंगल सैनः मैंने आपको यह सुजैस्ट किया था कि आबादी के हिसाब से आपको अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज मे खर्च करना चाहिए।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, हम रूरल एरियाज की डिवैल्पमैंट और अर्बन एरियाज की डिवैल्पमैंट का पूरे तौर पर, और बराबर ख्याल रखते है। एक बात डाक्टर साहब ने कह दी कि स्टेट लैवल पर कोई ग्रिवैसिज कमेटी बना दी है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि स्टेट ग्रिवैन्सिज कमेटी कोई नही है। केवल डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैंसिज कमेटीज है। मैं यह समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैसिज कमेटीज बहुत अच्छा

काम कर रही है। हर आदमी की ि ाकायत के बारे मते , जब तक उसको सामने न सुना जाये तब तक कोई समाधान नही हो सकता। इसलिये जब तक उसकी ि ाकायत दूर नही हो जाती, उसकी ि ाकायत की सुनवाई को हर महीने चालू रखा जाता है। मैं यह समझता हूं कि इस कमेटी के लोगों के कश्ट निवारण के लिये बहुत अच्छा काम किया है। एक बात उन्होंने रायट रिलिफ के बारे मे कह दी कि साहब यह एक लाख रूपया फिलीस्तीनियों को क्यों दे दिया गया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस की डिमांडज मे पेज 51 पर यह लिखा है। कि स्टेट लैवल पर कोई कमेटी बनी हुई है, उसके लिये 29400 रूपया इनको दिया जाये। मैंने बहिन भाकुंतला जी को यह कहा था कि आप तो खुद हरिजन है और आप उनके दुःख को बेहतर समझती है। सरकार यह कहती भी है कि हम हरिजनों का खास तौर पर ख्याल रखते है। अगर ऐसी बात तो फिर स्टेट लैवल पर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, स्टेट लैवल की जैसे मैनें पहले कहा, कोई कमेटी नही है, (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, अगर यह बहुत ज्यादा जिद्द करते है तो मैं इनको देख कर बता दूंगा। वैसे स्टेट लैवल पर कोई ग्रिवैन्सिज कमेटी नही है। डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैंसिज कमेटी जरूर बनी हुई है। (व्यवधान व भाोर) यह मेरे से बाद मे मिल ले, मैं इनको पोजी ान बता दूंगा।

Shri Mangal Sien: On a point of order, Sir. I am onpage 51 of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83. wherein it is written:-

"In order to devote special attention to the cases of victimisation and discrimination in respect of the members of the Scheduled Casts and blckward Classes, a State Level Grievances Committee has been set up by the State Government."

Chaudhri Katar Singh Chhokar: That is for the members of the Scheduled Castes. सपीकर साहब, इन्होंने तारे अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया है कि हरिजनों के लिये है। यह कोई जनरल कमेटी नही है। (व्यवधान व भाोर) आपने खुद तो बता दिया है कि हरिजनों के लिये यह कमेटी है। जनरल ग्रिवैंसिज कमेटी कोई भी स्टेट लैवल पर नही है।

श्री फतेह चंद विजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो बैग्यिर्ज पर 24 घंटे मे तीन ि ाफ्टों मे 20—25 हजार रूपया रोज का रि वत का लिया जा रहा है। इसको रोकने का कोई इंतजाम किया जा रहा है या नही या केवल जनता के ऊपर टैक्स ही बढ़ा रहे हो?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, जहां तक फिलीस्तीनियों को एक लाख रूपये देने की बात है, वह एक लाख रूपये का खर्च तो हमने इस साल के बजट मे दौरान रखा

हुआ था लेकिन हमें दो लाख रूपये के कम्बल फिलीस्तीनियों के लिये देने पड़े, इसलिये यह एक लाख लाख रूपया मांगा गया है

श्री मंगल सैनः क्या आपका असम वालों के लिये भी कोई प्रोग्राम है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः जब उनके लिये प्रोवीजन आयेगा तो आप आपति कर लेना। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैनः साहब, इसमे तो कोई आपत्ति वाली बात ही नही है। जब फिलीस्तीनियों के लिये आप यह कर रहे हो तो आसामियों के लिये क्यों नह कर रहे हो?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, दुनिया मे आपसी इतना रि ता है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से मे भी कोई परे ाानी आती है तो उसमे छोटी मोटी राहत हर जगह से आती है। डा0 साहब, थोड़ा सा उदार होना चाहिए।

श्री मंगल सैनः आसाम वालों के लिये भी आप कुछ उदर हो जाओ।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, यह पिदले साल की बात है। जब यह पैसा दिया गया था।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमैंट विदे ाों मे सहायता के रूप मे पैसा दे तो बात मानी जा सकती

है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट विदे ाों के लिये पैसा बजट मे रखे यह तो अनप्रैसिडैंटिड बात है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, अगर एक दो लाख रूपया आसाम वालों के लिये भी रख देते तो उससे उनका क्या होने वाला था। सैंट्रल गवर्नमैंट ने चालीस करोड़ रूपया उनको दिया है। एक दो लाख से क्या फर्क पड़ने वाला है। स्पीकर साहब, चौधरी किसताब सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिये बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूं कि इस आने वाले साल मे 43 करोड़ 80 लाख रूपये से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिये रखा है और जो चालू साल खत्म हो रहा है उसमे भी तकरीबन इतना ही रूपया रखा गया था। आप अंदाजा लगा सकते है कि यह रा ि ा कम नही है। स्पीकर साहब, उन्होंने कहा कि हैल स्टोर्म से किसानों की फसलों का 170 करोड़ रूपये का नुक्सान हुआ है और सिर्फ चौदह करोड़ रूपये की राहत किसानों को दी गई, वह नुक्सान हुआ और सिर्फ चौदह करोड़ रूपये की राहत किसानों को दी गई, वह नुक्सा के अनुपात मे काफी नही है। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि आलों से या दूसरी कैलेमिटी से जो नुक्सान होता है सरकार उनको सैंट परसैंट पूरा नही कर सकती। मान लो किसी का मकान गिर गया और मकान गिरने से उनका दस लाख का नुक्सान हो गया तो सरकार उसको किसी भी तरह से पूरा नही कर सकती। सरकार तो टोकन रिलीफ दे सकती है। सदन के

सभी माननीय सदस्य जानते है कि इस सरकार ने 182–83 मे चौदह करोड़ से अधिक रूपया ओलो से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जबकि आज तक जो भी सरकार आई उसने एक दो करोड़ रूपये से ज्यादा मुआवजा नही दिया। यह ठीक है कि किसान का नुक्सान हुआ है और अब का सरकार एक दो करोड़ की मदद दियाक रती थी परंतु इस सरकार ने चौदह करोड़ की सहायता दी है।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी ने माना है कि किसानों का 170 करोड़ रूपया का नुक्सान हुआ है और जैसा सरकार का फैसला है कि अगर 75 परसैंट से ज्यादा नुक्सान होगा तो चार सौ रूपया फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा तो उस हिसाब से तो मुआवजा दिया जाना चाहिए था।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, पीछे जब भी राहत दी गई, वह तीन सौ रूपये फी एकड़ के हिसाब से दी जाती रही है। लेकिन हमने सौ स्पया अधिक दी है। मतलब यह है कि हमने चार सौ रूपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। स्पीकर साहब, उन्होंने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेटस ज्यादा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान जो पैदा करता है उकसा रेट कम है और दूसरी चीजों के रेटस ज्यादा है। अगर किसान की चीज के रेट ज्यादा हो जाये तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिये स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इसके लिये बहुत सी

तैयारी करनी पड़ती हैं यह मामला भारत सरकार से संबंधित है। यह जनरल इकौनोमिक पौलिसी की बात है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सदन केनोटिस मे लाना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमैट के दौरान चाहे वह सैंटर मे है यह स्टेटस मे है। एग्रीकल्चरप्रोड्यूस की कीमत कौंसटैंटली रीजनेवली बढ़ाई गई है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब जनता राज आया था और प्रका ा सिंह बादल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सैंटर मे बने थे तो उन्होंने दावा किया था कि गेंहू की कीमत 125 रूपये प्रति क्विंटल कर दूंगा। उस वक्त 110 रूपये से केवल एक सौ साढ़े बारह रूपये कीमत ही वे कर पाये थे। केवल अढ़ाई रूपये की बढ़ौतरी ही वे कर पाये थे और उनको रिजाइनकरके वापस आना पड़ा था। कांग्रेस के टाईम मे कौंसैंटटलीदस, बारह रूपये कीमत बढ़ती रही है। पिछले साल 142 रूपये प्रति क्विंटल थी और सभी स्टेटस के चीफ मिनिस्टर यह कोि ा ा करते रहे कि कीमत बढ़ाई जाये।

श्री मंगल सैनः 1973 मे जब चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर थे और भजन लाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उसवक्त हरियाणा मे 74 रूपये का भाव था। किसान संघर्श समिति के आंदोलन के कारण उस वक्त गेहूं का भाव 110 रूपये दिया गया था और यह कहते है कि कांग्रेस सरकार ही दाम बढ़ाती रही है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः डा0 साहब, किसान का भला होना चाहिए। स्पीकर साहब, श्री किताब सिंह ने कहा

कि एम0एल0एज0 की पैं ान बंद होनी चाहिए गोहाना वाले एम0एल0ए0 अच्छा ही सुझाव देते है लेकिन यह आल इंडियालेवल की बात हो गई है। अगर पैं ान बंद होने का मौका आता है तो हमें कोई एतराज नही है। अपोजी ान वाले रिटायर हाने के आद पैं ान न ले। अगर ये पैं ान नही चाहते तो ये लिख कर दे दे। अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम ने कहा कि उनके यहां कोई रजिस्ट्री क्लर्क है वह बहुत क्रप्ट हैं उसने दो कोठी और एक कार बना ली है फिर कहा कि एम0आई0टी0सी0 द्वारा वाटर कोर्सिज मे सीमेंट नही लगाया जाता बल्कि ब्लैक मे बेचा जाता है। उनकी ये बाते नोट कर ली हैं अरग इस तरह की बात उएनके क्षेत्र मे हो रही है तो वे खिल कर दे तो अच्छा रहेगा। (ाोर व व्यवधान) स्पीकर साहब, नम्बरदारों को पचौतरा दिलाने की बात कही गई है, स्पीकर साहब, सरकार इस पर गौर करेगी। स्पीकर साहब, श्री जसवंत सिंह चौहान ट्रेजरी बैंचिज से बोले और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि डाउरी मांगने की वजह से अगर कोई डैथ होती है तो उस पर पैनल्टी लगनी चाहिए। स्पीकर साहब, डाउरी डैथस के बारे मे मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से बता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर देहात मे कोई आदमी प ाु नही रखता तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। ऐसा करने से देहात मे लोग प ाु रखने लगेंगे और कैटल वैल्थ इंक्रीज होगी। उनका सुझाव अच्छा है लेकिन अभी सरकार का इस तरह का टैक्स लगाने का इरादा नही है। स्पीकर साहब, चौहान साहब ने यह भी कहा कि उनका राई

का इलाका फलडिड एरिया है, वार्डर पर बसा हुआ है और वहां पर बहुत से ऐसे गांव है जो जमना मे आ जाते है। वहां पर सड़क बनाई जाये। स्पीकर साहब, वहां पर सड़क तो बनाई जा सकती है लेकिन पुल नही बनाया जा सकता क्योंकि जमना इरोजन कर देती है थोड़ी कीमत का पुल तो वहां ठहर नही सकेगा। सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है और मैं वि वास दिलाता हूं कि जो गांव बाकी है, सब को सड़क देंगे।

जो गांव नक ों पर रही है, जो डायरैक्टरी विलेजिज नही है अगर वहां की आबादी 250 की है और हरिजन कालोनीज मे आते है तो वहां पर सरकार सड़कें बनाने जा रही है।

श्री फतेह चंद विजः स्पीकर साहब, ब्रिजिज की बात अगर प्रैक्टीकेवल नही है तो जो गांव सड़कें न होने के कारण आपस मे मिल नही पा रहे, कम से कम वहां पर तो सड़कें बना कर उनको आपस मे मिलाया जाये।

चौधरी कटार सिंह छोकरः ठीक है, इस तरह के गांवों को आपस मे मिलाने के लिये सड़कें बनाई जायेगी। चौहान साहब ने एक सुझाव दिया है दिल्ली से लेकर मूरथल तक एक कच्चा बांध है, उसको पक्का कर दिया जाये और साथ मे सड़क भी बना दी जाये। मैं उन्हे कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो यह फिजीकल नही है। जब यह एग्जामिन होगा। तब इस पर विचार कर लेंगे क्योंकि ऐसा काम सारे प्रदे ा के लिये करना पड़ता है। एक ओर

बात उन्होंने स्कूल बिल्डिंग्ज के बारे मे कहीं कि उनके हल्के मे बहुत से गांवों मे स्कूल बिल्डिंगज बना रखी है लेकिन स्कूलों को अपग्रेड नही किया गया है। फिर भी मैं इस बारे मे उनकी डिमांड एजुके ान मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दुंगा और आ ाा है कि सरकार उनके इस सुझाव पर भी अव य विचार करेगी। एक बात और उन्होंने कही कि इंडस्ट्रीज के लिये सरकार दिल्ली के नजदीक लगने वाले गांवों की जमीन, गरीब किसानों की जमीन एक्वायर कर लेगी है जिससे वे लोग बेरोजगार हो जाते है। जब नौकरी वगैरह देने की बात आती है तो बड़े बड़े इंउस्ट्रियलिस्टसबाहर के लोगो को रख लेते हे। इससे उस इलाके के लोगो को बड़ी परे ाानी होती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बारे मे कुछ कर सकी तोइसओरपूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरि चंद हुड्डा जी ने भी एक आध बात कह दी। वे अपना सांग करके बैठ गये। मेरे तो कोई बात पल्ले नही पड़ी कि वे कह गये इसलिये किस बात का मैं जवाब दूं। सिर्फ खेती के बारे मे उन्होंने कहा कि एनुअलप्लान मे इसके लिये बड़ा पैसा रख गया, उसके लिये पैसा ज्यादा रखना चाहिए था। मैं जो कहूंगा वह उनकी समझ मे भाायद नही आयेगा। खेती के लिये जो प्रोवीजन रखा गया है, आने वाले साल मे उसमे 18.43 परसैंट वृद्धि की है। यह उनका कहना बिल्कुल निराधार है कि खेती के लिये जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम है।

इससे आगे श्री ई वर सिंह जी ने भी एक दो सुझाव दिये कि सिलेबस मे चेंज होनी चाहिए। रिलीजस, फिजीकल और योगा वगैरह सबजैक्ट भी स्कूलों/कोलेजों मे इंट्रोडयूस होने सुझाव दिये। हम उनसे सम्पर्क करके जैसे जैसे फिलीकल हुआ, कर लेंगे। एक ओर बात इन्होंने कही कि बस स्टैण्डज के लिये जमीन एक्वायर करने के बाद वहां वृक्ष लगाने चाहिए, इस पर भी हम गौर करेंगे।

चौधरी हुक्म सिंह जी ने बोलते हुए सरकार के ऊपर कुछ आरोप भी कसे और कुछ सुझाव भी दियें सब से पहले उन्होंने कहा कि राज भवन के अंदर एस्सटैं ान की गयी है। वैंकुट हाल बनाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर महोदय के लिये नई कार भी खरीदी गयी । यह बिल्कुल ठीक है। गवर्नर महोदय के लये नई कार खीरीदी गयी और पुरानी को बेचकरी यह कारी खीरीदी गयी है। गवर्नर का औहदा एक प्रतिश्ठा का औहदा होता है। वैन्कुट हाल कोई गवर्रन साहब ने उठाकर नही ले जाना, हमें इस तरह की बाते सहां पर कहना भाोभा नही देती। अगर आनरेबल मैंबर इसको फिजूल खर्ची कहे तो उनके लिये यचह उचित नही हैं एक दो बातें उन्होंने अपने हल्का के बारे मे भी कही कि इमलौट ओररानीलावाटर वर्कस का काम पिछले 5–10 सालों से वेसे ही पड़ा हुआ है। उस परकाम चालू था, लेकिन अब वे काम रूके पड़े है। मैं उनको इस हाउस मे आ वासन दिलाना चाहता हूं कि संबंधित विभाग का इस बारे

ध्यान आकर्शित कर दिया जायेगा और इस काम को जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट करवा दियाजायेगा दुसरा उन्होनं मौंघ डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे मे भी कहा कि एम0आई0टी0सी0 जो खाले बना रही है पानी आते ही वे खालें टूट जाती है, लाइनिंग ठीक नही है। खालें तो कई जगहों पर बनायी गयी है। अगर माननीय सदसय किसी पार्टिकूटलर जगह का नाम हमारे नोटिस मे लाऐ तो हम अव य उनकी बातों पर ध्यान देकर वाहं काम करवाने की कोि ा ा करेंगे और मुरम्मत भी आव यक करवा दी जायेगी जो खालें पिछले पांच पांच सालों से रूकी पड़ी है, उनको भी जल्दी ही बनवा दिया जायेगा। इसके साथ उन्होंने फर्टीलाइजर पर सबसिडी की बात कही कि इसका मिस युटीलाइजै ान हो रहा है। अगर माननीय सदस्य कोई बात हमारे नोटस मे लायेंगे तो हम आव य कार्यवाही करेंगे ओरध्यान रखेंगे कि आगे के लिये किसी के साथ कोइ घांधली न होने पाएं जहां तक एच0एस0ई0बी0 का ताल्लुक है, इस बारे मे कै चन आवर हमे ही आई0पी0एम0 साहब ने सारी पोजी ान क्लीयर कर दी थी। फिर भी मैं आनरेबल मैंबर्ज की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे एच0एस0ई0बी0 की हालत काफी अच्छी है। पहले एच0एस0ई0बी0 ने हमें काफी परे ाान किया था क्योंकि पानीपत और फरीदाबाद के दोनों थर्मल पलांटस खराब पड़े हुए थें लेकिनअब पानीपत के दोनो थर्मल पलांट जोकि 110–100 मैगावाट के है, वे अपनी 85 परसैंट कैपेसिटी पर चल रहे है अब हमें किसी बात की कोई परे ाानी नही है। इस वक्त

हमारी युटीलाइजे ान सारे दे ा मे टंाप पर है बे ार्ते की डाक्टर मंगल सैन जेसे उसे इसी हालत मे रहने दें (ाोर एवं व्यवधान) इन्ही भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूआ यह रिक्वैक्ट करूंगा कि इन एप्रोप्रिऐ ान बिल्ज को पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into ocnsideration at one.

The motion was carried

Clause 2 and 3, Schedule, Clause 1, Enacting Formula and Title

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 and 3, the Scheuled, clause1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into ocnsideration at one.

The motion was carried

Clause 2 and 3, Schedule, Clause 1, Enacting Formula and Title

That clause 2 and the Schedule, clause 1, the Enacting formula and the Title stand part of the Bill.

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगूले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983

श्री अध्यक्षः मुझे श्री मंगल सैन एम0एल0ए0 की ओर से फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट आडिंनैंस, 1983 (हरियाणा आर्डिनैंस नं0 2 आफ 1983) की अप्रूवल के लिये नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय बचाने के लिये इस प्रस्ताव पर और बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाये। परंतु चर्चा समाप्त होने पर इन पर अलग अलग मतदान किया जायेगा।

आवाजें: ठीक है जी।

श्रीमती चंद्रावतीः जनाव आपने जो हुकम दिया है वह हमने मान लिया है लेकिन एप्रोप्रिए ान बिल पर कुछ बोला जा सकता था। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस तो आई नही है। कल एक पुलिस एडमिनिस्ट्रे ान की रिपोर्ट आई थी जोकि वर्श 1978 की थी।

श्री अध्यक्षः बहिन जी अब तो एप्रोप्रिए ान बिल पास हो चुका है। वैसे भी आपसे अपनी पाटी के बोलने वालों के नाम मेरे पास भेजे थे और उसमें आपने अपना नाम नही लिखा था।

श्रीमती चन्द्रावतीः मैंने आपको जुबानी कहा था। बहुत सारी बाते कहने की थी। क्योंकि बाते तो बजट पर या डिमांडज पर बोलते ही कही जा सकती है।

श्री अध्यक्षः वह तो अब पास हो चुके है, आप कृपया बैठिये।

श्री मंगल सैंनः स्पीकर साहब, कल जब हम यहां पर आये तो हमै। पुलिस एडिमिनिस्ट्रे ान की 1978 की रिपोर्ट मिली। रूल्ज के मुताबिकइन पर डिसक ान के लिये हमें नोटिस देना पड़ता है। फिर जैसा कि आप जानते है सारा विजनैस र ा थ्रू किया जा रहा है। हम चाहते थे कि इस रिपोर्ट को स्टडी करके इस पर बहस की जाये। स्पीकर साहब, हम उस बात से डिप्राइव हो गये। आप इनकों इस बात की इजाजत न दें कि ऐसी रिपोर्टस फैग एंड मे लाएं बल्कि भारू मे लाएं।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) सं ाोधन अध्यादे ा, 1983 (1983 का हरियाणा अध्यादे ा संख्या 2) का निरनुमोदन करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह हाउस फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट अर्डिनैंस, 1983 (हरियाणा आर्डिनैंस नं0 2 आफ 1983) को डिसएप्रूव करता है।

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, लोकल बाडीज के मिनिस्टर महोदय ने पहले तो यह इजाजत दे रखी थी कि फरीदाबाद कम्पलैक्स मे 11 साल के बाद चुनाव कराये जायें और अब इन्होंने एक साल और बढ़ाने की मांग की है। ये हम से चाहते है कि हम इस बात पर मोहर लगाये। स्पीकर साहब, इस बिल के स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज मे इन्होंने फरमाया है।

".....Government in the Locak Self Government has for some timepast been exploring the possibilities of declaring Faridabad Complex as 'A' Class Municipalities/Corporation. It sas not possible to ninalise action before 14th January, 1983 when its present term was expiring. As such the period to constitute an elected body in Fariidabad Complex was extended by one year by issue of an Ordinance on 14th January, 1983."

स्पीकर साहब, लोक बौडी की गवर्नमैंट पिछले कई दिनों से यह बात एक्सप्लोर करती रही है या सम्भावनाओं के बारे मे प्रयत्न कर रही है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स को या तो 'ए' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी करार दे दिया जाये अथवा उसको निगम

बना दिया जाये। यह सरकार पिछले 11 सालों मे तकय नही कर सकी। अब ये कह देंगे कि दो अढ़ाई साल आपको भी मिले, आपने क्या किया था। ये दो अढ़ाई साल का रोना अननी चमड़ी बचाने के लिये और उस गवर्नमैंअ की इन एफिशिएंसी भाो करने के लिय रोते है। अगर हमारा मामला ठीक रहता और हमारे साथी दल बदल कर न भागते तो आपने आज यहां नही होना था। (ाोर) स्पीकर साहब, इस कम्पलैक्स से पहले वहां पर दो म्यूनिसिपल कमेटियों थी। एक ओल्ड फरीदाबाद की और दूसरी बल्लभगढ़ की । स्पीकर साहब, इनहोंने फरीदाबाद टाउनि ाप और 17 गांवों को मिलाकर यह कम्पलैक्स बनाया था। स्पीकर साहब, यह भी संयोंग की बात है कि जब फरीदाबाद कम्पलैक्स का एकट बना तो मैं उस समय भी इस हाउस का मैंबर था। उस समय हमने चौधरी बंसी लाल जी से कहा था कि आप इलैक्टिड बाडी क्यों नही बनाते। उन्होनें कहा कि अभीतो नया नया एक्सपीरिएंस है, कुछ दिनों के बाद बना दंगे। धीरे धीरे साल बढ़ते गयेऔर आज बाहरवें साल पर पहुंच गये। देखने वाली बात यह है कि वह एरिया दिल्ली के नजदीक है और लोग किस तरह से वहां परजमीन ले रहे है। हैफ्हैजर्ड ग्रोथ हो रही है। सारे दे ा से आए लोग वहां पर काम करते है। वहां पर उद्योग पतियों ने उद्योग लगा रखे है और काफी करोबार फलोरि ा कर रहे है अगर एक युनिट के हिसाब से हरियाणा का कोई सब से बड़ा इलाका है तो वह फरीदाबाद है और उसके बाद हमारे भाहर का नम्बर आता हैं स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी का तकाजा है और आप

जानते है कि जब अमरीका ने इंगलैंउ के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था तो कहा था कि 'नो टैक्से ान विदआउट रिप्रजेंटे ान' यानी बिना प्रतिनिधतव के कोइ टैक्स नही देगा। अगर म्यूनिसिपल कमेटी या कार्पोरे ान मे हमें नुमायंदगी नही मिलेगी तो हम आपको कोइ टैक्स नही देंगे। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी की पहली पीढ़ी लोकल बाडीज यानी पंचायत है। जहां से आदमी डैमोक्रेटिक फंक ानिंग का अभाव सीखता है। इस दे ा के बड़े मानीय नेता हो चुके है जैसे पहले प्रधान मंत्री, पहले राश्ट्रपति, पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भी बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो इन संस्थाओं से संबंधित रहे। इनमे से कुछ इलाहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी और पटना की म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैजीडैट रहे। लाला लाजपत राय लाहौर म्यूनिसिपल कमेटी के म्यूनिसिपल कमि नर थे। इसी प्रकार से बल्लभ भाई पटेल अपने क्षेत्र की म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैजीडेंट थे और धीरे धीरे राइज करते हुए उन्होंने दे ा के प्र ाासन को बड़ी अच्छी तरह से चलाया। तो स्पीकर साहब, वहां की जनता पिछले 11 सालों से अपने अफेसर खुद कन्ट्रोल करने से वंचित है। इन्होंने वहां पर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है और लोग उस आदमी के खिलाफ है। स्पीकर साहब, आप जानते है कि अगर डैमोक्रेसी न होती और नौकर ााही पर सारा मामला छोड़ दिया जाता.....

श्री अध्यक्षः आप थोड़ा ब्रीफ करें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह तो फर्स्ट स्टेज है। मैं इतना आहिस्ता तों बोल नही रहा जितना कटार सिंह जी बोल रहे थे। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता को अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल करने के लिये, सुपरवाइज करने के लिये और अपने नगर की व्यवस्था की देख भाल करने के लिये मौका मिलना चाहिए था, जोकि नही दिया। इसी प्रकार से सारी नगरपालिकाएं बंचित कर रखी है। चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि क्या करे। साहब जनगणना बीच मे आ गई हैं यह बहाना कब तक लगायेंगे। 81 बीत गया ओर 82 भी बीत गया और आज 1983 के मार्च की 23 तारीख हैं। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदे ा के अंदर नगरपालिकाओं का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने पहले भी एक दिन बोलते हुए यह कहा था कि हरियाणा प्रांत की सभी नगरपालिकाएं नर्कपापिकाएं बनी हुई हैं। (ाोर) स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना हूं कि नगरपालिकाओं के तुरंत चुनाव कराने के लिये घोशणा की जानी चाहिए। जिस भाहर की दो लाख की आबादी है उसकी नगरपालिका को कारपोरे ान का दर्जा देना चाहिए। स्पीकर साहब, रोहतक भाहर की रा ान कार्डो के हिसाब से दो लाख की आबादी है लेकिन जो सैंसस करने वाले थे। उनको यदि कोई आदमी घर मे मिल गया तो उसको लिख लिया और जो आदमी घर पर नही मिला उसको नही लिखा, इसलिये सैंसस के हिसाब से रोहतक भाहर की रा ान कार्डो के हिसाब से दो लाख की आबादी रह गई है। ऐसे बड़े भाहरों मे नगरपालिकाओं की बजाये कारपोरे ान

होनी चाहिए। स्पीकर साहब, गवर्नमैंट को यह चुनाव कराने के लिये घोशणा कर दे। इसमे संकां करने वाली क्या बात है ? जो भी आदमी चुनकर आयेंगे, वे आ जायेंगे। लोकल बाडीज मिनिस्टर को इस बात का इंतजार नही करना चाहिए कि मौसम अनुकूल होगा है या नही होता और फेवरेबल होता है या नही होता। इन भाब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि मैंने जो एस बिल की डिसएप्रूवल का नोटिस दिया है, मैं उस पर स्टैंड करता हूं और जो बिल आया है वह पास नही होना चाहिए। न ही इनको टाईम एक्सटैं ान का अधिकर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय जवाब दे दें।

स्थानीस भाासन राजय मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर साहब, मेरे मुअजिज दोस्त डा0 मंगल सैन जी ने इस बिल पर कुद एतराज उइाए हैं मैं उनकी जनरल कमैटरी का जिक्र नही करूंगा लेकिन उनकी दो बातों का जवाब अव य देना चहूंगां स्पीकर साहब, जनवरी 16983 तक इसकी मियाद थी। मैंनें सं ाोधन के जरिये एक साल की मियाद और मांगी हैं इहस बारे मे डा0 साहब ने भी एक बात वाजह तोर पर सजैस्ट की है कि इस मियाद को जून तक क्यों न कर दिया जाये। मैंने पहले भी एक एक सवाल के जवाब मे यह क्लीयर बताया था और अब भी बता देता हूं कि 1981 की सैंसस फिगर्ज हमें 1982 के आखिर मे मिली है। इसलिये सैंसस फिगर्ज मिलने के आद ही इस बारे मे गौर करना था। कि आया इसको ए क्लास कमेटी बनाना है या

इसको कारपोरे ान का दर्जा देना है। दिसम्बर 1983 के बाद जनवरी मे, चुनाव कराने के लिये हमें नोटिफिके ान के लिये भी 30 दिन का समय चाहिए था। लिहाजा मैंने इस अमैंडमैंड के जरिए एक साल की मियाद और मांगी है ताकी इा दौरान मे इसको कारपोरे ान या ए क्लास कमेटी बनाने के लिये वार्डबंदी की जा सके। डा0 साहब खुद मिनिस्टर रहे इनको खुद पता होना चाहिए कि कारपोरे ान की वार्डबंदी के लिये कम से कम एक साल का समय चाहिए और वह भी दिन रात काम करे ं तो वार्डबंदी का काम हो सकता है। स्पीकर साह, 13 जनवरी को इसकी मियाद सामप्त हो गई थी इसलिये टाईम की एक्सटैं ान लेना बहुत ही जरूरी था। दूसरी बात डा0 साहब ने मोसम के अनुकूल होने की कही। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वहां पर मौसम आपके अनुकूल कभी नही होगा। वहां पर तो मौसम मेरा ही हैं इसमे आपको चिंता करने की जरूरत नही है। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को कंसिडर तथा पास किया जाये। (इस समय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

Mr. Speaker: The Hon. Minister has now replied to the discussion on this motion.therafter, normally further discussion is not permitted. However, to accommodate the wishes of the hon. members, I will allow only 2 more members from the opposition to speak.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, यह जो दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल

सदन मे पे ा हुआ है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। स्पीकर साहब, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि अलग से किसी नगर की नगरपालिका को ए क्लास म्यूनिसिपल कमेटी या कारपोरे ान बनाने के लिये कोई बिल लाया जाये, या अमैंडमैंट लाई जाए। यह सारा डुप्लीकेट काम होता है। उनमे जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए है। आप किसी भी नगर की सब्जी मंडी मे से नही गुजर सकते क्योंकि किसी भी नगर की सब्जी मे सफाई नही है। सभी मंडियों मे सफाई नही है। सभी मंडियों मे जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए है। जो बड़े बड़े नगर है, वे तो प्राइज नगर माने जाते है लेकिन उनमे सफाई का कोई ध्यान नही रखा जाता। (ाोर एवं विघ्न) आप गरीब किसानों की ही जमीन एक्वायर करते है बड़े लोगों की जमीन एक्वायर नही करते। आपने फरीदाबाद मे बड़े बड़े लोगों की जमीन छोड़ दी और गरीब किसानों को जमीन एक्वायर की है। मैं यह बात पहले भी कह चुकी हूं कि झाड़सैतनी के गरीब किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। डिवैल्पमैंट का यह मतलब नही है कि आप गरीब किसानों की जमीन ले। डिवैल्पमैंट का मतलब यह है कि आप के पास जो चीज है उसी चीज को डिवैल्प करे। स्पीकर साहब, जिला हैडक्वार्टर्ज पर गवर्नरमैंट की जो फयर प्राइस भाप्स है, उनमे कपड़ा भी होता है, यह कपड़ा गरीब लोगों के काम नही आत बल्कि आफिसर्ज लोगों की रजाई और गद्दों मे काम मे आता है। जितना भी कपड़ा उन फेयर प्राइस भाप्स मे जाता है वह जन साधारण तक नही पहुंचता है। (ाोर) मैं फरीदाबाद कम्पलैक्स की

बात कर रही हूं। क्या फरीदाबाद कम्पलैक्स मे फेयरप्राइस भााप्त नही है ? फरीदाबाद कम्पलैक्स मे भी फेयर प्राइस भााप्स होगी। यदि वहां पर फेयर प्राईस भााप्स नही है तो आप उसको किस चीज का कम्पलैक्स बना रहे है। (ाोर) स्पीकर साहब, फेयर प्राइस भााप्स मे जितना भी कपड़ा जाता है वह बड़े बड़े अफसरों की रजाई और गद्दों के काम मे आता है, जन साधारण तक नही पहुंचता। स्पीकर साहब, फरीदाबाद कम्पलैक्स मे जो 17 गांव है उनकी वही दुर्गति है जो दिल्ली के आस पास के गांवो की हो रही है? इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि यह बिल उन 17 गांवों की पंचायत पर लागू नही होना चाहिए। स्पीकर साहब, उन गांवों के किसानों की जमीन टकों के भाव एक्वायर की जायेगी। फरीदाबाद के नजदीक जितने भी गांव है। उनमे सैनेटरी तक की भी सुविधा नही दी जा रही है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद मे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है लेकिन मजदूरों के लिये वहां पर कोई अच्छा इंतजाम नही किया गया है। फरीदाबाद के नजदीक जितने भी गांव है उनके लिये भी कोई अच्छा इंतजाम सरकार ने नही किया है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए है। और फैक्ट्रियों का गंदा पानी किसानों की जमीनों मे आता है। स्पीकर साहब, सरकार को फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज पर पोल्यू ान टैक्स लगाना चाहिए था और उस टैक्स का सारा पैसा वहां की गंदगी को साफ करने के काम पर और वहां पर जितने मजदूर रहते है। उनकी भलाई के काम पर खर्च किया जाना चाहिए था। यदि वहां की इंडस्ट्रीज पर पोल्यू ान टैक्स लगाया होता तो मजदूरों की

काफी भलाई हो सकती थी। फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज केवल धुआं ही नही निकालती है बल्कि उनका जो गंदा पानी बाहर निकलता है उससे भी काफी गंदगी फैलती है। फारीदाबाद मे इंडस्ट्रीज का गंदा पानी बाहर निकलने के कारण जगह जगह गंदगी फैली हुई है। एक या दो सैक्टर को छोड़ कर सारे फरीदाबाद मे गंदगी के ढेंर लगे हुए है। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगी कि जो बिल के जरिये अमैंडमेंट पे ा की गई है इसे पास न किया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सैंस हो तो बैठक का टाईम आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्षः बैठक का टाईम आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमेंट बिल,

1983 (पुनरारम्भ)

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, लोकल बाडीज मिनिस्टर ने जो दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंउ डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल पे ा किया है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हम पिछले कई सालों से यह देख रहे है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के लिये इसी प्रकार की अमैंडमैंट हर साल के आखिर मे आ जाती है। पहले आर्डीनैंस होता है उसके बाद अमैंडमैंट बिल आ जाता है और उसमे एक साल की मियाद और मांग ली जाती है। अभी तक सरकार यह फैसला नही कर पाई है कि फरीदाबाद मे कारपोरे ान का दर्जा देना है। या ए क्लास म्यूनिसिपल कमेटी बनाना है। यदि सरकार को यह फैसला करना ही है तो उसके लिये यह तक कर लिया जाये कि इतने समय मे यह काम कर दिया जायेगा। इसके अलावा स्पीकर साहब, इस बिल के एम्ज एंड आबजैक्टस मे नगरपालिकाओं के चुनाओ के बारे मे कहीं भी नही लिखा हुआ। जिस प्रकार से मार्किट कमेटिज की बात है, वहां इन्होंने चुनाव ही समाप्त कर दिये है। वहां पर ये अपने आदमियों कानोमिने ान करते है। जिनको लगाना ठीक समझते है, उन्ही को लगा दिया जाताहै। पंचायतों के चुनाव हुए पांच साल हो चुके है लेकिन पंचायत समितियों के चुनाव क्यों नही करवाती। जिस तरह से ये काम कर रही है उससे पता चलता है कि ये चुनाव पद्धति को समाप्त करने जा रहे है। स्पीकर साहब, यह सरकार फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव भी नही करवा रही। उसके लिये भी अब समय बढ़ा रही है। सरकार चुनाव करवाने की बजाये कमेटियों के के

जरिए कमजोर लोगो पर अनाप भानाप टैक्स लगा रही है। जिन लोगो के पास रेहड़िया थीं याजो खरादका काम करते थे, उनकी साल की लाईसैंस फीस चार सौ रूपये और साढ़े चार सौ रूपये कर दी है। इसी प्रकार से जो दूसरे छोटे छोटे दुकानदार है उन की लाईसैंस फीस भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटियों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे है लेकिन चुनाव नही करवाये जाते। अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे है लेकिनचुनाव नही करवाये जाते। अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हो जाते है और चुने हुए लोग वहां का काम देखेंगे तो वे लोग टैक्स की अच्छी तरह से वसूली कर सकेंगे। अंत मे सरकार फरीदाबाद कम्पलैक्स मे चुनाव न करवाने का जो बिल लाई है, मैं उसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

श्री हरि चन्द्र हुड्डा द्वारा

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री कटार सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने बोलते हुए मांग या ड्रामा कोई नही किया। मैंने यह कहा था कि मैंने बोलते हुए सांग या ड्रामा कोई नही किया। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा था कि यह सरकार 35 साल से काम कर रही है।

(ाोर) स्पीकर साहब, मैंने तो संविधान का जो आर्टिकल 372 है, उसके बारे मे कहा था। (ाोर) स्पीकर साहब, मैंने तो संविधान का जो आर्टिकल 372 है, उसके बारे मे कहा था। (ाोर) मैंने कोई सांग या ड्रामा नही किया । (ाोर)

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now if the hon. Minister wants to reply to the points raised by these hon. Members he may plaese do so.

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ए0सी0चौधरी): स्पीकर साहब, यहां पर फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल पर चर्चा चल रही है। इस संबंध मे कई साथियों ने अपने विचार किये है। आर्य साहब ने बोलते हुए सड़कों का जिक्र कर दिया तो कहीं पर गलियों का जिक्र कर दिया। मैं बड़े अदब के साथ इनको कहूं कि–

'हमको है उनसे वफा की उम्मीद,

जो नही जानते वफा क्या है।'

स्पीकर साहब, इनको भाहरों की हालत का बिल्कुल नही पता। फरीदाबाद के अंदर तो भाायद ये कभी नही गए

होंगे। ये यहां पर कह रहे थे कि 12 साल से कोई चुनाव नही करवाये गये। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल तो एक्ट मे ही थे कि कोई इलैक ान नही होंगे। इस संबंध मे एक अमैंडमैंट इन लोगो ने खुद की थी। दूसरी बात इन्होंने यह कही थी कि आर्डीनैंस पहले करदेते है और फिर उसकेबाद बिल ले आते है। इस कम्पलैक्स की टर्म जनवरी मे खत्म हो रही थी और मार्च मे सै ान आ रहा था। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई स्पे ाल सै ान बुलाया जाना चाहिए था। मैं इनको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि फरीदाबाद कम्पलैक्स की मियाद 13 जनवरी को खत्म हुई है। वहां के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये मैं सारे हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को यूनानीमसली पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1983 (Haryana Ordinance No. 2 of 1983)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title to be Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhri): Sir, I beg to move

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

The motion was carried.

(6) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1983

Mr. Speaker: Now a Minister will move his motion for th econsideration of the Punjab Ayurvedica and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1983

Health Minister(Shrimati Prasanni Devi): Sir, I beg to move-

That the Punjab Ayurvedic an Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Ayurvedic an Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, इस बिल पर मैंने अमैंडमैंट दी है और अमैंडमैंट देने का मतलब यह है कि हर रजिस्टर्ड प्रैक्टी ानर को रजिस्ट्रे ान रिन्यूवल के लिए हर साल एडमिनिस्ट्रे ान के जो चक्कर लगाने पड़ेंगे वह न लगाने पड़े इसलिए एक साल की लिमिट को पांच साल के लिए कर दें और पांच साल की इक्ट्ठी फीस जमा करवाई जाए। पांच साल से कम रजिस्ट्रे ान नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट प्रैक्टी ानर जो सनदयाफता हकीम और वैद्य है और इसके दूसरी तरफ जो एम.बी.बी.एस. डाक्टर्ज है है, इन दोनों को एक ही सतह पर होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है जिसकी वजह से भेदभाव की भावना पनपती हैं। मैं सरकार से दख्वास्त करूंगा कि इस बात पर विचार किया जाए और एक साल की जो लिमिट रखी है इसकों पांच साल के लिए कर दिया जाए ताकि बार–बार रजिस्ट्रे ान के लिए चक्कर न काटने पड़ें और कोई नाजायज फायदा न उठा सके।

श्री राम बिलास भार्मा(महेंद्रगढ): स्पीकर साहब, जो बिल मंत्री महोदय ने सदन में पे ा किया है, इस पर आपकी अनुमति से मैंने अमैंडमैंट दी थी।

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने रिजैक्ट कर दी थी और उसका जवाब आपको पहुंच गया होगा।

श्री राम बिलास भार्मा: हां जी पहुंच गया है। स्पीकर साहब मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूं कि यह अधिनियम पास होने के बाद करप् ान के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टी ानर जो देहात में काम करता है और डाक्टर के पास प्रैक्टिस करता है, वह हर साल अपना रजिस्ट्रे ान रिन्यू करवायेगा और वह भी पहले साल की अवधि समाप्त होने पर एक महीने के अंदर अंदर रिन्यू करवायेगा और अगर नहीं करवायेगा तो उसकी रजिस्ट्रे ान कैंसिल हो जायेगी। यह तो एक खतरनाक क्लाज जोड़ दी गई है क्योंकि इससे भ्रश्टाचार के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। गरीब आदमी इससे परे ाान होगा। प्रांत की गरीब जनता जो गांवों से बड़े हस्पतालों में नहीं जा सकती, बड़े डाक्टर की फीस अदा नहीं कर सकती, वह बिना दवाई के रह जायेगी। इसलिए मेरी सदन से गुजारि ा है कि इस बिल को पास न किया जाए। आज हरियाणा का पिछड़ा आदमी बेसहारा है, ज्यादा फीस डाक्टर को अदा नहीं कर सकता इस अमैंडमैंट का असर उस पर पड़ेगा, इसलिए इस बिल को पास न किया जाए।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, सदन में पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1983 पर चर्चा हो रही है। सेठ धमीजा साहब की अमैंडमैंट भी इस बिल पर आई है। स्पीकर साहब, इस बिल में एक गलती का अहतमाल हुआ है, इसको साफ करने के लिए

वाजह करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, रजिस्टर्ड प्रैक्टी ानर्ज की दो कैटेगरीज है, दो जुमले है। एक वे लोग है जो क्वालीफाईड प्रैक्टी ानर्ज है, जिन्होंने किसी कालेज से बाकायदा आयुर्वेदिक या यूनानी डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है। दूसरे वे लोग है जिनको क्वैक्स कहते हे। ये लोग दस दस साल के तजुर्बे के आधार पर रजिस्टर्ड किये गये है। आप इन दोनों कैटेगिरिज को खलतमलत कर रहे है जिससे कन्फयूजन पैदा होता है। जो डिग्री होल्डर्ज है चाहे ऐलोपैथी के है, एम0डी0 है चाहे एम0एस0 है, इन लोगों पर रिन्यूवल आफ रजिस्ट्रे ान फीस नहीं है लेकिन यूनानी और आयुर्वेदिक केजो क्वालिफाईड प्रैक्टी ानर्ज है उनके ऊपर रिन्यूवल फीस डाल रखी है, जबकि डिग्री होल्डर्ज डाक्टरों और आयुर्वेदिक एंड यूनानी के क्वालिफाईड प्रैक्टी ानर्ज के अंदर कोई फर्क नहीं है। वे भी बाकायदा डिग्री होल्डर्ज है और ये भी डिग्री होल्डर्ज है। जब दोनों बराबर है तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी के क्वालिफाईड प्रैक्टी ानर्ज के अंदर कोई फर्क नहीं है। वे भी बाकायदा डिग्री होल्डर्ज है। जब दोनों बराबर है तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज के ऊपर रिन्यूवल फीस क्यों डाली जा रही है? यह भेदभाव है, डिस्क्रीमिने ान है। हमारा जो कांस्टीच्यु ान है उसके आर्टिकल्ज 14, 19 और 22 में फंडामेंटल राईटस दिये हुए है और इन आर्टिकलज के तहत कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप देख ले मेरी बात ठीक है। यहां महकमें के एक्सपटर्स बैठे है प्रसन्नी देवी जी तो एक्सपर्ट नहीं है यह ठीक

है कि वे डिपार्टमैंट की मिनिस्टर है। स्पीकर साहब,जहांतक पैथी का ताल्लुक है इलाज का ताल्लुक है इसको देखने के लिए बाकायदा महकमे के अंदर क्वासलिफाईउ एक्सपर्टस रखें गये है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इन्होंने इस तरह की गलती कैसे कर दी? उनको चाहिए था कि जो क्वालिफाईड फिजि ियन है चाहे ऐलोपैथी के है चाहे यूनानी एंड आयुर्वेदिक के है उनको एक ही जुमले के बना देते है। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है जो यह नहीं जानते कि अनाटमी क्या होती है फिजिओलोजी क्या होती है, जिन को यह इल्म नहीं कि हमारे भारीर के अंदर लिवर का फंक ान क्या है नर्वस सिस्टम क्या है इन लोगों को महज तजुर्बे के आधार पर दस दस साल के एक्सपीरिएंस को देखते हुए रजिस्टर्ड प्रैक्टी ानर बना दिया है। जो लोग कुछ जानते हीनहीं उन्होंन पता नहीं किस तरह से रजिस्ट्रे ान करवा ली हैं। ठीक है उनकी रजिस्ट्रे ान हो गई वे हमारे भाई है इनको भी रोजगार चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोजी कमाने की आड़ में लोगों की जान से खेलते रहें। इसलिए इन लोगों के लिए एक छोटा सा कंडैंसड कोर्स बना दें जिससे उनको थोड़ा सा भारीर का ज्ञान हो जाए। चाहे यूनानी का प्रैक्टी ानर है चाहे आयुर्वेदिक का है जब तक वह कंडैसंड कोर्स को पास नहीं करता तब तक उसकी फरदर रिन्यूवल नहीं होनी चाहिए, यह पाबंदी सरकार को लगा देनी चाहिए। पहले बाकायदा कंडैसड कोर्स को पास कर ले, उसके बाद रिन्यूवल दी जाए। यह सारी कार्यवाही होने के बाद उनको डिप्लोमा होल्डर्ज

के जुमले में ले आये। (घंटी) स्पकीर साहब, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। इसके अलावा स्पीकर साहब, बिल में हर साल रिन्यूवल के लिए जो प्रोवीजन रखा है, यह पांच साल में एक बार होनी चाहिए और रिन्यूवल फीस नहीं होनी चाहिए। अगर फीस डालनी ही है तो डिस्क्रीमिने ान होगी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से लीडर आफ दि हाउस से कहूंगा कि इस बिल में कोई ऐसी गुंजाई ा रख दें कि अगर कोई आदमी किसी वजह से पांच साल के बाद दो साल तक मतवातर अपनी फीस जमा नहीं करवा पाता, ऐसी सूरत में उसका नाम रजिस्टर से नहीं काटना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं – एक क्वालिफाईड और दूसरे अनक्वालिफाईड की, ये नहीं होनी चाहिए और जो एलोपैथी के क्वालिफाईड डाक्टर हैं, जो सलूक इनके साथ किया जाता है वही ट्रीटमैंट यूनानी और आयुर्वेदिक प्रैक्टी ानर्ज के साथ होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह जो हाउस में अमैंड्डि बिल सरकार लाई है इससे ऐसा लगता है कि जाने या अनजाने में इन लोगों को स्वदे ाी उपचार से या उसके तरीके से कुछ नफरत हो गई है। इनको आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा के तरीके नकारद मालूम होते है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों को तो हर साल रजिस्ट्रै ान रिन्यू करवानी पड़ेगी

लेकिन एलोपैथिक वालों को नहीं करवानी पड़ेगी। स्पीकर साहब, धमीजा साहब ने अमैंडमैंट दी है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी अपना रजिस्ट्रीकरण पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं ाोधन) अधिनियम 1983 के प्रारम्भ से दो महीने के भीतर नवीकृत करायेगा और उसके बाद, प्रत्येक पांच वर्श बाद रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने पर ऐसी फीस के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत कराया जाएगा, जो विहित की जाये। अब सवाल तो यह है कि चाहे पांच साल का टाईम रखें चाहे दस साल का टाईम रखें लेकिन एलोपैथिक वाले तो रिन्यू नहीं करायेंगे और आयुर्वेदिक वाले करायेंगे। यह डिस्क्रिमिने ान क्यों है ? उनकी सुपीरियर पोजी ान क्यों समझी जाती है ? क्या यह जाने या अनजाने में किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी को इस बारे में गौर करना चाहिए। यह तो गुनाह बे–लज्जित करने वाली बात है। डा. ओमप्रका ा जी ने ठीक सुझाव दिया है, उन्हे कन्डेन्सड कोर्स करवाइये और प्रैक्टिस करने की इजाजत दें। हाउस में जो बिल मूव हुआ है वह रजिस्ट्रे ान के बारे में है। आयुर्वेदिक लोगों के साथ बड़ा हाईट आफ इन जस्टिस है, बड़ी ज्यादती है। जो लोग रिमोट विलेजिज में बैठे हुए हैं, जिनको हैड क्वार्टर पर आ कर रिन्यू कराने के लिए खर्च करना पड़ेगा और अगर चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रे ान रिन्यू की बात होगी तो और भज ज्यादा लुटाई होगी। सरकार दूसरे तरीके से बचत कर सकती थी। इस बिल को लाने की कोई जस्टिफिके ान नहीं है। हम इसे स्ट्रोंगली अपोज करते है। यह पास नहीं होना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): स्पीकर साहब, मैं बहिन जी से इस बिल के बारे में प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सुझाव डा. ओम प्रका ा जी ने दिया है, वह मान लिया जाये। उनकी बात ठीक हैं दूसरी मेरी राय यह है कि अगर यह बात न मानी जाये तो इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और आज इसे वापिस ले लें। अगर पास ही करवाना है तो फीस जमा कराने के बारे मे कोई बात नहीं की जानी चाहिए, उसे रिन्यू ही समझा जाना चाहिए। सरकार इसे पास करती है तो आयुर्वेदिक तथा यूनानी लोगों के साथ ज्यादती हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इसे पास नहीं किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि इस अमैडिंग बिल में कोई खास बात नहीं है। श्री राम बिलास भार्मा, डा. ओम प्रका ा भार्मा तथा डा. मंगल सैन जी ने कुछ बातें कही हैं। इस बिल से किसी गांव में प्रैक्टिस करने वाले को कोई फर्क नहीं होगा। हरियाणा में आज के दिन ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क का साधन न हो। दूसरी बात पैसे के बारे में है। उन लोगों से जो पैसा आयेगा वह सरकार के पास जमा नहीं होगा। रजिस्ट्रे ान फीस का पैसा चाहे प्राईवेट प्रैक्टि ानर से लिया जाये चाहे सरकारी से लिया जाये वह सारा पैसा बोर्ड में ही जमा रहेगा। यह उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो नाजायज फायदा उठाते हैं कई बार किसी की डैथ हो जाती है इसका

कारण यही है कि उन्हें दवाईयों का कोई ज्ञान नहीं होता। जिनको कोई ज्ञान नहीं है वे आदमी आज के दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

डा. ओम प्रका ा भार्मा: प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब बहिन जी ने अभी अभी कहा है कि जिन रजिस्टर्ड प्रैक्टि ानर्ज को कुछ ज्ञान नहीं हैं, उनके बारे में यह फीस है। क्या फसी लगा कर उन्हें ज्ञान हो जायेगा ? क्यों आप इन्सानी जिन्दगी से खेलना चाहती हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, भाायद डाक्टर साहब समझ नहीं पाये हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह फीस कोई लम्बी चौड़ी नहीं है। दस रूपये का मतलब यह है कि महीने में 80 पैसे। यह फीस सरकार के पास नहीं आयेगी, यह बोर्ड को जायेगी, चाहे वह प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर से आये चाहे सरकारी डाक्टर से आये। जो फीस आयेगी वह उन्हीं पर खर्च होती है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि इस वक्त 16 हजार 680 चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं, इनमें से अभी तक 1700 ठीक पाए गए। रिन्यू कराने से यह फायदा हो जायेगा कि जिन्हौंने बोगस डिग्रियां ली हुई है या कुछ लोग बोगस डिग्रियां खरीद लेते हैं, उनकी चैकिंग हो जायेगी। डा. मंगल सैन जी ने यह बात भी कही कि मंत्री जी इतनी योग्य नहीं है यानी आयुर्वेदिक के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि यह कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि इस महकमे का

इन्चार्ज वही हो जिसे इस बारे में ज्ञान हो। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने भी आयुर्वेदिक की भास्कर डिग्री ली हुई है। मैं भी इन सारी बातों को जानती हूं। आपको पता है कि गांवों में जो जुल्म होते हैं, वह किसी से छिपे नहीं। लोग दवाई का पता होने पर इलाज करना भुरू कर देते है। इन सारी दिक्कतों को देखते हुंए यह बिल लाया गाया हें धमीजा साहब ने जो अमैडमैड दी है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हैं एक साल की बजाय पांच साल आ जाये तो हमें कोई एतराज नही। इन भाब्दों के साथ मै प्रार्थना करूंगी कि इस बिल को पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is-

That is the Punjab Ayurvedic and Unani Practioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: I had received notices of two amendments to this clause from ShriRam Dass Dhamija, M.L.A. I had also received notice from the said hon. Member for the withdrawal of his first amendment, which has been allowed by me. Therefore, the second amendment of the hon. Member will only be deemed to have been read and moved together.

Shri. Ram Dass Dhamija: That for the porposed sub-section (1) of Section 15B of the Bill, the following sub section shall be substituted namely:-

(1) Every registered practitioner shall get his registration renewed within two months of the commencement of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Act, 1983 and thereafter the registration shall be got renewed after every five years within one months of the expiry of the period of registration, on payment of such fees as may be prescribed."

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो गई तो दस मिनट के लिए बैठक का टाईम बढा दिया जाये।

आवाजें: ठीक हैं, दस मिनट के लिए टाईम बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बैठक का टाईम दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दि पंजाब आयुवैर्दिक एंड यूनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1983 (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सेन (रोहतक): स्पीकर साहब, आदरणीय बहिन जी का जवाब मैनें बडे गौर से सुना है इन्होनें सदन को यह समझाने की कोि ा ा की है कि इस सं ाोधन से और रजिस्ट्रे ान रिन्यू कराने से केवल 80 पैसे महीने का फर्क पड़ेगा कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। स्पीकर साहब, 80 पैसे ओर दस पैसे का सवाल नहीं है। प्र न यह हैं कि आयुवैर्दिक प्रैक्टि ानर्ज

से तो बोर्ड पैसे चार्ज करेगा लेकिन एलोपेथी पैक्टिस करने वालो को क्यो इन्होने छोड़ दिया है।

14.00 बजे

श्री अध्यक्षः यह तो आपने पहले भी कह दिया।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, उन्होने मेरी उस बात का जवाब नही दिया। दूसरी बात यह हैं कि मंत्री महोदय बार बार यहां पर एम्फैसाईज कर रही थी कि कुछ लोगों ने इन्टरव्यू के आधार पर बोगस रजिस्ट्रे ान करवा ली। उनको वाइप आउट करने का तरीका एक और था जो और लोग बोगस रजिस्ट्रेसन करवा चुके हैं उनको हटाने के लिये आप कोई एग्जामिनेसन पास करने की बात कम्पलसरी कर देते तो हम आपकी तो हम आपकी बात को एप्रीि ायट करते कि आप बहुत अच्छा कर रहें हो क्योकि किसी को भी इन्सानों की जिन्दगियों से खेलने की इजाजत नही होनी चाहिये। वह तो आप कर नही रहे हो स्पीकर साहब, जो आयुवेदिक ओर यूनानी प्रैक्टिसनर्ज के रजिस्टर्ड लोग है उनको 10 रूपये देने पडेगे यह सरासर अन्याय हे। सरासर पक्षपात हैं और डिस्किमीनेसन है। स्पीकर साहब, कांस्टीच्यू ान की किताब मेरे पास है। मैं हाउस में उसमें से पढकर सुनाना चाहता हूं। उसमें आर्टीकल 14 में यह लिखा हुआ हैः—

"Equality before law – The State shall not deny....."

श्री अध्यक्षः आपक मतलब यह है कि यह डिस्क्रिमीने ान है। यह आपकी बात समझ आ चुकी है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप तो पु तैनी वकील है, आप तो समझ गये। आपको मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनको यह समझाा रहा हूं कि कल को अगर इस को चैलेन्ज किया गया, कोई भाई कोर्ट में चला गया और उसने यह कह दिया कि यह तो डिस्क्रिमीने ान है तो आप को यह बिल रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जायेगा। फिर आपके वकील भागे भागे फिरेंगे। आप बेकार में वकीलों को फीसें देते रहोगे इसलिए मेरी सबमि ान मेरी सबमि ान यह है कि इस बिल को विदड्रा करके, आपको जो बोगस रजिस्टर्ड लोगों को हटाने का पर्पज हैं, उसके लिए बिल लायें।

Mr. Speaker: Question is:-

That for the proposed sub-section (1) of section 15B of the Bill, the following sub section shall be substituted, namely:-

(1) Every registered practitioner shall get his registration renewed within two months of the commencement of the Punjab Ayurvedic ans Unani Practitioners (Haryana Amendment) Act, 1983 and thereafter the registration shall be get renewed afte every five year one month of the expiry of the period of registration, on payment of such fees as may be prescribed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Smt. Prasanni Devi): Sir, I beg to move:-

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 24th March, 1983.

14.03 Hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 24th March, 1983.)